चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 02 अप्रैल–08 अप्रैल 2012 | मूल्य 5 रुपये

मनमोहन लाचार

पेज-3

कोयला घोटाले का सच

पेज-5

अन्ना आंदोलन का अगला चरण

पेज-7

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आंकड़ों का खेल

पेज-12

यह सिद्धांत की लड़ाई है

जनरल वी के सिंह

मैं जन्म तिथि मामले में सुप्रीम कोर्ट इसलिए गया, क्योंकि यह सिद्धांत की बात थी. मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा कि मुझे अपना कार्यकाल नहीं बढ़ाना है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कोई फ़ैसला नहीं दिया. उन्होंने इसके ऊपर यह कहा कि हमारे पास जो समस्या आई है, उसे हम इस तरीक़े से ले रहे हैं कि जो इनकी आयु है, जो रिकॉर्ड के अंदर है, उसमें हमें कोई दिक्क़त नहीं है और इस पर अटॉर्नी जनरल साहब और सरकार ने जो आदेश दिया है, वह उन्होंने वापस ले लिया है, इसलिए कोई समस्या नहीं बनती. इसलिए पिटीशनर ने अपनी पिटीशन वापस ले ली है तो यह केस विड्रा हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग बड़े दिग्गज लोग हैं. उनके क्या विचार थे, क्या सोच, क्या युक्ति थी, वे जानें. हां, एक चीज़ अलग लगती है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक नियम बनाया आयु के ऊपर, वह सबके लिए लागू है. रिटायरमेंट के लिए हमने पहले बोला था कि हमारा कार्यकाल जैसा कि सरकार ने कहा कि 31 मई तक है, हम 31 मई को रिटायर हो जाएंगे. लड़ाई कार्यकाल के लिए नहीं थी, लड़ाई सिद्धांत के लिए थी.

पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं कि सेना कोई ऐसा काम नहीं करती, जो सरकार के ख़िलाफ़ हो. दूसरी, हम कोई ऐसी चीज़ अपने पास नहीं रखते, जिससे कि हमें जासूसी करनी पड़े. और जासूसी किसलिए? आख़िर सरकार और सेना के बीच में समन्वय है तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम किसी प्रकार की जासूसी करेंगे. इसे लेकर मीडिया के अंदर एक मनगढंत कहानी चलाई गई, ताकि छवि को धूमिल किया जाए. आपके ऊपर कीचड़ फेंका जाए. जिन दो गाड़ियों का ज़िक्र किया जा रहा है कि वे दो गाड़ियां रक्षा मंत्रालय के बाहर थीं और जासूसी का काम करती थीं, उनके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हो, कोई उसका नंबर नोट करके ले जाए और अख़बार में निकाले कि आप जासूसी कर रहे थे तो क्या आप सचमुच जासूसी कर रहे थे. आप तो बोलेंगे कि आपकी गाड़ी वहां खड़ी थी. उन्होंने किन गाड़ियों के नंबर नोट किए हैं, क्या उनके अंदर सामान था? अगर वह एक नॉर्मल डिटेचमेंट, जो हमारी एक काउंटर इंटेलिजेंस डिटेचमेंट है, अगर उसकी गाड़ी है, तो वह गाड़ी तो रोज़ आती है वहां पर. अगर उसके अंदर एक इक्यूपमेंट लगा होता तो उसमें कोई सुराख़ होता, कोई चीज़ होती, कोई बाहर सामान निकला होता. दूसरी चीज़ यह है कि अगर सेना के पास ऐसा सामान होता तो उसकी लिस्ट बाक़ायदा आईबी के पास होती. ऐसा कुछ नहीं था. अब सवाल है कि इस सारी कहानी के पीछे कौन है. हमने जब पता करने की कोशिश की तो हमें इंटेलिजेंस से पता नहीं चला, मीडिया के ज़रिए ही पता चला. वहां से हमें पता चला कि हमारे ही कुछ रिटायर्ड लोग थे, जो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे. उनमें कुछ तो ऐसे हैं, जिनके विदेशी हथियार वालों के साथ कुछ संबंध हैं. अब किसने किससे क्या बोला, नहीं पता, लेकिन इस सबके बीच संबंध ज़रूर है, यह मुझे पता है.

जहां तक सुकना का मामला है, एक कोर कमांडर कहकर गया था कि सिक्योरिटी के लिहाज़ से सेना को यह ज़मीन ले लेनी चाहिए. दूसरा कोर कमांडर आता है. वह भी छह महीने तक इसी बात को दोहराता है कि यह ज़मीन सरकार से सेना को ले लेनी चाहिए और एक महीने के अंदर वह बिल्कुल पलटी खा जाता है. जब हम लोगों को शक हुआ तो हमने तहक़ीक़ात की. आर्मी हेड क्वॉर्टर को बताया गया कि इसके अंदर ये–ये नुक्स हैं. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली. मेरा काम था उस चीज़ को सही जगह ले जाना, जिन लोगों ने ग़लती की है उनका नाम उजागर करना और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना. मैं यह कहूंगा कि इसमें हमारे रक्षा मंत्री ने सही निर्णय लिया और उनके पास जो हेड क्वॉर्टर की रिक्मेंडेशन गई थी, उसे उन्होंने नहीं माना. उन्होंने कहा कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. मेरे रिश्ते हमेशा से सबके साथ अच्छे रहे हैं. शायद जनरल कपूर के साथ रिश्तों में कुछ मनमुटाव हुआ हो सुकना को लेकर, क्योंकि उसके अंदर जनरल अवधेश शामिल थे. आदर्श सोसायटी घोटाले को सेना ने उजागर नहीं किया. यह मामला उजागर हुआ मीडिया के जरिए. हमारा काम सिर्फ़ यह था कि हम इसकी इंक्वायरी करें कि कौन दोषी है, किसकी ग़लती से सेना की ज़मीन एक प्राइवेट बिल्डर के पास

जब मैं सेनाध्यक्ष बना, तब सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने थी कि किस प्रकार हम अपने आपको मज़बूत करें. हमने ट्रांसफॉरमेशन स्टडी की और उसके द्वारा हमें पता चला कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जिनसे हम सेना को और अच्छा बना सकते हैं. हमारे पास एक दूसरी दिक्क़त थी कि हमारी मॉर्डनाइजेशन स्पीड काफ़ी स्लो थी. काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं, जो पाइप लाइन में रुकी पड़ी थीं. एक समस्या, जिसे मैं एक तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मूल चीज़ समझता हूं कि हमारी जो वैल्यूज थीं, जो हमारी छवि थी, कहीं उसने चोट खाई थी, क्योंकि कुछ मामले ऐसे हुए थे.

चली गई या कैसे एक सोसाइटी के पास चली गई. उसके अंदर काफ़ी लोग शामिल थे. यह नहीं कि हमने उसमें कोई अतिरिक्त रुचि दिखाई, उसके अंदर वह किया, जो सेना के नियम से होना चाहिए था. ऐसी ख़बरें भी आईं कि सेना और ख़ासकर सेना के जो कमांडर्स हैं, उनकी तरफ़ से मैंने कह दिया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेना नहीं जाएगी और मैंने सरकार की बात नहीं मानी. लेकिन यह सच नहीं है. हमसे सलाह मांगी गई थी कि आप पूरी स्थिति का अवलोकन करके बताइए कि क्या सेना को इसके अंदर उतरना चाहिए कि नहीं. एक प्रोफेशनल की तरह हमने सलाह दी और कहा कि नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक एवं गर्वनेंस की समस्या है. वहां के ट्राइबल शायद उसी हालत में हैं, जिस हालत में आज़ादी से पहले थे. ऐसे लोगों को जब नक्सली आकर बताते हैं कि देखिए, आप अभी तक वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और यह देखिए शहर की फोटो. हमने सिर्फ़ यह बोला कि इस समस्या के सुधार के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर मज़बूत करना है, वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए. दूसरी चीज़, वे आपसे कोई अलग देश नहीं मांग रहे हैं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं. सेना आख़िरी उपाय है. मुझे इस बात की ख़ुशी है कि हमारे गृहमंत्री ने इस बात को माना.

जब मैं सेनाध्यक्ष बना, तब सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने थी कि किस प्रकार हम अपने आपको मज़बूत करें. हमने ट्रांसफॉरमेशन स्टडी की और उसके द्वारा हमें पता चला कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जिनसे हम सेना को और अच्छा बना सकते हैं. हमारे पास एक दूसरी दिक्क़त थी कि हमारी मॉर्डनाइजेशन स्पीड काफ़ी स्लो थी. काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं, जो पाइप लाइन में रुकी पड़ी थीं. एक समस्या, जिसे मैं एक तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मूल चीज़ समझता हूं कि हमारी जो वैल्यूज थीं, जो हमारी छवि थी, कहीं उसने चोट खाई थी, क्योंकि कुछ मामले ऐसे हुए थे. लोगों को लगने लगा था कि सेना के अंदर कहीं भ्रष्टाचार बढ़ गया है. अगर आप छवि सुधारना चाहते हैं तो बहुत समय लगता है. जहां तक बिचौलियों का सवाल है, सरकार ने बहुत पहले एक निर्णय लिया था कि हम बिचौलियों को नहीं आने देंगे. यह सरकार का निर्णय है और उसका पालन करना सबका काम है. हमने यह किया कि जो सामान हम ख़रीद रहे हैं, जिस भी प्रोसीजर के अंदर हम चल रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सबको दिखना चाहिए कि क्या है. यह नहीं होना चाहिए कि दो साल बाद हम कहें कि यह सामान ही ख़राब था या ये जो बंदूकें ख़रीदी हैं, वे ख़रीदी ही नहीं जानी चाहिए थीं. सेना के एक रिटायर्ड व्यक्ति द्वारा मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने की ख़बर आई. मैं बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो अभी रिटायर हुआ हो और वह कई बातों के अंदर यह कहे कि यदि आप ऐसा काम करें तो आपको शायद यह चीज़ मिलेगी. अगर आपने ऐसी चीज़ सुनी न हो पहले तो आप भौचक्के रह जाएंगे, आपको यह समझ में नहीं आएगा कि यह आदमी क्या बोल रहा है. ऐसा हुआ. मैंने उनसे कहा कि आप चले जाइए, इससे पहले कि कुछ और हो. बाद में मैंने यही बात अपने रक्षा मंत्री को बताई कि यह स्थिति है. रक्षा मंत्री ने अपना माथा पीट लिया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हमें बाहर रखना चाहिए. उस वक़्त जिस तरीक़े से उस व्यक्ति ने बात की और कह रहा था कि यह फाइल क्लियर होगी तो इतने पैसे मिलेंगे, सब लोग लेते हैं, आपको क्या दिक्क़त है? तो एक तरीक़े से यह एक इंडायरेक्ट तरीक़ा था आपसे बोलने का और शायद इसीलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई. हम यह सोचकर चले कि एक छोटे कार्यकाल के दौरान सब कुछ साफ कर देंगे, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ कैंसर की तरह हमारे सिस्टम में घुस गई है, उसे निकालने के लिए काफ़ी बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है. मेरे और रक्षा मंत्री जी के बीच में बिल्कुल साफ है कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, जिससे ये चीज़ें बढ़ें. इसमें समय लगेगा और जो सिस्टम है, मुझे पूरी आशा है, उसके अनुरूप अगर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अखिलेश यादव ने ए सी शर्मा को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया है. इसके साथ-साथ 26 आईएएस एवं 30 आईपीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है.

दिल्ली का बाबू

बाबुओं का स्थानांतरण

उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बड़े पैमाने पर बाबुओं का स्थानांतरण शुरू हो गया है. बसपा के नज़दीकी कई बाबुओं का स्थानांतरण किया जा रहा है और उनकी जगह समाजवादी पार्टी के नज़दीक रहे बाबुओं को लाया जा रहा है. सरकार ने जावेद उस्मानी को मुख्य सचिव बनाने का फ़ैसला किया है. उनसे पहले 1975-76 में एक मुस्लिम अधिकारी महमूद बट्ट को मुख्य सचिव बनाया गया था. बट्ट के बाद उस्मानी ही ऐसे मुस्लिम अधिकारी हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव बनाया गया है. अखिलेश यादव ने ए सी शर्मा को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया है. इसके साथ-साथ 26 आईएएस एवं 30 आईपीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है. उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में भी बड़े पैमाने पर हेरफेर की जाएगी. मायावती सरकार के समय प्रमुख सचिव रहे नेतराम, रवींद्र सिंह, आरपीएस सिंह एवं डी एस मिश्रा सहित कई अधिकारियों का तबादला किया गया है. वहीं अनीता सिंह, राजीव कुमार, आर एम श्रीवास्तव, शंभू यादव एवं पंढारी यादव को लाया जा रहा है. ऐसा तो हमेशा बाबुओं के साथ होता रहा है. उन्हें राजनीतिक दलों से नज़दीकियों का ख़ामियाजा भुगतना पड़ता है और उसका फ़ायदा भी मिलता है. जब तक राजनीति और नौकरशाही का गठजोड़ बना रहेगा, तब तक सरकार बदलने का असर भी पड़ता रहेगा.

हिमाचल सरकार और बाबू

दिलीप चेरियन

आईएएस अधिकारियों की कमी के कारण हिमाचल सरकार को परेशानी हो रही है. मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यह परेशानी कम करने के लिए कुछ समय पहले भारतीय वन सेवा के कुछ अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सचिवालय और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों में नियुक्त किया था, लेकिन इससे आईएएस लॉबी नाराज़ हो गई थी. उसका कहना था कि जिन पदों पर आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, वहां अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, जो सही नहीं है. लगता है, आईएएस लॉबी का दबाव काम कर गया और मुख्यमंत्री को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी. वन सेवा के एक अधिकारी विनीत कुमार को हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के एमडी पद से अलग कर दिया गया है. कहा जा सकता है कि विनीत को अलग करने का कारण आईएएस लॉबी का विरोध है.

dilipcherian@gmail..com

यह सिद्धांत की लड़ाई है

पृष्ठ एक का शेष

आगे वाले चलेंगे तो हम ज़रूर एक ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे, जब कह सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं.

बोफोर्स तोप आई थी तो साथ में तकनीक भी लाई गई थी, लेकिन इतने सालों में भी ये तोपें मुल्क में नहीं बनाई जा सकीं. जब हम अपने तोपख़ाने के आधुनिकीकरण के बारे में विश्लेषण किया तो पाया कि काफ़ी ग़लतियों में हम वर्दीधारी भी शामिल हैं. बार-बार आप यह कहेंगे कि इसकी जगह हमें यह कैलीबर चाहिए. दुनिया के अंदर टोटल प्रोडक्शन को नहीं देखेंगे तो आपको देरी होगी. तब आपस में कॉन्ट्रेक्टर, वेंडर्स के बीच आपका कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए होड़ होगी. कोई उंगली उठाएगा, कोई कोर्ट जाएगा, कोई न कोई यह कहेगा कि फ़लां दलाल ने पैसे लिए हैं. बोफोर्स के इंसिडेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस था, उसमें यह देखने की कोशिश की जाने लगी कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए. कोई ऐसी डील नहीं होनी चाहिए, जिससे दस साल बाद हम फंस जाएं. लोगों ने इस प्रक्रिया में काफ़ी ढिलाई कर दी, वे स्लो हो गए, काफ़ी कॉसियस हो गए. जब हमने अपना विश्लेषण किया तो पाया कि तकनीक और ड्राइंग हमारे पास है, लेकिन कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा है. आर्डिनेंस फैक्ट्री से हमने पूछा कि आप इस पर काम कर सकते हैं तो उन्होंने हामी भर दी, उन्होंने गन तैयार की और उससे 450 राउंड फायर भी किए जा चुके हैं. देश में बनी बोफोर्स गन सफल है. हमने एक बढ़िया डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसिजर बनाया. अगर हम जेएसक्यूआर (ज्वाइंट सर्विसेज क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स) ही ग़लत बना देंगे तो वह चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जो आप चाहते हैं. आज की तारीख़ में पूरे विश्व में हथियार एक तरह का है. अगर आप कहें कि हथियार ऐसा होना चाहिए, जो उड़ सके, जो पानी में भी जा सके, ज़मीन में भी नीचे जा सके तो नहीं मिलेगा आपको ऐसा हथियार. आपको जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है, उसे देखना पड़ेगा. कई बार हम इस पर ग़लती करते हैं. हम जो दूसरी ग़लती करते हैं, जो वर्दी वाले लोग हैं कि हमारा टेंडर होता है छोटा. हमने अपना काम किया, उसके बाद हम भूल गए. अगला आदमी आता है, वह क्या करता है, उसमें क्या मीन-मेख निकालता है. हमने इस सबसे डील करने वाले डिपार्टमेंट को री-ऑर्गनाइज किया, ताकि कमियां दूर की जा सकें. सबसे बड़ी दिक्क़त हमारी क्या आती है कि सेना के जो तीन अंग है और जहां तक थलसेना का सवाल है तो हमारी ज़रूरत ज़्यादा है. चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए. सब अलग-अलग तरह की चाहिए, लेकिन उनकी क़ीमत कोई इतनी ज़्यादा नहीं है. हो सकता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट हो पांच सौ करोड़ का और उसके मुक़ाबले में शायद एयर फोर्स की एक या दो चीज़ की क़ीमत हो चार हज़ार करोड़. कई फाइलें होती हैं. एक फाइल होती है चार हज़ार करोड़ की, कोई तीन हज़ार करोड़ की, कोई पांच सौ करोड़ की. सभी फाइलों में समय तो उतना ही लगता है, चाहे वे कम रक़म की हों या ज़्यादा रक़म की. अब अगर आपके पास पांच सौ करोड़ के दस मामले हैं तो आपको बहुत समय लगेगा. इसलिए सेना पीछे रह जाती है, लेकिन साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि 2010-11 का जो वित्तीय वर्ष था, उसमें पहली बार सेना और एमओडी के इतिहास में प्रोक्योरमेंट का कैपिटल बजट पूरा ख़त्म हुआ. 2011-12 में हमें दिक्कत आई. 106 प्रपोजल हमने वित्तीय वर्ष के शुरू में दिए थे, लेकिन उनकी प्रोग्रेस थोड़ी ढीली पड़ गई. एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यप्रणाली ऐसी है कि किसी अधिकारी के नीचे का अधिकारी नहीं है तो काम आगे नहीं चल सकता. काम छह महीने ढीला चला. उसके बाद आगे बढ़ाने की कोशिश की तो जो नए आदमी आए, उससे फिर समय लगता है, लेकिन मुझे आशा थी कि यह छह महीने अगर बर्बाद न होते तो इस वर्ष भी अपना पूरा कैपिटल बजट हम ख़त्म कर सकते थे.

हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाईं, क्योंकि ज़िम्मेदारी फिक्स नहीं हो रही थी. काफ़ी ग़लतियां थीं. हम उन्हें एक वर्षीय टारगेट देते थे. हम उनसे यह नहीं कहते थे कि हमें अगले पंद्रह सालों के लिए क्या चाहिए. अगर आप किसी को नहीं बताएंगे कि अगले पंद्रह सालों में हमारी हर वर्ष की यह ज़रूरत है तो वे भी अपना डेवलपमेंट हिसाब से नहीं कर पाएंगे. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हमारे बीच समन्वय की भी कमी थी. वे क्या कर रही हैं, कुछ पता चलता था, कुछ पता नहीं चलता था. हम क्या चाह रहे हैं, कुछ उन्हें पता चलता था, कुछ नहीं चलता था. लेकिन अब चीज़ें सुधर रही हैं. भारतीय सेना जिस विदेशी ट्रक (टेट्रा) का इस्तेमाल करती है, उसके लिए कभी किसी समय यह निर्णय लिया गया कि हमें एक हाई मोबिलिटी वाइकल चाहिए. उस हाई मोबिलिटी वाइकल के लिए इस ट्रक का चयन हुआ और एक डिफेंस पीएसयू के माध्यम से इसकी ख़रीद-फ़रोख्त हुई, लेकिन यह अपने देश में बन नहीं रहा था. यह किसी ने देखने की कोशिश नहीं की कि एक ओरिजनल फैक्ट्री से एक और सब्सिडियरी ख़रीदती है, वह सब्सिडियरी डिफेंस पीएसयू को देती है, फिर डिफेंस पीएसयू सेना को देती है. ज़ाहिर है, इसमें ज़्यादा पैसा लगा. इस तरह के हमारे पास तक़रीबन 7000 ट्रक हैं. उनकी मेंटनेंस चेक के लिए, उनकी देखभाल के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया गया था. अगर कोई कंपनी, उदाहरण के तौर पर टाटा को लें, अगर वह आपको एक ट्रक दे तो उसका एक अलग सर्विस सेंटर है. आपका ट्रक कुछ दिनों बाद वहां जाकर सही हो सकता है. ऐसा नहीं किया गया. यह एक ग़लती है, जो किसी को ठीक करनी चाहिए थी और इसे हमने अब ठीक करने की कोशिश की है. हमने अब कहा है कि आप पहले 7000 ट्रकों की सर्विसिंग तो करिए. अभी तो चेकोस्लोवाकिया से आदमी बुलाना पड़ता है, इसे ठीक करने के लिए. हमारे पास खुद़ के ट्रेंड आदमी होने चाहिए.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

जवान फ़ौज में आते हैं, जल्दी रिटायर होते हैं, कम उम्र के अंदर रिटायर होकर घर चले जाते हैं. ऐसे में कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं. इसके लिए हमने एक स्कीम शुरू की कि हम किस प्रकार इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से उन्हें डिग्री दिला सके. इसके ऊपर बड़ा ज़ोर दिया गया. आज की तारीख़ में कम से कम साढ़े चार लाख जवान इस स्कीम के हिस्से हैं. अभी हाल में हमारे पास एक प्रस्ताव आया कि हमारा जो जवान रूरल एरिया से आता है, ज़्यादातर तबक़ा खेतिहर है, जिसके पास थोड़ी-बहुत ज़मीन होती है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं. इस प्रस्ताव के अंतर्गत हमने पाया कि अगर हम उन्हें ऑरगेनिक फॉर्मिंग की ट्रेनिंग दिलवाएं तो यह संस्था (मोरारका फाउंडेशन) उनसे उनके घर पर उनकी उपज लेने के लिए तैयार हैं. मुझे लगता है कि यह एक ऐसी स्कीम है, जिससे सेना के बड़े तबक़े का फ़ायदा हो सकता है. वह अपने घर जाकर ट्रेनिंग पाकर इस चीज़ को अगर शुरू करे और उसे यह फ़िक्र न हो कि सामान मंडी में ले जाना है, कोई आदमी ख़ुद आकर ख़रीद ले जाएगा और ऐसा सामान, जिसका मूल्य आम चीज़ से तीन-चार गुना ज़्यादा है तो उसे फ़ायदा होगा. हमने सेना में ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को एक स्टेज तक पहुंचाया. समय और होता तो मैं यह चाहता था कि इसे जिस स्टेज तक हमने सोचा है, पूरा हो सके. मुझे पूरी आशा है कि जो प्रक्रिया हमने चला दी है, वह पूरी होगी, उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी. सेना और जवानों के लिए मेरा संदेश यही है कि हम हमेशा सेना के हित में काम करें. जहां भी हम जाएं, अपना सिर उठाकर कहें कि यह सेना हमारे देश की है और देश हमारे लिए सर्वोपरि है. हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हम जो भी करें, वह सेना के वैल्यू सिस्टम के अंदर करें.

(चौथी दुनिया के एडिटर इन चीफ संतोष भारतीय से हुई बातचीत पर आधारित)

feedback@chauthiduniya.com

साउथ ब्लॉक

अनूप कुमार और विंद्रा स्वरूप एएस बनेंगे

1981 बैच के आईएएस अधिकारी अनूप कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया जाएगा. वह संगीता गैरोला की जगह लेंगे, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय में सचिव बनाया गया है. इसी बैच के आईएएस अधिकारी विंद्रा स्वरूप को विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है.

राजन कोटच और नवीन सोना निदेशक बने

1979 बैच के आईएएस अधिकारी राजन एस कोटच को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बनाया गया है. वह अरुण माथुर की जगह लेंगे. इसी तरह 2000 बैच के आईएएस अधिकारी एन नवीन सोना को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का निदेशक बनाया गया है. वह राजन सहगल की जगह लेंगे.

ए के जैन योजना आयोग जाएंगे

1986 बैच के आईएएस अधिकारी ए के जैन को योजना आयोग में सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है. वह डॉ. सुरई प्रकाश सेठ की जगह लेंगे.

सौरभ गर्ग और अनु अग्रवाल संयुक्त सचिव बने

1991 बैच के आईएएस अधिकारी सौरभ गर्ग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह मीना अग्रवाल की जगह लेंगे. इसी बैच की आईएएस अधिकारी अनु अग्रवाल को नाको (नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन) का संयुक्त निदेशक बनाया गया है.

मनोज झलानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में

1987 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज झलानी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में जेएस बनाया गया है. वह ब्रज किशोर प्रसाद की जगह लेंगे.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 04 अंक 04
दिल्ली, 02 अप्रैल-08 अप्रैल 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)
सी-20, ट्रांस यमुना, एनएच-2, आगरा
फोन : 0526-4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर-440012
फोन नं : 0712-2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888, 6452888, 011-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91-9266627366
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

गांधी परिवार से पुलक चटर्जी का रिश्ता दशकों पुराना है. पुलक चटर्जी संजय गांधी की पसंद हुआ करते थे.

सोनिया के फ़रमाबरदार पुलक चटर्जी
चला रहे हैं सरकार मनमोहन लाचार

मीडिया में कब कौन सी ख़बर लीक की जाए, किस घोटाले से पर्दा कब उठाया जाए, उस घोटाले में किसकी गर्दन फंसाई जाए, ताकि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की राह आसान हो सके और इसके लिए कौन सी चाल चली जाए, यह सब कुछ पुलक चटर्जी ही तय करते हैं.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

रूबी अरुण

यूं तो कहने को मनमोहन सिंह देश के वज़ीरे आज़म हैं, पर हकीक़त में देखा जाए तो फ़िलहाल उनकी भूमिका महज़ एक प्यादे भर की रह गई है, क्योंकि देश की बागडोर उनके हाथ में नहीं है. आर्थिक, वाणिज्यिक मामले हों या देश की सुरक्षा से जुड़े मसले या फिर विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और उनकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने की बात हो, इन सभी अहम मुद्दों पर फ़ैसला मनमोहन सिंह नहीं, बल्कि कोई और लेता है. टाटा, अंबानी एवं जिंदल जैसे उद्योगपति अपनी–अपनी परेशानियों को लेकर भले ही प्रधानमंत्री से मुलाक़ात करते हों, पर उनकी मुश्किलों का निपटारा कोई और करता है और इस शख्स का नाम है पुलक चटर्जी. पुलक 1974 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव के पद पर तैनात हैं. पुलक एक ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेहद अजीज़ और खास हैं. सोनिया गांधी की मर्ज़ी से ही पुलक को पीएमओ में बैठाया गया है. लिहाज़ा पुलक का रुतबा इतना बुलंद है कि पीएमओ में उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता. उनकी धमक का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब उन्हें सुपर पीएम के उपनाम से पुकारा जाने लगा है. इसकी वज़हें भी हैं. मीडिया में कब कौन सी ख़बर लीक की जाए, किस घोटाले से पर्दा कब उठाया जाए, उस घोटाले में किसकी गर्दन फंसाई जाए, ताकि राहुल गांधी की राह आसान हो सके और इसके लिए कौन सी चाल चली जाए, यह सब कुछ पुलक चटर्जी ही तय करते हैं.

पुलक को प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया जा सके , इसकी खातिर मनमोहन सिंह के बहुत विश्वस्त सहयोगी रहे टीकेए नायर को प्रमुख सचिव पद से हटाकर सलाहकार बना दिया गया. जबकि टीकेए नायर 2004 से पुलक के आने तक लगातार प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के तौर पर काम कर रहे थे. कुछ दिनों पहले तक पीएमओ में बेहद ताक़तवर रहे कुट्टी नायर को भी दरकिनार कर दिया गया है. आलीशान दफ्तर में बैठकर राजकाज संभालने वाले कुट्टी नायर अब एक छोटे से कमरे में बैठकर अपना वक़्त बिताते हैं. पुलक के इक़बाल के सामने क्या पी चिदंबरम, क्या अंबिका सोनी और प्रणब मुखर्जी, किसी की मर्ज़ी नहीं चल रही. पुलक के आने के कुछ वक़्त बाद की बात है कि गृहमंत्री पलनिअप्पम चिदंबरम को अपनी बीमार मां को देखने के लिए तमिलनाडु जाना पड़ा. तब सीसीईए की बैठक पर मीडिया को ब्रीफ करने के लिए जन सूचना अधिकारी नीलम कपूर ने अंबिका सोनी का नाम सुझाया, जो पुलक चटर्जी को ज़रा भी नहीं भाया और उन्होंने अंबिका के बजाय इसके लिए सलमान खुर्शीद को आगे कर दिया. मतलब यह कि जो भी कैबिनेट बैठकें होती हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स मीडिया को ब्रीफ करते हैं, उस एक–एक बात की जानकारी पुलक चटर्जी को दी जाती है. फिर पुलक ही यह तय करते हैं कि बैठक में किन बातों पर चर्चा होगी और कौन सा मंत्री मीडिया को क्या बताएगा.

सोनिया गांधी से मिली शह से पुलक कुछ इस क़दर जलवा अफरोज़ हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय से गोपनीय जानकारी भी बिना उनकी नज़र से गुज़रे नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइज़र के पास नहीं जा सकती. सीबीआई, आईबी एवं रॉ जैसी जांच और ख़ुफ़िया एजेंसियां कोई भी ख़ुफ़िया जानकारी मिलते ही उसे सबसे पहले पुलक से शेयर करती हैं, फिर पुलक उस बात को सोनिया गांधी तक पहुंचाते हैं. लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस बात से विचलित नहीं हैं. शायद वह सरकार के औपचारिक मुखिया बनकर ही ख़ुश हैं. तभी इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की कोई भूमिका ही नहीं होती यानी वह दरकिनार होते हैं. पीएमओ के कामकाज की शैली में यह आमूलचूल बदलाव है, जो मामूली नहीं है. यक़ीनन यह तब्दीली पीएमओ के काम करने के स्वभाव, सरकार और पार्टी के कामकाज में भी परिवर्तन का इशारा है. दरअसल, पुलक के आने के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा बेहद गर्म रही कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद राहुल गांधी देश की बागडोर संभाल सकें , इसकी खातिर पुलक चटर्जी पीएमओ को तैयार कर रहे हैं. राहुल गांधी के मिजाज़ के मुताबिक़ ही वहां कारिंदे भी रखे जाने लगे थे, पर उत्तर प्रदेश में हुई करारी हार के बाद फ़िलहाल कांग्रेस का राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का अभियान तो थमा है, लेकिन पुलक अपने मिशन को बदस्तूर अमलीजामा पहनाने में लगे हैं. वह राहुल गांधी को संभावित प्रधानमंत्री मानकर उनकी खातिर रोड मैप तैयार करने में लगे हैं, जिसके तहत पुलक चटर्जी ने सभी मंत्रालयों पर मश्कें कसना भी शुरू कर दिया है. पुलक चटर्जी के निशाने पर खास तौर पर वे मंत्रालय हैं, जो आधारभूत अधोसंरचना से जुड़े हैं, जिनमें ऊर्जा, कोयला, भूतल, शिपिंग, खनन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण एवं वाणिज्य शामिल हैं. चटर्जी ने इन मंत्रालयों को हिदायत दी है कि वे सभी अपना–अपना लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करें. यही नहीं, सचिव स्तर के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश मिले हैं कि अगर वे निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं कर सकते तो त्यागपत्र दे दें.

गांधी परिवार से पुलक चटर्जी का रिश्ता दशकों पुराना है. पुलक चटर्जी संजय गांधी की पसंद हुआ करते थे. अस्सी के दशक में संजय गांधी को सुल्तानपुर के लिए एक अदद डीएम की तलाश थी, उस वक़्त विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संजय गांधी से पुलक चटर्जी को सुल्तानपुर का डीएम बनाने की सिफारिश की थी. जब सोनिया एनडीए सरकार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं, तब पुलक उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हुआ करते थे. पुलक चटर्जी न सिर्फ़ गांधी परिवार के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के ज़िलाधिकारी रह चुके हैं, बल्कि वह राजीव गांधी फाउंडेशन में भी अहम ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं. पीएमओ में दोबारा तैनात होने के पहले पुलक वर्ल्ड बैंक में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे. सोनिया गांधी पिछले दिनों जब अपने इलाज़ के सिलसिले में अमेरिका गई थीं, तब सोनिया गांधी के इलाज़ से लेकर उनके परिवार के आतिथ्य तक की व्यवस्था पुलक ने ही की थी. इसी दरम्यान पुराने ताल्लुकातों ने फिर से अपना रंग दिखाया और पुलक को भारत वापस बुला लिया गया, ताकि वह सोनिया गांधी की आंख, नाक और कान बनकर प्रधानमंत्री कार्यालय में होने वाली सभी गतिविधियों पर न सिर्फ़ नज़र रखें, बल्कि सरकार के सभी अहम निर्णय सोनिया गांधी की मर्ज़ी के मुताबिक़ हों, इसका खास ख्याल रखें. पुलक को यह बात समझाने के लिए प्रियंका गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन में दो मर्तबा लंबी मीटिंग भी की. पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस नीत सरकार और संगठन के स्तर पर जो राजनीतिक दुश्वारियां पैदा हुई हैं, जो दरारें आई हैं, उन्हें पाटने की गरज से भी सोनिया गांधी ने पुलक चटर्जी को प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठाया है. हालांकि पुलक पहले भी सचिव के तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके हैं, पर इस बार खास बात यह है कि उन्होंने मनमोहन सिंह के बेहद विश्वस्त एवं खासमखास रहे टीएके नायर की जगह ली है. हर गुरुवार जिमखाना क्लब में सत्तर के दशक के रूमानी गीतों पर झूमने और डांस करने वाले पुलक सोनिया गांधी के मिजाज़, उनकी भंगिमाओं के उतार–चढ़ाव और पसंद–नापसंद से बहुत अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं. इसलिए सोनिया उन पर आंखें मूंदकर भरोसा करती हैं. यही वज़ह है कि पीएमओ में आने वाले आगंतुक प्रधानमंत्री से मिलने के बजाय पुलक से मिलने के ज़्यादा इच्छुक होते हैं. पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक से एक टीम भारत आई थी, पीएमओ के अधिकारी यह जानकार हैरान रह गए कि उस टीम की कोई रुचि मनमोहन सिंह से मिलने में नहीं थी.

पुलक को अभी तक राज्यमंत्री का भी दर्ज़ा नहीं मिला है, लेकिन उनकी चौखट पर काबीना मंत्री, राज्यमंत्री और दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री लाइन लगाकर खड़े होते हैं. बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय विसेंट जार्ज की देहरी पर मंत्री एड़ियां घिसते दिखाई देते थे. और तो और, प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पर पीएमओ ज्वाइन करने वाले पत्रकार पंकज पचौरी मनमोहन सिंह का महिमा मंडन करने के बजाय पुलक की ईमेज मेकिंग में जुटे पड़े हैं. यह पंकज पचौरी की मजबूरी भी है, वरना पूर्व मीडिया एडवाइज़र हरीश खरे की तरह उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. हालात भी कमोबेश कुछ ऐसे बन गए थे. पुलक किसी और सलाहकार की तलाश में थे, लेकिन हवा का रुख़ भांपते हुए पंकज पचौरी ने पुलक चटर्जी की जी हुज़ूरी करना मुनासिब समझा और उनकी सेवा में लग गए. पंकज पचौरी ने नया शिगूफ़ा छोड़ा है. वह सीनियर जर्नलिस्ट्स को राज्यसभा भेजने का लालच दे रहे हैं और बदले में उनसे कांग्रेस का एजेंडा बरास्ता पुलक चटर्जी आम अवाम के सामने परोसने की शर्त रख रहे हैं. इन पत्रकारों में बरखा दत्त, विनोद शर्मा, विनोद मेहता, राजदीप सरदेसाई, आलोक मेहता एवं मृणाल पांडेय के नाम अहम हैं. पंकज पचौरी के कहने पर ये पत्रकार 10 जनपथ के बेहद खास सुमन दुबे की परिक्रमा में लग चुके हैं. पंकज के इन दांव–पेंचों ने पुलक का मन थोड़ा नरम कर दिया है. फ़िलहाल पंकज अपनी जगह बने तो हैं, पर पुलक के सचिव की भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि पीएमओ के अन्य अधिकारी पुलक के इस नादिरशाही रवैये से परेशान नहीं हैं, पर किसी की मजाल नहीं कि वह चूं भी कर सके, क्योंकि सबको पुलक के कद का अंदाज़ा है. जब विपक्ष से लड़ने–जूझने की रणनीति बनाने और पार्टी के क्राइसिस मैनेजमेंट पर विचार करने वाला गुट, जिसमें अंबिका सोनी, गुलाम नबी आज़ाद, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल एवं पवन बंसल जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं, भी पुलक की जानकारी में संसद भवन के कमरा नंबर 9 या फिर अंबिका सोनी के कमरे में बैठकर अहम निर्णय लेता है, तब भला इस कद्दावर नौकरशाह के आगे दूसरे नौकरशाहों की क्या बिसात! बहरहाल, यूपीए–2 में जिस क़दर सरकार और पार्टी के बीच दरार गहरी हो चुकी थी, मनमुटाव बढ़ चुका था और पीएमओ मनमानी पर उतर आया था, उसके निराकरण के लिए सोनिया गांधी पुलक चटर्जी का इस्तेमाल बख़ूबी कर रही हैं. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सही मायनों में कठपुतली प्रधानमंत्री बने हुए हैं.

ruby@chauthiduniya.com

टी.के.ए.नायर पुलक चटर्जी

सोनिया गांधी से मिली शह से पुलक कुछ इस क़दर जलवा अफरोज़ हैं कि देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय से गोपनीय जानकारी भी बिना उनकी नज़र से गुज़रे नेशनल सिक्यूरिटी एडवाइज़र के पास नहीं जा सकती. सीबीआई, आईबी एवं रॉ जैसी जांच और ख़ुफ़िया एजेंसियां कोई भी ख़ुफ़िया जानकारी मिलते ही उसे सबसे पहले पुलक से शेयर करती हैं, फिर पुलक उस बात को सोनिया गांधी तक पहुंचाते हैं. लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस बात से विचलित नहीं हैं. शायद वह सरकार के औपचारिक मुखिया बनकर ही ख़ुश हैं.

मुलायम ने इस मौक़े पर सपा के चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए किए सभी वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

बिहार

एसी-डीसी बिल

सीबीआई जांच की तलवार

सरोज सिंह

पटना उच्च न्यायालय के बाद बिहार में एसी–डीसी बिल में 67 हज़ार करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है. आम भाषा में समझें तो यह मामला ख़र्च के लिए सरकारी ख़ज़ाने से निकाली गई राशि का हिसाब न देने का है. इसे लेकर सरकार पर घोटाले का शक किया जा रहा है. विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है. इस मामले में वकील अरविंद शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका 970/2012 दायर की थी. बीते 16 मार्च को इसी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

एडवांस कंटिजेंट यानी एसी बिल और डिटेल्ड कंटिजेंट यानी डीसी बिल का मामला पहले पटना हाईकोर्ट में भी गूंज चुका है. अरविंद कुमार शर्मा ने ही रिट याचिका 1710/2010 दायर करके यह मामला उठाया था. याचिका में कहा गया था कि मिड डे मील, इंदिरा आवास एवं मनरेगा सहित कई योजनाओं में भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, पैसों का दुरुपयोग एवं गबन हुआ है. सामान्य व्यय के लिए भी एसी बिल से मोटी रक़म ट्रेजरी से निकाल ली गई. 2002–03 से लेकर 2007–08 तक 11 हज़ार 412 करोड़ रुपये का डीसी बिल बिहार ट्रेजरी कोर्ट में 322/2 के तहत नहीं जमा किया गया है. इसलिए इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए और संबंधित धनराशि की वसूली कराई जाए. 15 जुलाई, 2010 को उच्च न्यायालय ने पाया कि यह रिट याचिका देश में अपने आप में अद्वितीय लोकहित याचिका है. सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ग़रीबों के हित के पैसों का गबन न हो. सरकार को इसकी जांच स्वयं सीबीआई से कराने की कार्रवाई करनी चाहिए, पर वह इसका विरोध कर रही है. कोर्ट ने 26 जुलाई, 2010 को सीबीआई के डायरेक्टर एवं ज्वाइंट डायरेक्टर को हाज़िर होने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि लोक लेखा समिति इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है. इससे पहले बहस के दौरान अरविंद कुमार शर्मा के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि चारा घोटाले में भी सरकार ने यह तर्क दिया था कि मामला जब पीएसी के पास है तो सीबीआई जांच नहीं होगी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का निर्देश दिया था. यहां तक कि टू जी स्पेक्ट्रम मामले में भी पीएसी वाले तर्क को ख़ारिज कर दिया गया था. उड़ीसा में भी मनरेगा से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट पर ही जांच हो रही है, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया. इसके बाद अरविंद शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले को रखा. आवेदक ने मूल रूप से कोर्ट से प्रार्थना की कि सीएजी की रिपोर्ट में अनियमितता की बात आई है. उच्च न्यायालय ने पहले जांच का निर्देश दिया था, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए. अरविंद शर्मा के अधिवक्ताद्वय मुकुल रोहतगी एवं दीनू कुमार ने इस एसी–डीसी से जुड़े सारे तथ्यों से कोर्ट को अवगत कराया.

अरविन्द शर्मा

दीनू बाबू

रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि पीएसी को मामले की अपराधिकता देखने का अधिकार नहीं है. याचिका में कहा गया कि सीएजी ने बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया है कि राज्य सरकार ने 11 हज़ार करोड़ रुपये के जो वाउचर सौंपे हैं, उनमें मात्र 38 करोड़ रुपये के वाउचर सही हैं. इसलिए सरकारी धन की यह बहुत बड़ी अनियमितता है. मूल वाउचर डीसी बिल के साथ नहीं हैं. बहस के बाद न्यायमूर्ति डी के जैन एवं न्यायमूर्ति ए आर दवे की खंडपीठ ने बिहार सरकार और कैग से जवाब–तलब किया और इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि एसी–डीसी बिल में सीबीआई जांच ही सारी अनियमितताओं को सामने ला सकती है. जितने बड़े पैमाने पर पैसों की लूट हुई है, उसका उदाहरण खोजे नहीं मिलता है. घोटाले की राशि लगातार बढ़ती जा रही है. पीएसी की जांच के साथ सीबीआई की जांच भी कई मामलों में हुई है. उच्चतम न्यायालय ने भी कई मामलों में ऐसे निर्देश दिए हैं. इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से एसी–डीसी मामले की सीबीआई जांच के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. याची अरविंद शर्मा ने बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने गबन की राशि देखते हुए बिहार सरकार और कैग को नोटिस दिया.

feedback@chauthiduniya.com

अपनों ने खोला विनय सिन्हा का भेद!

नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का दावा कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ़ उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष विनय कुमार सिन्हा की फैक्ट्री पर आयकर विभाग के छापे में आटे के बोरे से चार करोड़ छह लाख रुपये पकड़े जाते हैं. इसके अलावा रियल इस्टेट कारोबार में निवेश के कई काग़ज़ात भी आयकर विभाग के हाथ लगते हैं. कथनी और करनी का यही विरोधाभास सुशासन को शक के घेरे में लाता है. इससे पहले भी जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन के ठिकानों पर आयकर का छापा पड़ चुका है और इस कारण उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था. रंजन भी रियल इस्टेट कारोबार से जुड़े रहे हैं. आयकर अधिकारी सिन्हा के यहां मिले पैसों एवं काग़ज़ात की सघन जांच कर रहे हैं. पूरी जांच के बाद बरामदगी का सही आंकड़ा सामने आएगा, लेकिन आयकर विभाग के सूत्र बताते हैं कि लगभग 12 करोड़ रुपये की ऐसी संपत्ति का पता लगाया गया है, जिसका हिसाब नहीं दिया गया था. सही तस्वीर पूरी जांच के बाद सामने आएगी. राजनीतिक सूत्रों की बातों पर भरोसा करें तो किसी अपने ने ही विनय सिन्हा का भेद खोल दिया. आटे के बोरे में पैसे रखे हैं, इतनी सटीक जानकारी आयकर विभाग तक कैसे पहुंची, इस बात के पोस्टमार्टम में माथा खफाया जा रहा है. माना जा रहा है कि कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा विनय सिन्हा से टकराने लगी थी. उन्हें सबक़ सिखाने के लिए यह पूरी व्यूह रचना रची गई, लेकिन जदयू के लोग ठीक बिहार दिवस के दिन इन छापों का राज़ समझने में लगे हैं. उन्हें लगता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली में बैठे कुछ नेता इस तरह की ओछी हरकत करा रहे हैं. आटे के बोरे में मिले चार करोड़ छह लाख रुपये का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है. लोजपा का आरोप है कि यह पैसा नीतीश कुमार का हो सकता है, क्योंकि विनय सिन्हा नीतीश के काफ़ी क़रीबी हैं और जदयू से जुड़े हैं. लोजपा के प्रधान महासचिव राघवेंद्र कुशवाहा एवं प्रवक्ता ललन चंद्रवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में आने से पहले नीतीश कुमार विनय सिन्हा के मकान में ही रहते थे. इसलिए इस मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. राजद सांसद राम कृपाल यादव का मानना है कि यह बहुत गंभीर मामला है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विनय सिन्हा के मकान से ही नीतीश कुमार ने कई चुनाव लड़े हैं. पूर्व विधान पार्षद पी के सिन्हा के अनुसार, इस मामले में पूरी तरह नीतीश कुमार दोषी हैं, विनय सिन्हा को तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है. मैंने तो भ्रष्टाचार के मामले में ही नीतीश से दूरी बनाई, अब सारी बातें जनता के सामने आ रही हैं. इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए. दरअसल, यह पूरा मामला तब सामने आया, जब कर चोरी के मामले में आयकर अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने पूजा फूड प्रोडक्ट, दीघा के ठिकानों पर छापेमारी की. टीम ने कंपनी के मालिकों के सीता सदन, राजापुर पुल और उत्तरी श्रीकृष्णपुरी स्थित आवासों पर एक साथ छापेमारी करके करोड़ों रुपये की अनियमितता उजागर की. विनय कुमार सिन्हा, अविनाश कुमार एवं राजेश कुमार सिंह द्वारा संचालित पूजा फूड प्रोडक्ट में छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारी उस समय स्तब्ध रह गए, जब आटे के एक बोरे से 4 करोड़ छह लाख रुपये मिले. आयकर विभाग द्वारा राजधानी पटना में यह अब तक की सबसे बड़ी ज़ब्ती है. विभागीय अधिकारियों ने कंपनी के खातों एवं काग़ज़ात की जांच की. इस क्रम में उन्होंने कर संबंधी बड़ी अनियमितता के साथ-साथ कंपनी मालिकों द्वारा हाल के दिनों में अर्जित की गई अकूत संपत्ति भी उजागर की. कंपनी के तीनों पार्टनर पटना में 50 से अधिक फ्लैटों के मालिक हैं. उन्होंने कई प्लॉट डेवलपर्स को भी दे रखे हैं. छापेमारी का नेतृत्व आयकर अन्वेषण ब्यूरो के सहायक निदेशक मनीष कुमार झा एवं सौरभ राय ने किया.

उत्तर प्रदेश

मुलायम धर्मगुरुओं की चौखट पर

अजय कुमार

2007 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की बेरुख़ी का नतीजा देख चुके सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव अब कोई ग़लती नहीं करना चाहते हैं. उन्हें पता है कि 2014 के आम चुनाव के मद्देनज़र केंद्र की कांग्रेस सरकार मुसलमानों को रिझाने के मामले में पीछे हटने वाली नहीं है. इसलिए मुलायम सिंह ने अभी से पेशबंदी शुरू कर दी है. वहीं दूसरी तरफ़ समाजवादी पार्टी के भीतर और बाहर मौजूद मुस्लिम नेतृत्व भी मौक़े का पूरा फ़ायदा उठाने को बेताब दिख रहा है. भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों से किए गए वादे पूरे करने का दबाव बढ़ने लगा है. कुछ मुस्लिम नेता उनसे मिलकर मुसलमानों के लिए सौदेबाज़ी कर रहे हैं, तो मुलायम स्वयं भी वोट के लिए आभार प्रकट करने के बहाने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मुस्लिम धर्मगुरुओं के यहां दस्तक देने पहुंच रहे हैं. मुलायम अकेले ही इस काम में नहीं लगे हैं. अखिलेश सिंह भी मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलकर उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं. वैसे अपने मंत्रिमंडल में अच्छी ख़ासी तादाद में मुसलमान नेताओं को शामिल करने के अलावा हाईस्कूल पास मुस्लिम लड़कियों को तीस हज़ार रुपये की मदद और मुसलमानों के क़ब्रिस्तान आदि को अवैध क़ब्ज़ों से मुक्त कराने के लिए चहारदीवारी बनवाने का आदेश देकर उनका विश्वास जीत चुके हैं. जावेद उस्मानी को मुख्य सचिव और आज़म ख़ां का अलिखेश सरकार में क़द बढ़ाकर भी मुसलमानों को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी है. कुछ दिन पूर्व मुलायम सिंह लखनऊ में प्रसिद्ध शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद से भी मिल चुके हैं.

भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों से किए गए वादे पूरे करने का दबाव बढ़ने लगा है. कुछ मुस्लिम नेता उनसे मिलकर मुसलमानों के लिए सौदेबाज़ी कर रहे हैं, तो मुलायम स्वयं भी वोट के लिए आभार प्रकट करने के बहाने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मुस्लिम धर्मगुरुओं के यहां दस्तक देने पहुंच रहे हैं.

विशेष तौर पर अखिलेश लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं से नज़दीकी बढ़ाने में लगे हैं, तो मुलायम दिल्ली में इसी काम में व्यस्त हैं. इसी क्रम में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने गत दिनों दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुख़ारी और जमीयत उलेमा–ए–हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी से मुलाक़ात की, तो इन नेताओं ने मुलायम को मुसलमानों से किए गए वादे याद दिलाने में ज़रा भी देरी नहीं की. मुलायम ने इस मौक़े पर सपा के चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए किए सभी वादों को पूरा करने का भरोसा दिलाया. सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह जामा मस्जिद पहुंचे और विधानसभा चुनाव में पार्टी को खुलकर समर्थन करने वाले बुख़ारी से क़रीब 45 मिनट तक मुलाक़ात की. दोनों के बीच क्या बातें हुईं, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जा रहा है कि बुख़ारी ने मुसलमानों की कई समस्याओं से उनको अवगत कराया. जामा मस्जिद ट्रस्ट के प्रवक्ता राहत महमूद चौधरी ने बताया कि मुलायम सिंह शाही इमाम से मिले और उनसे आगे भी समर्थन देते रहने का आग्रह किया है. उन्होंने मुसलमानों के लिए चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने का भरोसा भी दिया है. चौधरी ने कहा कि शाही इमाम ने जेलों में बंद मुस्लिम युवकों को रिहा कराने, उर्दू को बढ़ावा देने और मुसलमानों को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने इस पर अमल करने का भरोसा दिया है. उनसे 18 फ़ीसदी आरक्षण की बात को व्यवहारिक रूप से अमल करने की बात कही गई है. यह बात सही है कि इसके लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन सरकार चाहे तो रास्ता निकाला जा सकता है.

ग़ौरतलब हो, हाल में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुख़ारी ने समाजवादी पार्टी का खुलकर समर्थन किया था. बुख़ारी के दामाद उमर अली ख़ान भी सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. जामा मस्जिद के शाही इमाम बुख़ारी से मुलाक़ात करने के बाद मुलायम सिंह जमीयत उलेमा–ए–हिंद के दफ्तर पहुंचे और मौलाना अरशद मदनी से मुलाक़ात की. मुलायम क़रीब आधे घंटे तक वहां रुके. यहां भी मुस्लिम समाज की समस्याओं पर खुलकर चर्चा हुई. मुलायम सिंह जहां भी जाते हैं, मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं से आगे भी समर्थन देने की बात करना नहीं भूलते. वह जानते हैं कि इमारत तभी मज़बूत बन सकती है, जब बुनियाद मज़बूत हो. मुलायम सिंह मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं से ही समर्थन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी अभी से 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लेने की बात कह रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र के माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी इस प्रक्रिया के चलते कोल इंडिया से कुछ ब्लॉक मुफ्त ले लिए. ये ब्लॉक थे अगरझरी, वरोरा, मार्की, जामनी, अदकुली और गारे पेलम आदि.

चौथी दुनिया की रिपोर्ट सच साबित हुई

कोयला घोटाले का सच

कोयले को काला सोना कहा जाता है, काला हीरा कहा जाता है, लेकिन सरकार ने इस हीरे की बंदरबांट कर डाली और अपने प्रिय-चहेते पूंजीपतियों एवं दलालों को मुफ्त ही दे दिया. अगर 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला देश के सभी घोटालों की जननी है तो जिस घोटाले का चौथी दुनिया ने पर्दाफ़ाश किया है, वह देश में हुए अब तक के सभी घोटालों का पितामह है. देश में कोयला आवंटन के नाम पर क़रीब 26 लाख करोड़ रुपये की लूट हुई है. सीएजी की जो रिपोर्ट लीक हुई है और जिस तरह संसद में हंगामा हुआ, उससे यह साबित होता है कि चौथी दुनिया की रिपोर्ट सही थी.

चौथी दुनिया ने अप्रैल 2011 में कोयला घोटाले का पर्दाफ़ाश किया था. उस वक़्त न सीएजी रिपोर्ट आई थी, न किसी ने यह सोचा था कि इतना बड़ा घोटाला भी हो सकता है. उस वक़्त इस घोटाले पर किसी ने विश्वास नहीं किया. जिन्हें विश्वास भी हुआ तो आधा अधूरा हुआ. चौथी दुनिया ने आपसे अप्रैल 2011 में जो बातें कहीं, उस पर वह आज भी अडिग है. हमारी तहक़ीक़ात के मुताबिक़, यह कोयला घोटाला कम से कम 26 लाख करोड़ रुपये का है और यह इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है. संसद में जो हंगामा मचा, उसकी वजह यह थी कि एक अंग्रेजी अख़बार ने सीएजी की रिपोर्ट को छाप दिया. सीएजी इस रिपोर्ट में घोटाले की बात करती है, लेकिन उसने घोटाले की रक़म कम बताई है. सीएजी की लीक रिपोर्ट के मुताबिक़, यह घोटाला दस लाख सत्तर हज़ार करोड़ रुपये का है, लेकिन सरकार की तरफ़ से यह ख़बर दी गई कि सीएजी ख़ुद अपनी रिपोर्ट पर क़ायम नहीं है और जो ख़बर छपी है, वह झूठी है. सीएजी की एक चिट्ठी का हवाला देकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह ख़बर फैलाई. मज़ेदार बात यह है कि अगले ही दिन इस सीएजी की पूरी सच्चाई बाहर आ गई, जिसका निष्कर्ष यही निकलता है कि सीएजी ने घोटाले से इंकार नहीं किया है. वैसे समझने वाली बात यह है कि इस घोटाले के बारे में सभी पार्टियों को पहले से पता है, लेकिन फिर भी वे ख़ामोश रहीं. अख़बार में सीएजी की रिपोर्ट छपते ही मामले ने तूल पकड़ा और संसद में शोर शराबा शुरू हो गया. सीएजी की रिपोर्ट से एक बात यह साबित होती है कि चौथी दुनिया ने जो अप्रैल 2011 में कोयला घोटाले का पर्दाफ़ाश किया, वह सच है. हालांकि देश की तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया अब भी तटस्थ बैठा है. वह तय नहीं कर पा रहा है कि घोटाला है भी या नहीं. और अगर घोटाला है तो फिर कितने का है.

यह बात है 2006-07 की, जब शिबू सोरेन जेल में थे और सरकार तेज़ी से कोयला खदानों को मुफ्त बांटने लगी थी. सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोयले की खानें सिर्फ़ 100 रुपये प्रति टन की खनिज रॉयल्टी के एवज में बांट दी गईं. मतलब यह कि पहले मुफ्त में खदानें दे दी गईं, फिर इन खदानों से कोयला निकालने के बाद 100 रुपये प्रति टन के रेट से सरकार को पैसे मिलने का प्रावधान बनाया गया. ऐसा तब किया गया, जब कोयले का बाज़ार मूल्य 1800 से 2000 रुपये प्रति टन के ऊपर था. जब संसद में इस बात को लेकर कुछ सांसदों ने हंगामा किया, तब शर्मसार होकर सरकार ने कहा कि माइंस और मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 में संशोधन किया जाएगा और तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी. 2006 में यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया और यह माना गया कि जब तक दोनों सदन इसे मंज़ूरी नहीं दे देते और यह बिल पास नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी, लेकिन यह विधेयक चार साल तक लोकसभा में जानबूझ कर लंबित रखा गया और 2010 में ही यह क़ानून में तब्दील हो पाया. इस दौरान देश के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया. संसद में किए गए वादे से सरकार मुकर गई और कोयला खदान बांटने का गोरखधंधा चलता रहा. असल में इस विधेयक को लंबित रखने की राजनीति बहुत गहरी थी. यह नेताओं, अधिकारियों एवं उद्योगपतियों की बहुत बड़ी साज़िश है. इस विधेयक में साफ़-साफ़ लिखा था कि कोयले या किसी भी खनिज की खदानों के लिए सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. अगर यह विधेयक 2006 में ही पास हो जाता तो 26 लाख करोड़ रुपये नुक़सान नहीं होता. सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को मुफ्त कोयला नहीं बांट पाती. इस समयावधि में लगभग 21.69 बिलियन टन कोयले के उत्पादन क्षमता वाली खदानें निजी क्षेत्र के दलालों और पूंजीपतियों को मुफ्त दे दी गईं. कुल 63 ब्लॉक बांट दिए गए. इन चार सालों में लगभग 175 ब्लॉक आनन-फानन में पूंजीपतियों और दलालों को मुफ्त में दे दिए गए. वैसे बाहर से देखने में इस घोटाले की असलियत सामने नहीं आती, इसलिए हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि इस घोटाले से देश को कितना घाटा हुआ है. जो परिणाम सामने आया, वह चौंकाने वाला था. दरअसल, निजी क्षेत्र में कैप्टिव (संशोधित) ब्लॉक देने का काम 1993 से शुरू किया गया. कहने को ऐसा इसलिए किया गया कि कुछ कोयला खदानें खनन की दृष्टि से सरकार के लिए आर्थिक रूप से कठिन कार्य सिद्ध होंगी. इसलिए उन्हें निजी क्षेत्र में देने की ठान ली गई. ऐसा कहा गया कि मुनाफ़े की लालसा में निजी उपक्रम इन दूरदराज़ की और कठिन खदानों को विकसित कर लेंगे और देश के कोयला उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी. 1993 से लेकर 2010 तक कोयले के 208 ब्लॉक बांटे गए, जो कि 49.07 बिलियन टन कोयला था. इनमें से 113 ब्लॉक निजी क्षेत्र में 184 निजी कंपनियों को दिए गए, जो कि 21.69 बिलियन टन कोयला था. अगर बाज़ार मूल्य पर इसका आकलन किया जाए तो 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से इस कोयले का मूल्य 5,382,830.50 करोड़ रुपये निकलता है. अगर इसमें से 1250 रुपये प्रति टन काट दिया जाए, यह मानकर कि 850 रुपये उत्पादन की क़ीमत है और 400 रुपये मुनाफ़ा, तो भी देश को लगभग 26 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ. सबसे बड़ी बात है कि यह घोटाला सरकारी फाइलों में दर्ज है और सरकार के ही आंकड़े चीख़-चीख़कर कह रहे हैं कि यह घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है.

चौथी दुनिया ने एक साल पहले जो कोयला घोटाले का पर्दाफ़ाश किया, उसे सीएजी की रिपोर्ट ने सही ठहराया है. 2006 में कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर संसद में हंगामा हुआ था. इसके बाद सरकार ने संसद और लोगों को गुमराह करने का काम किया. सरकारी विधेयक लाने की बात कही गई, जिसके तहत यह नीलामी की जा सकेगी, लेकिन यह विधेयक चार साल तक लोकसभा में लंबित रखा गया, ताकि सरकार के जिन निजी खिलाड़ियों के साथ काले संबंध हैं, उन्हें इस दरम्यान कोयले के ब्लॉक जल्दी-जल्दी बांटकर ख़त्म कर दिए जाएं. इसमें कितनी रक़म का लेन-देन हुआ होगा, यह ज़ाहिर सी बात है, लेकिन अनियमितताएं यहीं ख़त्म नहीं हो जातीं. इस घोटाले से जुड़े कई सवाल हैं. सरकार की नीयत पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि उससे कई सारी ग़लतियां हुई हैं. एक तो मामला मुफ्त में कोयला खदानें देना और दूसरी यह कि जिन कंपनियों को कोयला खदानें दी गईं, उन्होंने सारे क़ानूनों को ताख़ पर रख दिया.

इस घोटाले में कई नियम तोड़े गए. ऐसे नियमों और शर्तों की अनदेखी की गई, जिन्हें किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता. ऐसी एक शर्त यह है कि लाइसेंस मिलने पर एक तय अवधि के बाद खनन शुरू हो जाना चाहिए. जिन खदानों में कोयले का खनन सतह के नीचे होता है, उनमें आवंटन के 36 माह बाद खनन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए. यदि खदान ओपन कास्ट क़िस्म की है तो यह अवधि 48 माह की होती है. अगर खदान जंगल में है तो यह अवधि छह महीने बढ़ा दी जाती है. नियम के मुताबिक़, इस अवधि में काम शुरू नहीं होता है तो खदान मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है, ताकि खदान और कोयले का उत्खनन बिचौलियों के हाथ न लगे, जो सीधे-सीधे तो कोयले का काम नहीं करते, बल्कि खदान ख़रीद कर ऐसे व्यापारियों या उद्योगपतियों को बेच देते हैं, जिन्हें कोयले की ज़रूरत है. इस गोरखधंधे में बिचौलिए मुंह मांगे दामों पर खदानें बेच सकते हैं. सरकार ने ऐसी किसी खदान का लाइसेंस रद्द नहीं किया, जो तय अवधि के भीतर उत्पादन शुरू नहीं कर पाईं. क्या खदान मालिकों पर इस देश का क़ानून लागू नहीं होता है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खदानें बिचौलियों को आवंटित की गई थीं, ताकि वे उन्हें आगे चलकर उद्योगपतियों को आसमान छूती क़ीमतों पर बेच सकें? यदि सरकार और बिचौलियों के बीच साठगांठ नहीं थी तो ऐसा कैसे हो गया? 2003 तक 40 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें अब तक सिर्फ़ 24 ने उत्पादन शुरू किया है. तो बाक़ी 16 कंपनियों के लाइसेंस ख़ारिज क्यों नहीं किए गए? 2004 में 4 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें आज तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया. 2005 में 22 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिनमें आज तक केवल 2 ब्लॉकों में ही उत्पादन शुरू हो पाया है. इसी तरह 2006 में 52, 2007 में 51, 2008 में 22, 2009 में 16 और 2010 में एक ब्लॉक का आवंटन हुआ, लेकिन 18 जनवरी, 2011 तक की रिपोर्ट के अनुसार, कोई भी ब्लॉक उत्पादन शुरू होने की अवस्था में नहीं है. पहले तो बिचौलियों को ब्लॉक मुफ्त दिए गए, जिसके लिए माइंस और मिनरल एक्ट में संशोधन को लोकसभा में चार साल तक रोके रखा गया. फिर जब उन बिचौलियों की खदानों में उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो भी उनके लाइसेंस रद्द नहीं किए गए. सरकार, बिचौलियों एवं फ़र्ज़ी कंपनियों के बीच साठगांठ होने की आशंका बढ़ जाती है. वरना आज 208 ब्लॉकों में से सिर्फ़ 26 में उत्पादन हो रहा हो, ऐसा न होता. सरकार कहती है कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना आवश्यक है. देश में ऊर्जा की कमी है, इसलिए अधिक से अधिक कोयले का उत्पादन होना चाहिए. इसी उद्देश्य से कोयले का उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहिए, लेकिन सरकार ने एक तरफ़ विकास का नारा देकर जनता को गुमराह किया और दूसरी तरफ़ देश की सबसे क़ीमती धरोहर बिचौलियों और उद्योगपतियों के नाम कर दी.

महाराष्ट्र के माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी इस प्रक्रिया के चलते कोल इंडिया से कुछ ब्लॉक मुफ्त ले लिए. ये ब्लॉक थे अगरझरी, वरोरा, मार्की, जामनी, अदकुली और गारे पेलम आदि. बाद में कॉरपोरेशन ने उक्त ब्लॉक निजी खिलाड़ियों को बेच दिए, जिससे उसे 750 करोड़ रुपये का फ़ायदा हुआ. यह भी एक तरीक़ा था, जिससे सरकार इन ब्लॉकों को बेच सकती थी, लेकिन ब्लॉकों को तो मुफ्त ही बांट डाला गया. ऐसा भी नहीं है कि बिचौलियों के होने का सिर्फ़ क़यास लगाया जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र की एक कंपनी, जिसका कोयले से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं था, ने कोयले के एक आवंटित ब्लॉक को 500 करोड़ रुपये में बेचकर अंधा मुनाफ़ा कमाया. मतलब यह कि सरकार ने कोयले और खदानों को दलाल पथ बना दिया, जहां पर खदानें शेयर बन गईं, जिनकी ख़रीद-फ़रोख्त चलती रही और जनता की धरोहर का चीरहरण होता रहा. अगर इस साल के बजट को भी देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र को एक लाख साठ हज़ार करोड़ रुपये आवंटित हुए. मूल ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को दो लाख चौदह हज़ार करोड़, रक्षा मंत्रालय को एक लाख चौसठ हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए गए. भारत का वित्तीय घाटा लगभग चार लाख बारह हज़ार करोड़ रुपये है. टैक्स से होने वाली आमद नौ लाख बत्तीस हज़ार करोड़ रुपये है. मतलब यह कि आम जनता की तीन साल की कमाई पर लगा टैक्स अकेले इस घोटाले ने निगल लिया. मतलब यह कि इतने पैसों में हमारे देश की रक्षा व्यवस्था को आगामी 25 सालों तक के लिए सुसज्जित किया जा सकता था. मतलब यह कि देश के मूल ढांचे को एक साल में ही चाक-चौबंद किया जा सकता था. सबसे बड़ी बात यह कि वैश्विक मंदी से उबरते समय हमारे देश का सारा क़र्ज़ चुकाया जा सकता था. विदेशी बैंकों में रखा काला धन आजकल देश का सिरदर्द बना हुआ है. बाहर देशों से अपना धन लाने से पहले इस कोयला घोटाले का धन वापस जनता के पास कैसे आएगा?

अब सवाल यह है कि इन कंपनियों में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये क़ानून भी तोड़ती हैं, फिर भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब इन कंपनियों को कोयला निकालना ही नहीं था तो इन्होंने इन खदानों पर क़ब्ज़ा क्यों जमा लिया? पिछले एक महीने से सरकार कह रही है कि देश में कोयले की कमी है. हक़ीक़त यह है कि इस घोटाले में जितना कोयला निजी कंपनियों को दिया गया है, वह अगले 50 सालों तक के लिए पर्याप्त है. इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि यह घोटाला एक साज़िश के तहत किया गया है. इस घोटाले को अधिकारियों, नेताओं एवं पूंजीपतियों की साठगांठ से अंजाम दिया गया है. देश की खनिज संपदा, जिस पर 120 करोड़ भारतीयों का समान अधिकार है, को इस सरकार ने मुफ्त में अनैतिक कारणों से प्रेरित होकर बांट दिया. अगर इसे सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया अपना कर बांटा जाता तो भारत को इस घोटाले से हुए 26 लाख करोड़ रुपये के राजस्व घाटे से बचाया जा सकता था और यह पैसा देशवासियों के हित में ख़र्च किया जा सकता था.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया ने एक साल पहले जो कोयला घोटाले का पर्दाफ़ाश किया, उसे सीएजी की रिपोर्ट ने सही ठहराया है. 2006 में कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर संसद में हंगामा हुआ था. इसके बाद सरकार ने संसद और लोगों को गुमराह करने का काम किया. सरकारी विधेयक लाने की बात कही गई, जिसके तहत यह नीलामी की जा सकेगी, लेकिन यह विधेयक चार साल तक लोकसभा में लंबित रखा गया, ताकि सरकार के जिन निजी खिलाड़ियों के साथ काले संबंध हैं, उन्हें इस दरम्यान कोयले के ब्लॉक जल्दी-जल्दी बांटकर ख़त्म कर दिए जाएं. इसमें कितनी रकम का लेन-देन हुआ होगा, यह ज़ाहिर सी बात है, लेकिन अनियमितताएं यहीं ख़त्म नहीं हो जातीं. इस घोटाले से जुड़े कई सवाल हैं.

राजस्थान के कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा मिलने के बाद राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर और पाली ज़िले के क़रीब 127 गांवों के हज़ारों लोगों के समक्ष सर छुपाने और रोज़ी-रोटी का संकट पैदा हो गया है.

कुंभलगढ़ नेशनल पार्क

फ़िक्र जानवरों की, आदिवासियों की नहीं

ज़मीन का पट्टा वितरित नहीं

कुंभलगढ़ नेशनल पार्क के विरोध में राजसमंद, उदयपुर और पाली ज़िलों से प्रभावित गांवों के लोग अब आर-पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना चुके है. आदिवासियों में सरकार के ख़िलाफ़ आक्रोश है, लेकिन इन ज़िलों के मौजूदा सांसदों और विधायकों को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है. इन जनप्रतिनिधियों ने नेशनल पार्क के चलते होने वाले विस्थापन के बारे में सरकार के सामने पीड़ित लोगों का कोई पक्ष नहीं रखा है. ग़ौरतलब है कि वर्ष 2006 में वन क़ानून बनने के बाद राज्य सरकार ने महज़ 32 हज़ार वनवासियों को ही आधे-अधूरे पट्टे वितरित किए हैं. बाक़ी बचे लाखों परिवारों का क्या होगा, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है.

मांगू राम भील को यह समझ में नहीं आ रहा कि वह अपने परिवार के साथ जाए तो जाए कहां. वह कभी अरावली की ऊंची पहाड़ियों की तरफ़ देखता है, तो कभी नज़रें झुका कर ज़मीन की तरफ़. अरावली श्रृंखला देखकर शायद, उसे अपने पुरखों की कहानियां याद आ रही हैं, जिनमें उसने सुना था कि किस तरह चित्तौड़ के महाराजा महाराणा प्रताप ने मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई में यहां निवास करने वाले भील आदिवासियों की मदद ली थी. राणा प्रताप का व्यवहार भी भीलों के प्रति मित्रवत रहा. यही कारण था कि सदियों से यहां निवास करने वाले भीलों व अन्य जनजातियों के लोग अपने लोकगीतों में राणाओं व भीलों की वीरता का गुणगान करते हैं, लेकिन अरावली की गोद में कई पीढ़ियों से रहने वाले हज़ारों भीलों को राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर बेघर करने की क़वायद शुरू हो चुकी है.

अभिषेक रंजन सिंह

राजस्थान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हज़ारों लोगों को विस्थापित करने की पूरी तैयारी कर ली है. इस बार विस्थापन का यह खेल किसी उद्योगपति को कारख़ाना लगाने के नाम पर ज़मीन मुहैया कराने के लिए नहीं खेला जा रहा. दरअसल, एक उद्यान का दायरा बढ़ाकर उसे राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) बनाने की ख़ातिर आदिवासियों को उनके घरों से खदेड़ने का फ़रमान जारी कर दिया गया है. राज्य सरकार की दलील है कि इससे पर्यटन उद्योग तेज़ी से बढ़ेगा और राजस्व में वृद्धि होगी. ग़रीब आदिवासियों के आंसुओं की एवज में विदेशी सैलानियों के गोरे चेहरे पर मुस्कान पैदा कर धन बटोरने की चाहत रखने वाली सरकार का यह कौन सा अर्थशास्त्र है, इसे समझने की ज़रूरत है.

राजस्थान के कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा मिलने के बाद राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर और पाली ज़िले के क़रीब 127 गांवों के हज़ारों लोगों के समक्ष सर छुपाने और रोज़ी-रोटी का संकट पैदा हो गया है. विकास के नाम पर विस्थापन का क्रूर खेल खेलने वाली केंद्र और राज्य सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आदिवासियों की जगह जानवरों को आश्रय देने के बाद, इस क्षेत्र में अपनी ज़मीन से बेदख़ल होने वाले लोगों को कहां बसाया जाएगा. ग़ौरतलब है कि कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले राजसमंद, उदयपुर और पाली ज़िले के दर्जनों गांव आदिवासी बहुल हैं. यहां निवास करने वालों में भीलों और गमेती आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है. कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद इसे अमलीजामा पहनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस बाबत राजसमंद ज़िला कलक्टर ने अधिसूचना जारी करते हुए इस क्षेत्र में निवास करने वालों से ज़मीन पर रहने के दावे मांगे हैं.

चौथी दुनिया से बात करते हुए राजसमंद के ज़िला कलेक्टर डॉ. प्रीतम बी. यशवंत ने वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम-1972 की धारा-21 का हवाला देते हुए कहा कि अधिसूचना में राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में आने वाले राजसमंद ज़िले के हिस्सों को उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, दक्षिण सीमा व पश्चिम सीमा में बांटा गया है. कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान परिक्षेत्र में आदिवासियों की बड़ी आबादी वर्षों से निवास करती है. चूंकि यह ज़मीन वन विभाग की है, लिहाज़ा नेशनल पार्क की मंज़ूरी मिलने के बाद उन्हें वहां से हटना होगा, ताकि यहां जानवरों को अच्छी तरह से बसाया जा सके. यह पूछे जाने पर कि 127 गांवों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को कहां बसाया जाएगा, इस सवाल का जवाब राजसमंद के ज़िला कलेक्टर नहीं दे सके. इस बारे में जब उप मुख्य वन अधिकारी भंवर सिंह चौहान से पूछा गया तो, उनका जवाब हैरान करने वाला था. चौहान के अनुसार, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा मिलने के बाद राजस्थान ख़ासकर मारवाड़ इलाक़े की तस्वीर बदल जाएगी. यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा. नेशनल पार्क आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी. उप मुख्य वन अधिकारी भंवर सिंह चौहान से जब यह पूछा गया कि कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को विकसित करने के बाद वहां रहने वाले हज़ारों आदिवासियों का क्या होगा और वह कहां जाएंगे, इस बात पर उन्होंने ख़ामोशी अख्तियार कर ली.

शासन-प्रशासन की इस चुप्पी से यह साबित होता है कि कुंभलगढ़ में सदियों से निवास करने वाले जनजातियों की क़ीमत पर नेशनल पार्क बनाने की घोषणा इस इलाक़े में एक ख़ूनी टकराव को आमंत्रण दे रही है. उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने पिछले साल नवंबर में कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद राजसमंद, उदयपुर और पाली ज़िलों में विरोध शुरू हो गया. सरकार के इस आदेश का तीव्र विरोध वहां के किसान-मज़दूर संगठनों के अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ता भी कर रहे हैं. राजसमंद में पेशे से पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता ओमप्रकाश शर्मा का कहना है कि केंद्र और राजस्थान सरकार कुंभलगढ़ नेशनल पार्क के नाम पर इस इलाक़े को नंदीग्राम बनाने की तैयारी कर ली है. शर्मा के मुताबिक़, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क बनाने से पहले सरकार ने यह नहीं सोचा कि यहां रहने वाले ग़रीब आदिवासियों का क्या होगा. प्रशासन ने बग़ैर किसी पूर्व तैयारी के इस जगह को ख़ाली करने की सूचना प्रकाशित कर दी. खानापूर्ति के नाम पर ज़िला प्रशासन ने लोगों को दो महीने के भीतर ज़मीन का पट्टा और इससे जुड़े दस्तावेज़ तथा दावा पेश करने को कहा है. सरकार के इस फ़रमान के बाद इन ज़िलों के लोग हलकान हैं.

पिछले दिनों राजसमंद ज़िला मुख्यालय में अखिल भारतीय किसान सभा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में यहां के हज़ारों आदिवासी किसान इकट्ठे हुए. इन आदिवासियों ने कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए ज़मीन से बेदख़ली को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की. उदयपुर की गोगुंदा, राजसमंद ज़िले की कुंभलगढ़ व पाली ज़िले की सादड़ी तहसील की क़रीब दो दर्जन पंचायतों के लोगों ने ज़िला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार का यह फ़ैसला उनके स्वाभिमान एवं हितों पर चोट करने वाला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए भील आदिवासियों को अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े. नेशनल पार्क के नाम पर हो रही इस बेदख़ली के बाद ग़रीब आदिवासी परिवारों का क्या होगा, वे कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जीएंगे? इसका जवाब न तो इन ज़िलों के कलेक्टरों के पास है और न ही यहां के वन अधिकारियों के.

सरकार राजस्थान में नक्सलवाद का बीज बो रही है

राजस्थान के भीलों की वीरता की कहानी हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है. मध्य काल में मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई में भील सेनाओं ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया था, लेकिन आज वही भील और अन्य आदिवासी समाज कुंभलगढ़ नेशनल पार्क की वजह से विस्थापित होने की कगार पर पहुंच चुका है. जिस ज़मीन पर उनकी पीढ़ियों ने गुज़र-बसर की, अब उसी ज़मीन से उन्हें भगाने की तैयारी हो रही है. विरोध करने पर प्रशासन दो टूक कहता है कि वह शासनादेश का पालन कर रहा है. सरकार के इस फ़ैसले से वनवासी हताश और परेशान हैं. हैरत इस बात की है कि पिछले कई महीनों से राजस्थान में नेशनल पार्क और आदिवासियों के विस्थापन का मुद्दा ज्वलंत है, लेकिन मीडिया और दिल्ली में राजनीति कर रहे नेताओं को इसकी भनक तक नहीं है. केंद्र सरकार समय-समय पर नक्सलवाद और उसके विस्तार को रोकने के लिए प्रभावित राज्य सरकारों के साथ राजधानी दिल्ली में बैठकें करती है, लेकिन जिस तरह कुंभलगढ़ नेशनल पार्क के नाम पर इलाक़े के आदिवासी विस्थापित होंगे, उससे इस क्षेत्र में नक्सलवाद पनपेगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता. ग़ौरतलब है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा सूबा है, जहां अब तक नक्सलवाद जैसी समस्या नहीं है. हालांकि इस राज्य में जिस तरह का सामाजिक वातावरण बन रहा है, उससे यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में नक्सलवाद पनप सकता है. केंद्र और राज्य सरकार की जैसी नीति है, उससे लगता है कि वे राजस्थान के मारवाड़ इलाक़े को नक्सलवाद की आग में झोंकना चाहती हैं. कुंभलगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में आने वाले आदिवासी अपनी ज़मीन किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते. वहीं दूसरी तरफ़ शासन-प्रशासन हर क़ीमत पर उस जगह को ख़ाली कराने पर अड़ा हुआ है. ऐसे में यहां की शांति भंग होने की आशंका बनी हुई है. सरकार को चाहिए कि वह कोई ऐसा सर्वमान्य हल निकाले, जिससे सरकार यहां के निवासियों की परेशानी भी हल हो जाए और सरकार का मक़सद भी पूरा हो सके.

उदयपुर ज़िले के प्रभावित गांव

प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गोगुंदा तहसील के बागड़, भानपुरा, कांबा, मघा, कोविया, ढिकोड़ा, जोरमा, सिंघाड़ा, बोखाड़ा, दियाण, सायरा, चावड़ावास, भाटों का सायरा, सेमड़, केसर सिंह जी का गुडा, चराओं का गुडा, बटेरी, कुर्रा सूरजपोल, मजावड़ा, माल, और निचला कुर्रा आदि क्षेत्र नेशनल पार्क के दायरे में आएंगे.

राजसमंद ज़िले के प्रभावित गांव

ग्वार, कुंभलगढ़ किला, आरेट, उदावड़, पोखरिया, कोटड़ा, वरदड़ा, दूधालिया, फिंया, कडिया, मानवतों का गुड़ा, सेवंत्री, उमरवास, उदावड़, पोकरिया, कोटड़ा, दूधालिया व भानपुर नेशनल पार्क के दायरे में आएंगे.

arsingh@chauthiduntya.com

मेरी दुनिया.... सच का सामना

जन लोकपाल की लड़ाई ने भारतीय जनतंत्र के खोखलेपन को जनता के सामने ला दिया है. क्या यह सरकार, यह व्यवस्था और यह संसद कभी जन लोकपाल क़ानून दे सकती है?

अन्ना आंदोलन का अगला चरण

देश को वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है. वैचारिक मंथन करके इन प्रश्नों के समाधान ढूंढने की ज़रूरत है. जिस दिन पूरा देश वैचारिक स्तर पर खड़ा हो गया, इस क्रांति को कोई नहीं रोक पाएगा. क्रांति अहिंसक होगी, लेकिन देश में मूलभूत परिवर्तन करेगी. इसके लिए देशभर में चर्चा समूहों का गठन किया जा रहा है. इनका नाम है–स्वराज चर्चा समूह या अन्ना चर्चा समूह.

अन्ना के नेतृत्व में पूरा देश भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सड़क पर उतरा. एक ही मांग थी, जन लोकपाल बिल भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक सख्त क़ानून बने, ताकि भ्रष्टाचार करने वालों को सज़ा मिले, उनके मन में डर पैदा हो. क्या जनता की मांग नाजायज़ थी?

कई जनमत संग्रह हुए. 95 प्रतिशत से ज़्यादा जनता टीम अन्ना और जनता द्वारा बनाए गए जन लोकपाल बिल के साथ थी. कई टीवी चैनलों ने सर्वे कराए. 80 प्रतिशत से अधिक जनता ने जन लोकपाल बिल का समर्थन किया.

इसके बावजूद सरकार ने एक लूला–लंगड़ा, कमज़ोर और ख़तरनाक लोकपाल बिल संसद में प्रस्तुत किया. लोकसभा में यह पास भी हो गया. जल्द ही राज्यसभा में भी पास हो जाएगा. लालू प्रसाद यादव ने खुलकर कहा, कोई भी सांसद और कोई पार्टी जन लोकपाल बिल नहीं चाहती. इसका मतलब देश की 80 प्रतिशत से अधिक जनता ने एक क़ानून की मांग की और इस देश की संसद वह क़ानून देने में अक्षम रही. उल्टा देश की संसद जनता की इस मांग के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई. तो क्या हम इसे जनतंत्र कहेंगे? इसी संसद में कलमाड़ी, कनिमोई, राजा जैसे अनेक भ्रष्टाचारी सदस्य हैं. इसी संसद के 160 से अधिक सदस्यों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं. सवाल उठता है कि क्या यह संसद इस देश को ग़रीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकती है? या यह संसद ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है?

जन लोकपाल की लड़ाई ने भारतीय जनतंत्र के खोखलेपन को जनता के सामने ला दिया है. क्या यह सरकार, यह व्यवस्था और यह संसद कभी जन लोकपाल क़ानून दे सकती है? चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने. क्या ये भ्रष्टाचारी नेता और पार्टियां कभी भी अपने गले में ख़ुद फांसी का फंदा डालेंगे? जब तक पूरी व्यवस्था को पूर्ण रूप से नहीं बदला जाएगा, क्या तब तक जन लोकपाल क़ानून आ सकता है? क्या अब हमारी व्यवस्था के बारे में कुछ मूलभूत प्रश्न पूछने का समय आ गया है ? जैसे कि क्या आज की न्याय प्रणाली ग़रीबों को न्याय देती है? क्या विधानसभाएं और संसद वाक़ई जनहित में क़ानून बनाती हैं? पुलिस जनता को संरक्षण देती है या अपराधियों को? सीबीआई भ्रष्टाचारियों को सज़ा दिलवाती है या उन्हें संरक्षण देती है? क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि प्रधानमंत्री ने वाक़ई आपके और आपके परिवार की भलाई के लिए काम किया? क्या यह पूरा सिस्टम बुरी तरह से सड़ नहीं गया है?

क्या इन सब प्रश्नों के उत्तर मांगने का समय आ गया है? क्या इस सड़ी–गली व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है? क्या एक नई व्यवस्था की स्थापना का समय आ गया है? देश को वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है. वैचारिक मंथन करके इन प्रश्नों के समाधान ढूंढने की ज़रूरत है. जिस दिन पूरा देश वैचारिक स्तर पर खड़ा हो गया, इस क्रांति को कोई नहीं रोक पाएगा. क्रांति अहिंसक होगी, लेकिन देश में मूलभूत परिवर्तन करेगी. इसके लिए देशभर में चर्चा समूहों का गठन किया जा रहा है. इनका नाम है–स्वराज चर्चा समूह या अन्ना चर्चा समूह. इस समूहों के ज़रिये जनता सामूहिक रूप से ये प्रश्न खड़े करेगी और इनके समाधान ढूंढेगी. यदि आप भी इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऐसे ही चर्चा समूह का गठन कीजिए और अनेक ऐसे समूहों का गठन करने में मदद कीजिए.

चर्चा समूह में आयोजक की भूमिक क्या होगी?

1. कुछ लोगों को एक साथ लेकर चर्चा समूह को शुरू करना एवं सुनिश्चित करना कि लोग हर सप्ताह नियमित रूप से चर्चा समूह में आएं. कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्चा समूह का हिस्सा बनें.
2. हमारी वेबसाइट पर हर हफ्ते एक पर्चा और फिल्म अपलोड की जाएगी, जिसमें आंदोलन और बिल के संबंध में मुद्दे शामिल होंगे. उसे डाउनलोड कर बैठक में लाने की ज़िम्मेदारी आयोजक की होगी.
3. चर्चा समूह में आयोजक या तो ख़ुद या फिर कोई अन्य व्यक्ति पर्चे को पढ़कर सुनाएगा. अगर संभव हो तो फिल्म भी दिखाई जा सकती है. अगर फिल्म दिखाना संभव नहीं है तो आईवीआर नंबर 09212123212 पर डायल करके स्पीकर फोन की सहायता से लोगों को सुनाया जा सकता है और फिर चर्चा शुरू की जा सकती है.
4. आयोजक के लिए आवश्यक नहीं है कि वह कोई अच्छा वक्ता हो या सभी सवालों के जवाब दे. वह सिर्फ़ आंदोलन के नेतृत्व और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा. चर्चा के अंत में जो सवाल रह जाते हैं, वे हमारी हेल्पलाइन 09718500606 पर फोन करके या *Indiaagainstcorruption.2010@gmail.com* ईमेल के माध्यम से उनके जवाब जाने जा सकते हैं. प्राप्त जवाबों पर चर्चा अगली बैठक में की जाएगी.
5. चर्चा के दौरान अगर कोई विचार या सुझाव आता है, तो उसकी जानकारी आंदोलन के नेतृत्व तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी भी आयोजक की होगी. आंदोलन के नेतृत्व से उपर्युक्त हेल्पलाइन या ईमेल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
6. चर्चा समूह का सदस्य बनने के लिए किसी भी प्रकार के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की कोई आवश्यकता नहीं है.
7. आयोजक में किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है. बस देशभक्ति की भावना कूट–कूट कर भरी हो.

अगर आयोजक पर्चे में लिखी हुई बातों से सहमत नहीं है, तो इसका समाधान क्या है?

यह आवश्यक नहीं है कि आयोजक पर्चे में लिखी बातों से सहमत हो. जब चर्चा के दौरान पम्फ्लेट पढ़ा जाएगा और फिल्म दिखाई जाएगी और फिर उस पर लोगों के बीच में चर्चा होगी. तत्पश्चात चर्चा समूह में मौजूद लोगों को अगर यह लगता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं, वह ग़लत है तो इस बात की सूचना आंदोलन के नेतृत्व तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी आयोजक की होगी. चर्चा समूह का मक़सद ही यही है कि हम लोगों के विचार जानें और आंदोलन जनता की इच्छानुसार चलें.

चर्चा समूह

चर्चा समूह क्या है?

कोई भी व्यक्ति अपने कुछ मित्रों, सहकर्मियों, पड़ोसियों आदि के साथ मिलकर चर्चा समूह शुरू कर सकता है. शुरू करने वाला व्यक्ति आयोजक कहा जा सकता है. इन्हें हम स्वराज चर्चा समूह अथवा अन्ना चर्चा समूह भी कह सकते हैं. चर्चा समूह की बैठक हर सप्ताह, निश्चित समय और स्थान पर हो.

चर्चा समूह क्यों?

लोगों के मन में जन लोकपाल और आंदोलन के बारे में कई तरह की शंकाएं और सवाल उठ रहे हैं. स्वार्थी और भ्रष्ट तत्वों द्वारा जानबूझकर फैलाई जा रही अफ़वाहों के कारण कई तरह के भ्रम फैल रहे हैं. इन शंकाओं और सवालों के जवाब अभी तक केवल मीडिया के माध्यम से ही मिल पा रहे थे. कई बार ऐसे जवाब एक तरफ़ा, अधूरे या भ्रामक होते हैं. चर्चा समूह दो तरफ़ा संवाद का माध्यम बनेगा.

यह संवाद दो तरफ़ा कैसे होगा?

हर सप्ताह एक पर्चा और वीडियो तैयार किया जाएगा. इस वेबसाइट पर भी डाला जाएगा. इस पर्चे और वीडियो के माध्यम से सवालों और शंकाओं के जवाब लोगों तक सीधे पहुंचाए जाएंगे. चर्चा समूहों की बैठक में शामिल होने वाले लोग सवाल रखेंगे. चर्चा समूह के आयोजक इन सवालों के जवाब आंदोलन के नेतृत्व से लेकर अगली बैठकों में रखेंगे. इन चर्चा समूहों के माध्यम से लोग अपने सुझाव और विचार भी आंदोलन के नेतृत्व तक पहुंचा सकेंगे.

चर्चा समूह की बैठक कितने समय में होगी?

चर्चा समूहों की सफलता के लिए उचित होगा कि ये बैठकें सप्ताह में एक बार निश्चित समय और स्थान पर हों.

चर्चा समूह शुरू कैसे होगा?

कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक या भावनात्मक रूप से अन्ना के आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वह अपने परिवार के सदस्य, दोस्तों, सहकर्मियों या पड़ोसियों के साथ मिलकर एक चर्चा समूह शुरू कर सकता है.

चर्चा समूह में कितने लोग होने चाहिए?

कोई भी व्यक्ति पांच या अधिक लोगों से चर्चा समूह शुरू कर सकता है और धीरे–धीरे ज़्यादा लोगों को जोड़ सकता है. लेकिन अगर संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक चर्चा समूह को कई चर्चा समूहों में बांटा जा सकता है.

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ चौथी दुनिया की मुहिम

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ चौथी दुनिया की एक और मुहिम. चौथी दुनिया के माध्यम से आप भी अन्ना आंदोलन से जुड़ सकते हैं. अपनी राय, सवाल और सुझाव सीधे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और टीम अन्ना के सामने रख सकते हैं. चौथी दुनिया आपके सवाल और राय को सीधे पहुंचाएगा टीम अन्ना तक और उनके जवाब आप तक. आप हमें पत्र और ईमेल के ज़रिये अपनी बात और अपने सवाल भेज सकते हैं. चौथी दुनिया अख़बार और चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर लगातार हम इस कॉलम और अरविंद केजरीवाल का साक्षत्कार प्रकाशित और प्रसारित करते रहेंगे. आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर 11
नोएडा
उत्तर प्रदेश
पिन:201301
ईमेल: sawal@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया **हम सवाल पूछने की ताक़त देते हैं**

फ़सल बीमा का अग्रिम प्रीमियम वसूल करने वाली बीमा कंपनियां ज़रूरत पड़ने पर दावा राशि का भुगतान करने में भी आनाकानी करती हैं.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

नवीनीकरण का विरोध

नई मशीनरी का परिणाम है कम मज़दूरों से अधिक काम करवा सकना. उससे मज़दूरों की ज़रूरत न रहने से कटौती या छंटनी होती है. जो लोग बेकार होते हैं, वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि नई मशीनरी लगाई जाए. जो काम करते रहें, उन्हें अधिक वेतन दें तथा हमें निकाल बाहर करें. युक्तीकरण का सबसे बड़ा विरोध इसी बुनियाद पर हो रहा है. नवीनीकरण में सबसे बड़ी बाधा इन मज़दूरों की छंटनी है. कहीं-कहीं तो इतने उपद्रव हो जाते हैं कि नई आई हुई मशीनरी लगाई ही नहीं जा सकती या लगा दी जाती है तो श्रमिक लोग उसे तोड़-फोड़ डालते हैं. ये सब क्यों होता है? क्योंकि बेकारी बढ़ने का अंदेशा होता है, श्रम संघ की सदस्यता में कमी आती है. स्वाभाविक ही है, अपनी रोटी की आंच की फिक्र सभी को है. स्वार्थपरता में वे यह सब भूल जाते हैं कि देश की समृद्धि ज़्यादा उत्पादन में ही है. किसी भी प्रकार से ज़्यादा उत्पादन होगा तो सबका ही भला होने वाला है, पर इनमें कोई भी अपनी पूंजीवादी व्यवस्था में ज़रा भी दरार पड़ने की गुंजाइश हो तो इसे सहन नहीं कर सकते. हड़तालों से जो सुविधा या अधिकार श्रमिक संघ श्रमिकों को दिलाते थे, उन्हें थोड़े समय बाद मौक़ा आते ही मालिक लोग तालाबंदियों से निरस्त कर देते थे. इस तरह से श्रमिकों की हालत जैसी की तैसी बनी रहती थी, बल्कि उससे भी कुछ ख़राब हो जाती थी. इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए क़ानून बनने अनिवार्य हुए. श्रम संबंधित क़ानूनों में परिवर्तन हुए. जो भी समझौता श्रमिक संघ और मालिकों के बीच हो, उसका उल्लंघन करना क़ानूनन अपराध बना दिया गया. कोई भी मालिक चाहे कितना ही अप्रसन्न हो तो भी जो समझौता वह श्रमिक संघ के साथ कर लेता है, उसे वह बदल नहीं सकता. ऐसा क़ानून बन गया है.

जिस तरह से श्रमिकों ने अपने संघ बनाकर सामूहिक सौदेबाज़ी को अपनाया, मालिकों ने भी सोचा कि किसी प्रकार का संगठन वे नहीं बनाएंगे तो बढ़ती हुई श्रमिकों की मांगों के सामने वे उद्योग नहीं चला पाएंगे. परिणामत: उन्होंने भी मिलकर मिल मालिक संघ या नियोक्ता संगठन बनाए. श्रमिकों के संघ में अध्यक्ष और सचिव थे, मालिकों के फेडरेशन में भी अध्यक्ष और सचिव नियुक्त हुए. नियम बना दिए गए कि जो भी समझौता हो, उसे सब उद्योगों पर समान रूप से लागू किया जाए. पाश्चात्य देशों की तुलना में हालांकि हमारे श्रमिक संघ इतने भयानक नहीं बन पाए हैं और वहां जैसी परिस्थिति यहां नहीं पैदा हो पाई है कि कोई भी श्रमिक संघ

का सदस्य हुए बिना कहीं भी रोजी कर ही नहीं सके या कोई मालिक बिना संघ की इच्छा या सहायता के किसी भी श्रमिक को नौकर रख ही न सके. फिर भी श्रमिक संघों की पूंजीवादी मनोवृत्ति यहां भी फैल रही है. भारत में महात्मा गांधी ने अपने नेतृत्व में असहयोग एवं सत्याग्रह का आंदोलन चलाकर विदेशी राज्य को उखाड़ने में जो सफलता प्राप्त की, उसे देखकर आज हर छोटे-बड़े कामों में वही सत्याग्रह कर बैठने का भूत सब पर सवार हो गया है. उन्होंने जब यह अमोघ और नूतन अस्त्र प्रजा को दिया था तो उसके पीछे एक नैतिक बल था, आत्मिक श्रद्धा थी. वह सत्याग्रह या अनशन उस वक़्त के लिए उपयोगी समझते थे, जब दूसरा कोई मार्ग शेष न रहे. किसी से जोर-ज़बरदस्ती द्वारा कोई काम करवा लेने के लिए यह हथियार कदापि नहीं था.

दुर्भाग्य से कुछ तथाकथित गांधीवादियों ने समय-असमय, जां-बेजां किसी भी मांग को हासिल करने के लिए इसी अमोघ अस्त्र का उपयोग करना अपना व्यवसाय बना लिया है. उन्हें नहीं मालूम कि गांधी जी के इस अस्त्रोपयोग द्वारा मानसिक भावनाएं बदलना अभीष्ठ था. आज भूख हड़ताल करके अगर आप ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा भी लें तो विपक्षी के दिल पर इसका असर इतना बुरा पड़ता है कि सदियों से चला आ रहा स्नेह धुल-पुंछ जाता है और वैमनस्य का बीजारोपण हो जाता है. भारत में श्रमिक संघ के अधिकारियों ने कई बार ऐसे-ऐसे जघन्य कर्म इस सत्याग्रह की आड़ में किए हैं, जो क़ानून की दृष्टि से सर्वथा अवैध हैं. उनके वे कर्म पाश्चात्य देशों में चली आ रही खुली गुंडागिरी से किसी भी हालत में कम नहीं हैं. श्रमिक संघों के पूंजीवाद का यह नया स्वरूप भारत का अपना है. मानव की कोमल भावनाओं को झकझोर डालना उतना ही ख़तरनाक है, जितना उसे शारीरिक कष्ट पहुंचाना. अगर कोई व्यक्ति आपको छुरा, कटार या पिस्तौल दिखाकर आपसे आपके रुपये छीन लेता है तो वह डाकू है. आप सहर्ष तो उसे कुछ दे नहीं रहे हैं, आप विवश हुए हैं, तभी तो दे रहे हैं. ऐसे जबरन छीन लेने के विरुद्ध क़ानून है और पुलिस आपकी रक्षा करती है. पर अगर वही व्यक्ति आपसे कहे कि आप अपने रुपये मुझे दे दीजिए, वरना मैं आपके द्वार पर बैठा भूखों मरूंगा और जान दे डालूंगा तो चाहे उसकी प्रार्थना कितनी ही अनुचित या अवैधानिक क्यों न हो, हज़ारों आदमी सहानुभूति करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे और आपको कहने लगेंगे कि भाई आप पूरे नहीं तो कुछ रुपये तो दे ही दीजिए, अगर यह व्यक्ति प्राण गंवा बैठा तो?

कुछ ही दिनों में शोरगुल उठने लगेगा कि वह भूख हड़ताली कमज़ोर हो रहा है और मरणासन्न है. समाज के गुंडे लोग उस समय मौक़ा देखकर दंगा शुरू करने से बाज नहीं आते. जो स्पष्ट डाका था, वह जनता की सहानुभूति प्राप्त करके उचित मांग का प्रतीक बन जाता है. अराजकता, भीड़-शासन इसी तरह से तो होता है. कोई आदमी यों ही दौड़ रहा हो, दो-चार आदमी उसके पीछे चोर-चोर चिल्लाते हुए दौड़ने लगें, रास्ते पर चलने वाले उस व्यक्ति को तत्काल पकड़ लेंगे. आप घूंसा-थप्पड़ मारना शुरू कर दीजिए, सब लोग उसे पीटना शुरू कर देंगे. उस वक़्त कोई भी विवेक से यह नहीं पूछेगा कि भाई इसने किसका क्या चुराया है? कोई निर्णय उस समय ज़रूरी नहीं समझा जाएगा. इसी प्रकार के क्षुब्ध वातावरण को भीड़ का राज कहते हैं. श्रमिक संघ का विकास इसी तरह के भीड़ प्रचार से हुआ है और आज उसी प्रचार पर यह जिंदा है. जहां भी मानव ने विवेक या बुद्धि से काम लिया, इन संघों की पोल खुली. आख़िर जिस बुराई को मिटाने के लिए ये संघ बने हैं, वही बुराई अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में ये ख़ुद कर रहे हैं या करने को प्रोत्साहन दे रहे हैं. और कर भी क्या सकते हैं? इन संघों या संगठनों की व्याधि इतनी बढ़ गई है कि आजकल हर बात और काम के लिए संघ खड़े होने लग गए हैं. शासन अथवा सरकार से कोई बात मनवानी है तो संघ से आवेदन पत्र भेजिए. शासन फौरन मान जाएगा अथवा ज़्यादा ध्यान देगा. किसी व्यक्ति की प्रार्थना, चाहे वह कितनी ही उपादेय एवं उचित क्यों न हो, शायद ही सुनी जाए. कारण, शासन भी संघों या संगठनों द्वारा स्थापित हुआ है. बिना संघों की सहायता के, बिना उनके वोटों की मदद के उस पार्टी की सरकार बन ही नहीं सकती थी. अतएव जिन-जिन संघों ने उन्हें सहायता दी है, उन तमाम संघों की प्रार्थनाओं को विशेष पक्षपात से देखना सरकार का सुनिश्चित कर्तव्य सा हो गया है.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

फ़सल बीमा योजना किसानों के साथ छलावा है

जाहिद खान

हमारे मुल्क में किसानों की हालत सुधारने या उन्हें राहत देने के मक़सद से सरकारी स्तर पर कई पहल हुई हैं. एक दशक पहले शुरू हुई राष्ट्रीय फ़सल बीमा योजना ऐसी ही एक पहल है. इस योजना का सीधा-सीधा मक़सद फ़सल नष्ट होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति करना और किसान को मदद पहुंचाना है. अपने घोषित मक़सद की वजह से ज़ाहिर है कि यह योजना काफी लोकलुभावनी दिखाई देती है, लेकिन हक़ीक़त इसके उलट है. बीमा कंपनियों ने बड़ी चालाकी से इसकी ऐसी शर्तें तय की हैं कि हर्जाने का दावा मान्य होने पर कंपनियों को बहुत मामूली भुगतान करना पड़े. मुआवज़ा भी तब मिलता है, जब तालुका या प्रखंड स्तर पर फ़सल बर्बाद हुई हो. इससे कम क्षेत्र में नुक़सान होने पर भरपाई नहीं की जाती. इतना सब कुछ पक्ष में होने के बाद भी कंपनियों की नीयत किसानों को फ़ायदा देने की नहीं है. फ़सल बीमा का अग्रिम प्रीमियम वसूल करने वाली बीमा कंपनियां ज़रूरत पड़ने पर दावा राशि का भुगतान करने में भी आनाकानी करती हैं. बीमा कंपनियों की इन धांधलियों का मामला हाल में मध्य प्रदेश विधानसभा में उठा. विधायकों ने सरकार से मांग की कि किसानों को बीमा कंपनियों से फ़सल बीमा योजना का फ़ायदा दिलाया जाए.

ग़ौरतलब है कि किसानों से जुड़े इस अहम मसले को विपक्ष ने नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने उठाया. विधायकों का कहना था कि सूबे के कई ज़िलों में सोयाबीन की फ़सल बर्बाद हो गई, मगर प्रभावित किसानों को बीमा कंपनियों ने अभी तक क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया. सर्वे हो जाने के बाद भी उक्त कंपनियां किसानों को दावा राशि का भुगतान करने में आनाकानी कर रही हैं, जिसके चलते किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं. यदि समय रहते दावा राशि का भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे. विडंबना यह है कि एक तरफ़ किसानों को फ़सल बीमा का फ़ायदा नहीं मिला, वहीं बैंक अधिकारी क़र्ज़ वसूली के लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं. किसानों पर दंड एवं ब्याज लगाया जा रहा है, कुर्की की जा रही है. यदि सरकार ने जल्द कोई क़दम नहीं उठाया तो किसानों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी. मध्य प्रदेश

में होने वाली ख़रीफ़ की फ़सलों में सोयाबीन एक प्रमुख फ़सल है. कई ज़िलों में सोयाबीन की फ़सल बहुतायत में होती है. बीते साल हुई लगातार बारिश ने सोयाबीन की फ़सल में पहले पीला मोजेक रोग और बाद में तंबाकू इल्ली लगने से काफी नुक़सान हुआ. ख़ास तौर पर होशंगाबाद और हरदा ज़िले में सोयाबीन की पूरी फ़सल बर्बाद हो गई. कहने को यहां फ़सल बीमा था और किसानों ने बीमे का अग्रिम प्रीमियम भी भरा, लेकिन बीमा कंपनियों ने अभी तक इन बीमा दावों को मंजूर नहीं किया. न सिर्फ़ क्षतिपूर्ति भुगतान करने में आनाकानी की जा रही है, बल्कि जहां-जहां भुगतान किया गया, उसमें भी धांधली है. बीमा कंपनियां फ़सल बीमा योजना की आड़ में किस तरह गोरखधंधा करती हैं, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है. फ़सल बीमा योजना के तहत होशंगाबाद ज़िले में 49 हज़ार 175 किसानों से बीमा प्रीमियम काटा गया. कुल बीमित राशि 222 करोड़ रुपये की थी, जिसके लिए दो निजी कंपनियों को दस फ़ीसदी यानी 22 करोड़ 22 लाख रुपये का प्रीमियम मिला, लेकिन जब फ़सल ख़राब हो गई तो कंपनियों ने 222 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 17 करोड़ 15 लाख रुपये के क्षतिपूर्ति भुगतान का हिसाब लगाया यानी प्रीमियम राशि में से भी 5 करोड़ 5 लाख रुपये बचा लिए गए. बीते रबी सीजन में भी बीमा कंपनियों ने गेहूं की फ़सल के लिए किसानों से 15 करोड़ 73 लाख रुपये का प्रीमियम लिया, लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो उन्हें सिर्फ़ 85 लाख रुपये देकर चलता कर दिया.

फ़सल बीमा योजना की सबसे बड़ी गड़बड़ी योजना का स्वैच्छिक और अनिवार्य होना है. जो भी किसान बैंक या सहकारी संस्था से ऋण लेता है, बैंक उससे बिना पूछे अनिवार्य रूप से प्रीमियम काट लेता है. उसे कोई जानकारी, रसीद या पॉलिसी पेपर नहीं दिया जाता, जिसके चलते किसान को मालूम नहीं चलता कि उसकी फ़सल का बीमा हुआ भी है या नहीं. मौसम आधारित फ़सल बीमा योजनाएं हमारे यहां पश्चिमी देशों से आई हैं. इसके पीछे विश्व बैंक की सिफारिशें एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा दबाव था. पश्चिमी देशों और हमारे यहां की परिस्थितियों में बुनियादी फ़र्क़ है. यूरोपीय देशों में जहां सैकड़ों-हज़ारों एकड़ ज़मीन के किसान और कंपनियां बहुतायत में हैं, वहीं हमारे यहां छोटे-छोटे काश्तकार हैं. वहां के किसान संतुष्ट होकर स्वेच्छा से अपनी फ़सल का बीमा कराते हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने यह बीमा ज़बरदस्ती किसानों पर थोपा है. किसान चाहे न चाहे, उसे बीमा कराना पड़ेगा. हमारे यहां सभी फ़सल बीमा योजनाएं सरकार के अनुदान और सहयोग से क्रियान्वित हो रही हैं. इसके बाद भी तस्वीर यह है कि पैसा किसान एवं सरकार का, मुनाफ़ा कंपनियों का, नुक़सान सिर्फ़ और सिर्फ़ किसान का. तमाम सरकारी दावों और वायदों के बाद भी फ़सल बीमा योजना किसानों के लिए सिर्फ़ एक छलावा साबित हुई है. किसानों की आत्महत्याएं फ़सल बीमा योजना की नाकामी को उजागर करती हैं. राष्ट्रीय बीमा योजना अमल में आए एक दशक से ज़्यादा हो गया, लेकिन किसानों की आत्महत्याओं में कोई कमी नहीं आई. सरकार इस योजना की पुनर्समीक्षा करे, गड़बड़ियों को दुरुस्त करे, तभी किसानों को फ़सल बीमा योजना का फ़ायदा मिल पाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

कठोर दंड की ज़रूरत

देश में महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. राजधानी दिल्ली को ले लीजिए. आएदिन दिल्ली के किसी न किसी इलाक़े से महिलाओं से दुष्कर्म की कोई न कोई वारदात सामने आ जाती है. अन्य राज्यों का भी यही हाल है. बेहद अफ़सोस की बात है कि इतने संगीन मामले होने के बावजूद पुलिस कोई सख्त क़दम नहीं उठा रही है. अपराधी बेख़ौफ़ घूमते रहते हैं. जब तक इस तरह के अपराधों के लिए कठोर दंड नहीं होगा और आरोपी के ख़िलाफ़ त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाना आसान नहीं है.

-बलजीत, *नई दिल्ली.*

यह कैसा समाजवाद है

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख अखिलेश-शिवपाल में ठनी रार पढ़ा. लगा कि क्या इसी के लिए राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव आदि चिंतकों ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया था. आज कोई यह नहीं बता सकता कि डॉ. राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान सांसद डॉ. रघुवंश प्रताप सिंह के बच्चे, भतीजे एवं भाई का क्या नाम है या वे लोग क्या करते हैं? समाजवाद का चोग़ा पहने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव एवं रामविलास पासवान का पूरा परिवार सांसद एवं विधायक बनने के लिए तैयार है. क्या यही है लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद?

-**सुशील प्रताप सिंह,** *जहानाबाद, बिहार.*

जनता क्या करे

चुनाव में जनता अपने क़ीमती समय का उपयोग कर एक नेता को अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही नेता जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं करता. ऐसे में हर बार जनता को निराशा का सामना करना पड़ता है. हर बार जनता इसी तरह ठगी जाती है. शायद यही उसकी नियति है. उसे अपने प्रतिनिधि से सिर्फ़ आश्वासन और वादे ही मिलते हैं. ऐसी स्थिति में जनता क्या करे, वह कहां से अपना हितैषी प्रतिनिधि लाए.

-**रंजन कुमार सिंह राजपूत,** *पटना, बिहार.*

मानव धर्म आधारित संगठन बने

आज हर जगह धर्म और जाति के नाम पर संगठनों का बोलबाला है. कुछ लोग अपने धर्म के नाम पर संगठन बनाते हैं तो कुछ जाति के आधार पर संगठन बना लेते हैं. ऐसे में मानव धर्म गौण हो जाता है. आज के दौर में ऐसे संगठनों की ज़रूरत है, जो धर्म और जाति से परे हटकर मानव हित के लिए कार्य करें. चौथी दुनिया के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मानव धर्म पर आधारित संगठन बनाएं और जनहित में कार्य करें.

-**महेंद्र गोयल,** *फतेहाबाद, हरियाणा.*

प्रसार भारती ध्यान दे

आकाशवाणी दिल्ली से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जैसे पैग़ाम आपके-गीत हमारे, आप और हम, हैलो सरगम, हैलो ज़िंदगी, आपके नाम आदि. देश के विभिन्न प्रांतों के लाखों लोग इन्हें सुनते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों से जुड़े टेलीफोन अक्सर ख़राब हो जाते हैं, जिससे श्रोताओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. प्रसार भारती से अनुरोध है कि वह इस समस्या के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करे.

-**अख्तर हुसैन राजा,** *सीतामढ़ी, बिहार.*

शान या कुछ और

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है. मंत्रियों को उनके विभाग मिल चुके हैं. अब वे शान से अपने क़ाफ़िले के साथ निकल रहे हैं. इस दौरान उनके समर्थक हवा में गोलियां चलाकर उनका कथित मान बढ़ा रहे हैं. क्या ऐसा करना उचित है? हालांकि पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि इस तरह गोलियां चलाने या चलवाने वाले मंत्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.

-**आफ़ताब,** *दिल्ली.*

अंत में

कभी उसको नज़रअंदाज़ न करो
जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो
वरना किसी दिन तुम्हें अहसास होगा
कि पत्थर जमा करते-करते
तुमने हीरा गंवा दिया.

-रवि

राजकमल प्रकाशन समूह

1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274

लेखन विधा सम्मान 2011

'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपए की किताबें

मूल्य ₹ 1000 पृ. : 448
राजकमल प्रकाशन प्रा.लि.

देश के जाने-माने पत्रकार एवं 'चौथी दुनिया' के सम्पादक संतोष भारतीय के संपादन में प्रकाशित 'दलित अल्पसंख्यक सशक्तीकरण' के वैश्विक प्रयासों का तथ्यात्मक दस्तावेज। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि दुनिया भर के गरीब, दबे-कुचले और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग समूहबद्ध होकर यदि शक्तिसम्पन्न होने का संकल्प लें तो वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आएँगे।

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

पिछले एक साल से महंगाई दर लगातार दोहरे अंक के आसपास रही है और अभी भी यह 7 प्रतिशत के क़रीब है. इसी तरह बजट घाटा घटाकर 4.6 प्रतिशत करना था, लेकिन यह 5.9 प्रतिशत रहा.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

हम अपनी बात पर क़ायम हैं

कोयले की कहानी कोयले की तरह और काली होती जा रही है. जब चौथी दुनिया ने 25 अप्रैल–1 मई 2011 के अंक में 26 लाख करोड़ का महाघोटाला शीर्षक से कहानी छापी तो हमें लगा कि हमने एक कर्तव्य पूरा किया, क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों, सरकार बनाने वाले प्रतिनिधियों ने हिंदुस्तान के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा कुछ लोगों की जेब में डाल दिया और उसमें से कुछ पैसा उनकी जेब में भी गया. हमें लगा कि हिंदुस्तान की यह कहानी लोकसभा के सदस्यों की आंख खोलने में मदद करेगी, पर हमें क्या पता था कि यह कहानी तो क्या, इस जैसी कई कहानियां भी लोकसभा के सदस्यों की आंख नहीं खोल सकतीं. हमने पत्रकारिता के सिद्धांतों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिया, क्योंकि पत्रकारिता यह नहीं कहती कि आप स्टोरी छापें और उसके बाद यह अपेक्षा करें कि उसके ऊपर लोकसभा में चर्चा होगी, पर हमें लगा कि यह देश का ऐसा मामला है, जो लोगों के सामने आना चाहिए. जब हमारे कई साथियों ने कहा कि हम कुछ वरिष्ठ सांसदों को और बड़ी पार्टियों को इस स्टोरी की कॉपी दे दें, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया. वे गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और कुछ छोटी पार्टियों के सांसदों को कॉपियां दीं, लेकिन इस कहानी से उन नेताओं की आंख नहीं खुली. फिर हमने यह अख़बार छह सौ सांसदों के घर डलवाया. तब भी सांसदों की आंख नहीं खुली और उन्हें लगा कि यह स्टोरी ऐसी नहीं, जिसे उठाया जा सके. हालांकि हमने इस स्टोरी में विस्तार के साथ कि कैसे 26 लाख करोड़ की लूट हुई, उसे सरकारी आंकड़ों और सरकारी काग़ज़ों के सहारे सार्वजनिक किया. हमारी इंवेस्टिगेशन ने हमें बताया कि हमारे आंकड़े सही हैं, तभी हमने यह स्टोरी सारे सांसदों को भेजी. अगर हम ग़लत होते तो जिन कंपनियों के नाम हमने प्रथम पृष्ठ पर छापे थे, वे हमें अब तक अदालत में खड़ा कर चुकी होतीं.

हमारे पास फोन आए, लेकिन वे फोन हमें बरगलाने, हमें ख़रीदने या हमें धमकाने के लिए थे. हमने माना कि जब हम पत्रकारिता के इस पवित्र पेशे में हैं तो यह इसकी क़ीमत है और इस क़ीमत को हमें देना चाहिए, इसलिए हम घबराए नहीं. लेकिन जब 22 मार्च की सुबह दिल्ली के अंग्रेजी अख़बार टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह ख़बर छापी कि साढ़े दस लाख करोड़ का कोयला घोटाला हुआ है और सीएजी इस तरह की रिपोर्ट देने वाली है तो इसे दिखाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ. एक बार राज्यसभा स्थगित भी हुई, लेकिन कोई सांसद इस सवाल के ऊपर गंभीर नहीं था और एक रहस्यमय डेवलपमेंट यह हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय के नए मीडिया सलाहकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ़ से फोन कर सीएजी की रिपोर्ट जाननी चाही तो सीएजी ने कहा कि हमें बहुत दु:ख है कि हमारे यहां से यह ख़बर लीक हुई, पर हमने अभी कोई रिपोर्ट फाइनली बनाई नहीं है, अभी शुरुआती दौर में है. चिट्ठी का यह अंदाज़ बताता है कि रिपोर्ट लिखी जा रही है और सीएजी कैलकुलेशन कर रही है, जिसमें एक कैलकुलेशन साढ़े दस लाख करोड़ का है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सारे मीडिया चैनलों को यह बता दिया कि रिपोर्ट अभी आई नहीं है और जब रिपोर्ट नहीं आई है तो सफाई क्या देनी. साथ ही उसने यह कह दिया कि साढ़े दस लाख करोड़ जैसी कोई बात नहीं है. प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी जगह बिल्कुल सही है. उसे यही सब करना चाहिए. लेकिन हम आपको बताएं कि सीएजी के कैलकुलेशन करने का तरीक़ा भी हमें समझ में नहीं आया. हमने चौथी दुनिया की स्टोरी में सरकार के आंकड़े रखें, जो 26 लाख करोड़ होते हैं. सीएजी ने इस पत्र में एक चीज़ और लिखी कि उसने उस रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट कोल मिनिस्ट्री को देखने के लिए भेजा. कोयला मंत्री ने 22 तारीख को कहा, उन्हें कुछ नहीं पता कि इसमें क्या हो रहा है. सीएजी कह रही है कि उसने कोल मिनिस्ट्री को ड्राफ्ट भेजा. इसका मतलब है कि यह ड्राफ्ट सीएजी के दफ्तर से नहीं, कोयला मंत्रालय से लीक हुआ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता को जब यह ड्राफ्ट मिला तो उसने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए इसे छाप दिया.

हम क़ानूनी तर्क ले सकते हैं, हम नैतिक तर्क ले सकते हैं, लेकिन देश का एक तर्क, जो हम भूल रहे हैं, वह यह है कि अगर हम किसी सड़ांध को देखते हैं और उस सड़ांध को बाहर न लाएं, तो फिर हम पत्रकारिता क्यों करें. टाइम्स ऑफ इंडिया ने शायद उस रिपोर्ट को जो कोल मिनिस्ट्री में गई और कोल मिनिस्ट्री को जितना पता था, उसे लेकर छाप दिया. हमारा यह कहना है कि जब यह रिपोर्ट आएगी तो 26 लाख करोड़ के घोटाले से ज़्यादा की फिगर बताएगी, क्योंकि हमें पता है कि सीएजी ऐसी संस्था है, जो सारे पहलुओं को काफ़ी बारीकी से देखती है, लेकिन हो सकता है कि सीएजी भी सरकारी इंफ्लूएंस में आ जाए.

हम क़ानूनी तर्क ले सकते हैं, हम नैतिक तर्क ले सकते हैं, लेकिन देश का एक तर्क, जो हम भूल रहे हैं, वह यह है कि अगर हम किसी सड़ांध को देखते हैं और उस सड़ांध को बाहर न लाएं, तो फिर हम पत्रकारिता क्यों करें. टाइम्स ऑफ इंडिया ने शायद उस रिपोर्ट को जो कोल मिनिस्ट्री में गई और कोल मिनिस्ट्री को जितना पता था, उसे लेकर छाप दिया. हमारा यह कहना है कि जब यह रिपोर्ट आएगी तो 26 लाख करोड़ के घोटाले से ज़्यादा की फिगर बताएगी, क्योंकि हमें पता है कि सीएजी ऐसी संस्था है, जो सारे पहलुओं को काफ़ी बारीकी से देखती है, लेकिन हो सकता है कि सीएजी भी सरकारी इंफ्लूएंस में आ जाए. पिछले दिनों हमने देखा कि हमारे कई संवैधानिक संस्थान सरकार द्वारा दिए गए तर्कों से काफ़ी जल्दी सहमत नज़र आए. कुछ ने तो फ़ैसला देने में भी बाज़ीगरी की और देश के लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब लगीं. संवैधानिक संस्थाओं का यह फ़र्ज़ है कि वे दोनों पक्षों की बात सुनकर अपना फ़ैसला दे. कोई संवैधानिक संस्था अगर फ़ैसला नहीं देती या चीज़ों को तोड़ती–मरोड़ती है या गोलमोल करती है तो वह भारत के संविधान का अपमान करती है, जो उसे संवैधानिक संस्था का स्वरूप देता है. हो सकता है कि भारत सरकार के तर्कों से सीएजी थोड़ी–बहुत सहमत दिखाई दे, पर सरकार के तर्क इतने खोखले और थोथे हैं कि हमें विश्वास नहीं होता कि सीएजी उससे सहमत होगी. हम अपनी स्टोरी पर क़ायम हैं. हम अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहते हैं कि आप एक दिन तो बहुत उत्साह में रहे और आपने स्टोरी चलाई. जब सीएजी की चिट्ठी का अधूरा हिस्सा आपके पास आया, आपको बहाना मिल गया और आपने पूरी स्टोरी को बाइंडअप कर दिया. दूसरी जिस बात का अफ़सोस होता है, वे हैं देश के विपक्षी दल. उन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर न नौ महीने पहले हंगामा मचाया और न अब. तर्कपूर्ण ढंग से तो हंगामा बिल्कुल नहीं मचाया, एक औपचारिकता हुई है.

क्या हम यह मानें कि 26 लाख करोड़ की लूट में शामिल कंपनियों ने हमारे विपक्षी दलों की अंतर्रात्मा पर भी क़ब्ज़ा कर लिया है, क्या उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कुछ वायदे किए गए हैं? हम बड़े दु:ख से यह सवाल पूछ रहे हैं. दु:ख से इसलिए, क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता कि भारत के संविधान की शपथ लेकर संसद में जाने वाले लोग, विपक्ष और सरकारी पक्ष में बैठने वाले लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं. पर हिस्सा तो बने ही, क्योंकि घटनाएं यही बताती हैं, उनकी ख़ामोशी यही बताती है, जांच न होने देने की स्ट्रेटजी यही बताती है. होना तो यह चाहिए कि जब कोई इतना बड़ा मामला आए और कोई ज़िम्मेदार पक्ष आरोप लगाए तो भले ही उसमें कोई दम सरकार को नज़र आए या नहीं, लेकिन सरकार का फ़र्ज़ है कि उसकी जांच कराए और लोगों के सामने अपनी छवि साफ करे. सरकार के ऊपर आरोप कितने लगते हैं, ज़िम्मेदार लोगों के, सांसदों के, अख़बारों के आरोप कम लगते हैं. जब आरोप लगते हैं तो उनका निराकरण या उनकी सफाई का काम देश के लोगों के सामने होना चाहिए. एक काग़ज़ पर अगर पांच मिनट में 26 लाख करोड़ को संख्या में लिख सकते हैं तो मैं मानूंगा कि आप सही गणितज्ञ हैं और भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं. अगर आप पांच मिनट में 26 लाख करोड़ को संख्या में नहीं लिख पाए तो मान लीजिए कि आप भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते, बल्कि भ्रष्टाचार ही आपके ऊपर राज करता रहेगा. हम इस देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोई सुने या न सुने, हम आपके पक्ष में वे सारी चीज़ें रखते रहेंगे, जिन्हें रखना भारत में लोकतंत्र क़ायम रखने के लिए ज़रूरी है. हम यह भी वायदा करते हैं कि न हम प्रलोभन में आएंगे, न धमकी में आएंगे और न अपने कर्तव्य को अनदेखा करेंगे. इसलिए, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए आप सर्वोपरि हैं और आपके लिए हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

बजट किसके लिए है

ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री सराह बेमहर्ड जब डिक्शनरी भी पढ़ती थीं तो लोगों की आंखों में आंसू ला देती थीं. प्रणव मुखर्जी भी इसके काफ़ी क़रीब नज़र आए, जब उन्होंने सर्विस टैक्स के लिए नकारात्मक सूची वाले क्षेत्रों को पढ़ना शुरू किया. वित्त मंत्री को यह नकारात्मक सूची क्यों पढ़नी चाहिए, यह एक रहस्य है. कहा जा सकता है कि यह समय गुज़ारने का एक तरीक़ा था, क्योंकि आगे का बजटीय भाषण भी इससे ज़्यादा रुचिकर नहीं था. यदि वह ज़्यादा रुचिकर होता तो वित्त मंत्री नकारात्मक सूची पर इतना समय न देते. बजट को न्यायसंगत साबित करने के लिए इस छोटे मुद्दे को बड़ा करके दिखाना ज़रूरी हो गया था. पिछले साल कहा गया था कि अगले साल विकास दर 8.5 प्रतिशत होगी, लेकिन वास्तव में यह 6.9 प्रतिशत रही. पिछले एक साल से महंगाई दर लगातार दोहरे अंक के आसपास रही है और अभी भी यह 7 प्रतिशत के क़रीब है. इसी तरह बजट घाटा घटाकर 4.6 प्रतिशत करना था, लेकिन यह 5.9 प्रतिशत रहा. 2012–13 के लिए यह 5.1 प्रतिशत तय किया गया है, जबकि बजट इस बात का विश्वास नहीं दिलाता है कि इस स्तर की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष किया जाएगा. इसका कारण साफ है कि सरकार इस बात के लिए अधिक चिंतित है कि उसके सहयोगी दल कहीं नाराज़ न हो जाएं.

आम बजट से दो दिन पहले रेल बजट पेश किया गया. इस बजट में यात्री किराए में वृद्धि की गई. दस वर्षों के बाद यात्री किराए में वृद्धि की गई है. रेल मंत्री के इस फ़ैसले ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को दु:खी कर दिया, जो रेल मंत्रालय को अपनी जागीर समझती हैं. उनके चुने हुए रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने रेलवे को घाटे से उबारा है. ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए ख़तरा मोल ले लिया. तृणमूल कांग्रेस का उत्तर साफ था. टीएमसी यात्री किराया कम करने के लिए यूपीए सरकार पर दबाव डाल रही है. दिनेश त्रिवेदी का हश्र आपके सामने है. रणनीति सफल हो सकती है. हो सकता है, यूपीए–2 सरकार मई 2014 तक किसी तरह बची रहे, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस नीति से सरकार जीडीपी विकास दर को सात प्रतिशत के स्तर पर भी बनाए रख पाए, ऐसा मुश्किल है. इससे ज़्यादा होने की उम्मीद करना बेमानी होगा. सरकार का अनुमान 7.6 प्रतिशत का है, जिसमें 0.25 प्रतिशत अधिक या कम हो सकता है. सरकार महंगाई पर क़ाबू पाने के लिए भी कोई कारगर नीति नहीं बना पा रही है. घाटे के इस स्तर के बाद कोई कारण नहीं है कि आरबीआई को अपनी ब्याज़ दर क्यों घटानी चाहिए.

देश में जिस बात पर बहस की ज़रूरत है, वह है विभिन्न क्षेत्रों को दी जा रही सब्सिडी. इसकी ज़रूरत है या नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन बजट में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सभी दलों का इस पर एक ही रवैया होता है. वे इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. अगर भारत को खाद्य सुरक्षा योजना सफल बनानी है तो सबसे पहले उसे उर्वरक और डीजल पर सब्सिडी समाप्त करनी होगी. इसके अलावा कर छूट पर भी बहस होनी चाहिए. ग़रीबों पर बोझ बढ़ाकर अमीरों को कर छूट देना किसी तरह न्यायसंगत नहीं है. उदार आर्थिक सुधार पैकेज प्रगतिशील एवं समावेशी हो सकता है और होना भी चाहिए. इस पर कड़ा क़दम उठाना चाहिए, न कि लोकप्रिय फ़ैसले लेने चाहिए. भारतीय राजनीतिक दल लोकप्रिय फ़ैसले लेते हैं, जबकि राष्ट्र हित में हमेशा लोकप्रिय नहीं, बल्कि सही और कड़वे फ़ैसले भी लेने पड़ते हैं. भारत में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, जो ऐसी आर्थिक नीति बना सके, जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके. जब लोकसभा में कुछ योजनाओं के ख़र्च में बढ़ोत्तरी की गई तो सभी सांसदों ने मेज़ें थपथपा कर इसका स्वागत किया.

सभी राजनीतिक दल और नेता यह दावा करना चाहते हैं कि वे अपने मतदाताओं को मुफ्त में भोजन दे सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं कि आम जनता वास्तविक दुनिया में रहती है, न कि उनकी तरह लुटियंस के बंगले में. वह जानती है कि उसे कुछ भी ख़रीदने के लिए बढ़ती दरों का सामना करना पड़ता है. भारतीय राजनीतिक दल लोगों

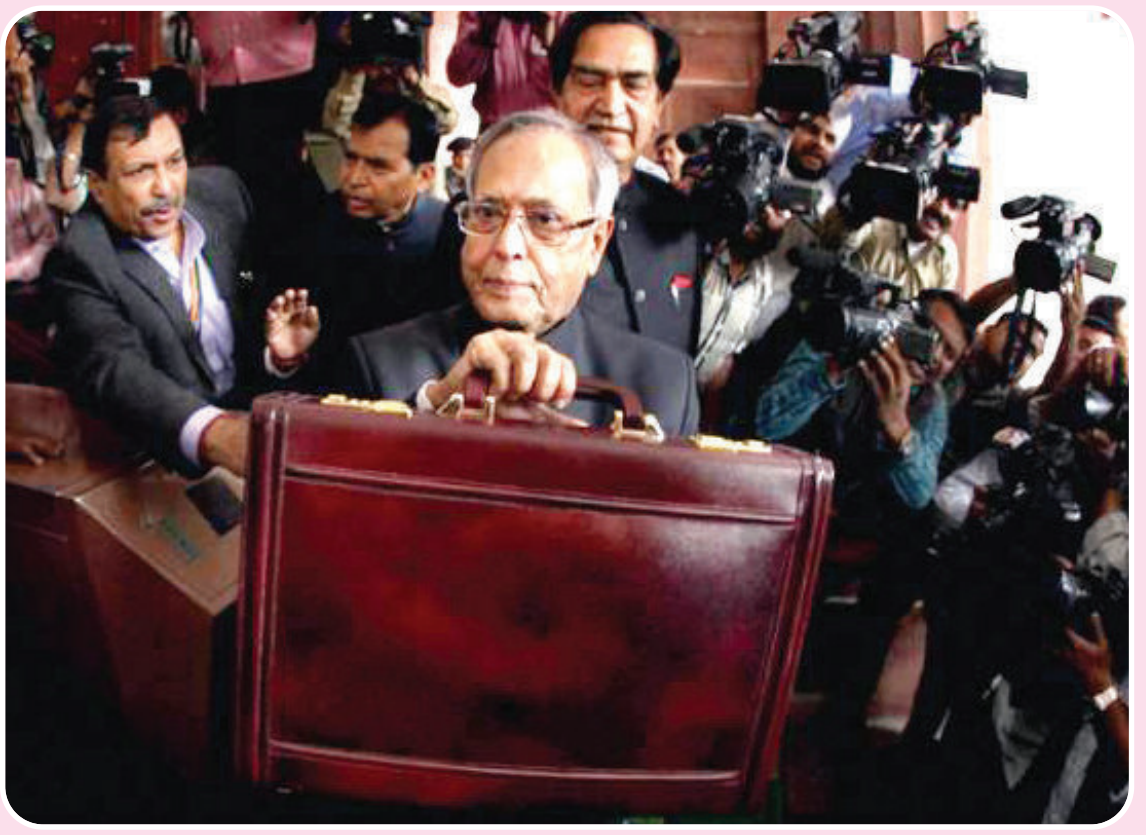

के साथ छल करते हैं. उन्हें पता है कि रेल भाड़ा कम करके लोगों को ख़ुश किया जा सकता है, जबकि कई छुपे हुए कर लगाकर उनकी जेब से पैसा खींचा जा सकता है जिसका सामान्य लोगों को पता भी नहीं चलता. नेताओं को अपने आपको अर्थव्यवस्था की सच्चाई से रूबरू कराना होगा, ताकि उनके मतदाताओं को जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, वे सस्ती एवं ख़रीदने योग्य हो सकें. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत कल्याणकारी राज्य के दायित्वों का निर्वहन तभी कर सकता है, जबकि देश की विकास दर उच्च हो, सब्सिडी कम हो और कम से कम छूट के साथ एक प्रगतिशील कर प्रणाली हो. यूपीए–2 सरकार ने ऐसा नहीं किया है. क्या यूपीए या एनडीए की अगली गठबंधन सरकार ऐसा कर पाएगी? अब इंतज़ार है, अगली गठबंधन सरकार और उसकी नीतियों का.

feedback@chauthiduniya.com

जापान में बनी स्पीच जैमर नामक यह मशीन अत्यधिक बोलने वाले को एकदम से ख़ामोश कर सकती है. इस मशीन में माइक्रोफोन और स्पीकर लगा हुआ है.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 02 अप्रैल–08 अप्रैल 2012

सूचना का अधिकार
जागते का अधिकार जीते का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सांसद निधि के पैसों का क्या हुआ

विकास कार्य के लिए आपके सांसद को हर साल करोड़ों रुपये मिलते हैं, जिसे सांसद स्थानीय विकास फंड कहा जाता है. इस फंड से आपके क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य किए जाने की व्यवस्था होती है. क्या कभी आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद निधि से हुए विकास कार्यों के बारे में जानने की कोशिश की? क्या आपने कभी यह सवाल पूछा कि आपके इलाक़े में सांसद फंड से कितना काम हुआ है? आप उस वक्त को याद कीजिए, जब कोई नेता आपसे वोट मांगने आता है और कहता है कि आप उसे वोट दें, ताकि वह अगले पांच सालों तक आपकी सेवा करता रहे यानी इस हिसाब से देखें तो जनता मालिक और नेता सेवक. लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है? क्या आपको पता चलता है कि आपके सांसद को क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार की ओर से जो करोड़ों रुपये मिलते हैं, वे कहां जाते हैं? आपके क्षेत्र के विकास में सांसद निधि का कितना इस्तेमाल हुआ? कहीं सांसद के चहेतों के बीच उस फंड का बंदरबांट तो नहीं हो गया अथवा फिर ठेकेदार और नेता जी मिलकर उस फंड को हजम तो नहीं कर गए? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे, लेकिन आप ये सवाल अपने सांसद से नहीं पूछते. वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल न पूछकर आप एक तरह से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देते हैं. ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप सवाल पूछें, ताकि व्यवस्था और आपके सांसद पर दबाव बन सके. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि बिना कोई काम किए या आधा-अधूरा काम करके अब तक जो पैसा भ्रष्ट लोगों की जेब में चला जाता था, वह आपके क्षेत्र के विकास में काम आएगा. ऐसा नहीं है कि एक आवेदन देने भर से परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपका अकेला आवेदन भी उन भ्रष्ट लोगों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए काफी होगा कि जनता अपने सेवकों पर लगाम लगाना जानती है. यदि आप सचमुच परिवर्तन चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को ऐसे आवेदन डालने के लिए प्रेरित करें. ज़ाहिर है, जब ज़्यादा संख्या में लोग सवाल पूछेंगे तो उससे बनने वाले दबाव का असर भी उतना ही ज़्यादा होगा. चौथी दुनिया हर क़दम पर आपके साथ है. किसी भी समस्या या सुझाव के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. इस अंक में सांसद निधि से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप
(सांसद विकास निधि का विवरण)

सेवा में
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

दिनांक.....

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन
महोदय,
कृपया.....विधानसभा/संसदीय क्षेत्र की विधायक/सांसद विकास निधि के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-
1.....से.....के दौरान उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के विधायक/सांसद की विकास निधि से कराए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें:-
कार्य का नाम.....
कार्य का संक्षिप्त विवरण.....
कार्य के लिए स्वीकृत राशि.....
कार्य स्वीकृत होने की तिथि.....
कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति.....
कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम.....
कार्य शुरू होने की तिथि.....
कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया.....
कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है.....
कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति.....
2. इस कार्य को कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित निर्णयों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.
3. उपरोक्त प्रतिनिधि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कितनी राशि आवंटित हुई है और पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी राशि शेष रही?
4. उपरोक्त कार्यों में से अब तक कितने कार्यों के लिए और कुल कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है?
5. उपरोक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों के लिए और कितनी राशि स्वीकृत होनी है?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....
संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

ज़ुबान को लगेगा ताला

आजकल लोग अपनी इतनी हांकते हैं कि चुप ही नहीं होते. उनकी ज़ुबान पर विराम चिन्ह लगाना बड़ा मुश्किल होता है. हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जिनकी फिजूल की बातों में सामने वाले को भले ही रुचि न हो, लेकिन उनकी बकबक चालू रहती है. अब ऐसे लोगों की ज़ुबान पर ताला लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मशीन तैयार की है. जापान में बनी स्पीच जैमर नामक यह मशीन अत्यधिक बोलने वाले को एकदम से ख़ामोश कर सकती है. इस मशीन में माइक्रोफोन और स्पीकर लगा हुआ है. माइक्रोफोन बोलने वाले की आवाज़ को रिकॉर्ड कर स्पीकर को भेज देता है और 0.2 सेकंड की देरी के बाद दोबारा सुनाता है. जब वक्ता को अपने ही शब्द तक़रीबन एक सेकंड बाद सुनाई देते हैं तो वह बात करने में अक्षम हो जाता है. इस तरह बकबकी लोगों से सामने वालों को छुटकारा मिल जाता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

वाद्य यंत्र बनाने का नया तरीक़ा

हम लोगों को लगता है कि सब्जियां केवल खाने के लिए होती हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि सब्जियों का खाने के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बीजिंग शहर के दो भाइयों ने इस तरह का कारनामा कर दिखाया है. उन्होंने आलू-गाजर जैसी सब्जियों के इस्तेमाल से एक ऐसा वाद्य यंत्र बनाया है, जिसे बजाया जा सकता है. लोगों को इस यंत्र की आवाज़ बेहद पसंद आ रही है. इसकी मोहक आवाज़ सुनने के लिए रोज इन भाइयों के घर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है. इन्हें जनता की फरमाइश पर रोज एक-दो घंटे इस यंत्र को बजाकर सुनाना पड़ता है.

कबाड़ बना जुगाड़

इस तकनीकी दुनिया में कोई भी चमत्कार कर सकता है, लेकिन एक किसान केवल खेती से जुड़ा रहता है. ग़रीबी के कारण वह पढ़-लिख नहीं सकता. किसान का नाम सुनते ही खेत और फ़सल से जुड़ी चीजें ही दिमाग़ में आती हैं, लेकिन शंघाई के एक 58 वर्षीय किसान ने अजब कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखने के लिए आसपास के शहरों से भी लोग आ रहे हैं. उक्त किसान हवाई जहाज बनाना चाहता है और इसके लिए पिछले दो वर्षों से प्रयासरत है. सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वह इसे कबाड़ में बेकार पड़ी चीजों की सहायता से बना रहा है. इस काम में अब तक उसके 6200 डॉलर (लगभग तीन लाख ग्यारह हज़ार रुपये) लग चुके हैं.

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह अचानक यात्रा का योग बनेगा. पारिवारिक मतभेद बढ़ने की आशंका है आप अपनी बातें मनवाने की जिद्द न करें. परिवार के अंदर संतान प्राप्ति की ख़बर मिलेगी. आर्थिक रूप से शुभ समय होगा. धनार्जन की उम्मीद बनी रहेगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आप हर्षित रहेंगे. व्यापारी वर्ग अपने व्यापार से प्रसन्न होंगे और उद्यम बढ़ाने की सोचेंगे. शुभ समाचार प्राप्त होगा. नौकरीपेशा लोग ख़र्च पर नियंत्रण रखें. कार्यालय में अपनी उन्नति से संबंधित बातें समझदारी से अपने अधिकारी के सामने प्रस्तुत करें.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
यह सप्ताह आपके लिए कष्टप्रद और थोड़ा थकावट वाला होगा. कोई मांगलिक कार्य संपादित करने की वजह से थकावट ज़्यादा होगी. दांपत्य जीवन सुखकारी रहेगा. शारीरिक रूप से थोड़ा कष्ट बढ़ेगा. अस्थि विकार होने पर चिकित्सक से मिलें. गुस्से पर नियंत्रण रखें. आर्थिक तनाव को ज़्यादा न बढ़ने दें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह आप किसी नई जगह की यात्रा के लिए तैयार रहें. किसी लंबित सरकारी कार्य से संबंधित शुभ सूचना प्राप्त होगी. आर्थिक रूप से व्यापारी और नौकरीपेशा दोनों वर्ग ख़ुश रहेंगे. वाहन तेज़ न चलाएं, अन्यथा नुक़सान होगा. पानी और धूप से संबंधित एलर्जी से बचें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह आप थोड़ी अलग प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे. यात्रा से बचें, अन्यथा तकलीफ होगी. नई संपत्ति ख़रीदने की सोचेंगे और संयोग भी अच्छा रहेगा. ख़र्चा ज़्यादा दिख रहा है, अत: बजट नियंत्रण में रखें. रक्तचाप का ध्यान रखें. संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आपके सहयोगी, सहपाठी और पुराने मित्र नज़दीक आएंगे और आपको सबकी मदद प्राप्त रहेगी. परिवारीजनों का बर्ताव भी आपके पक्ष में होगा. ख़र्च बढ़ेगा, जो मानसिक तनाव का कारण बनेगा. गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको नुक़सान होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आप इस सप्ताह स्थानांतरण के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें. कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा. आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी. आर्थिक रूप से आप मज़बूत होंगे. परिवारीजनों का स्नेह मिलेगा. किसी पुराने क़र्ज़ की वापसी की संभावना बढ़ेगी. आप अपने व्यक्तित्व के निखार में सफल रहेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
परिवार से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. कोई यात्रा संबंधी योजना बना सकते हैं. किसी पुराने कार्य से संबंधित पुरस्कार की संभावना बनती है. आर्थिक रूप से थोड़े तनाव में रहेंगे. सहयोगियों एवं परिवारीजनों का समर्थन प्राप्त होगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य से संबंधित चिंता परेशान करेगी. कोई संपत्ति ख़रीदेंगे. क़ानूनी मामले से बचें. कोई निर्णय करने से पहले आत्ममंथन करने की ज़रूरत है. सड़क पर चलते समय सावधानी बरतें. आर्थिक रूप से आप अच्छा महसूस करेंगे. किसी के ऊपर अत्यधिक विश्वास करके कोई कार्य न करें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह आपकी कार्यशैली में थोड़ा बदलाव आएगा और आप एक अच्छा बदलाव महसूस करेंगे. कोई क़ानूनी दांव-पेंच से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा. आपको अतिथि सेवा में भी समय देना पड़ेगा. आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा समय रहेगा. युवा उत्साहित रहेंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह भाग्य आपके साथ चलेगा. दुश्मनों पर निगाह रखें, अन्यथा आपको नुक़सान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. कुछ पारिवारिक मामलों की वजह से आप थोड़ा अस्थिर महसूस करेंगे. कुछ उम्मीद के परे लाभ होने की संभावना है. शारीरिक रूप से मज़बूत रहेंगे. ख़र्च को रोकें और जोखिम वाले बाज़ार से बचें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
आप व्यर्थ का तनाव न लें. आप आर्थिक रूप से मज़बूत होंगे. संतान सुख प्राप्त होगा और दांपत्य जीवन सुखकारी रहेगा. किसी पुराने कार्य से संबंधित सफलता की संभावना बनेगी. कार्यालय और पारिवारिक कार्य के बीच संतुलन बनाकर चलने की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

भारत को अगर मध्य एशिया के ऊर्जा संसाधनों तक अपनी पहुंच बनानी है तो ईरान के साथ संबंध सुदृढ़ बनाना होगा.

ईरान पर अमेरिका का दोहरा चरित्र

एक तरफ़ उसे इज़रायल का दबाव झेलना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ़ उसे डर है कि अगर इस समय ईरान पर सैनिक कार्रवाई की गई तो उसकी फ़ज़ीहत हो जाएगी. इज़रायल की बात न मानने की कोई वजह तो अमेरिका को बतानी होगी, क्योंकि अमेरिका की यहूदी लॉबी की वहां के राजनीतिक गलियारे में अच्छी ख़ासी पहुंच है. अमेरिका के इस दोहरे रवैये से दूसरे देशों को यह समझना चाहिए कि वे अपनी विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर करें न कि किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव में.

ऐसा करना भारत के लिए और भी ज़रूरी है. हालांकि ईरान के मुद्दे पर भारत ने यूरोपीय संघ और अमेरिका की बात नहीं मानी है और राष्ट्रीय हितों को ही ध्यान में रखा है. भारत ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने और वहां से तेल आयात न करने की उनकी मांग को ख़ारिज कर दिया था. चूंकि भारत अपनी पेट्रोलियम खपत का 12 प्रतिशत ईरान से आयात करता है, जब तक इसका विकल्प न हो और ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कोई ठोस प्रमाण न मिले, भारत को ईरान के संबंध में अपना रुख़ ऐसा ही रखना चाहिए. लेकिन भारत की गठबंधन सरकार कब क्या कर दे, यह पता नहीं होता है. हाल में श्रीलंका में मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर पहले तो सरकार चुप रही, लेकिन जब सरकार के सहयोगी दल द्रमुक ने दबाव डाला तो उसे अमेरिका के उस प्रस्ताव का समर्थन करने को मजबूर होना पड़ा, जिसमें श्रीलंका में लिट्टे के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मानवाधिकार हनन की निंदा की गई है. इस मुद्दे को पश्चिमी मीडिया ने उठाया था और घटनाओं को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया था. तमिलनाडु के राजनीतिक दलों को तमिलों का कितना ख्याल है यह तो पता नहीं, लेकिन इस मुद्दे को उछालकर वह अपना वोट बैंक ही सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके साथ केंद्र सरकार सही ग़लत सोचे बिना निर्णय लेने को तैयार है, क्योंकि उसे अपनी सत्ता बचानी है. कहीं इसी तरह कोई सहयोगी दल ईरान के मुद्दे पर भी भारतीय नीति को बदलवाने की ठान ले तो सरकार वह भी कर देगी. भारतीय राजनीति में अमेरिका परस्त राजनीतिक दलों की कमी तो है नहीं. इसलिए इस बात का डर तो वर्तमान भारतीय सरकार के संबंध में बना ही रहता है. भारत को अगर मध्य एशिया के ऊर्जा संसाधनों तक अपनी पहुंच बनानी है तो ईरान के साथ संबंध सुदृढ़ बनाना होगा. अभी एक ईरान के सहयोग से मध्य एशिया तक समुद्री मार्ग से अपनी पहुंच बनाने के लिए एक ट्रांजिट रूट बना रही है. इससे समय और धन दोनों की बचत होगी. मध्य एशिया से तेल या गैस परिवहन में सहयोग मिलेगा तथा इसके दाम भी कुछ कम होंगे. इसलिए भारतीय राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि कम से कम विदेश नीति बनाने में आंतरिक राजनीति को तवज्जो न दे, बल्कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे. अमेरिका अपने हितों को ध्यान में रखता है. हालांकि हमें उसके नक्शे–क़दम पर नहीं चलना है, क्योंकि उसका हित दूसरे देशों का अहित करके पूरा होता है. लेकिन भारत का हित दूसरे देशों के हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करके पूरा होता है और होना भी चाहिए. हमें तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति करनी चाहिए. ईरान के मुद्दे पर अमेरिका का स्वार्थ जगज़ाहिर हो गया है. उम्मीद यही है कि भारत अमेरिका के जाल में नहीं फंसेगा.

rajiv@chauthiduniya.com

राजीव कुमार

ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और इज़रायल दूसरे देशों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. एक ओर इन दोनों देशों ने ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाया है और इसके कारण उस पर न केवल स्वयं आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, बल्कि दूसरे देशों पर भी इसके लिए दबाव डाला है. इसके विपरीत अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है. अमेरिका के एक अख़बार ने यह ख़बर छापी है कि ईरान के संबंध में अमेरिका का ताज़ा आकलन वही है, जो 2007 में था. उस समय अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी ने कहा था कि ईरान ने 2003 में ही परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम बंद कर दिया था. यही नहीं उस वरिष्ठ ख़ुफ़िया अधिकारी ने यह भी कहा है कि इज़रायल भले ही अमेरिका से ईरान के विषय में कठिन सवाल कर रहा है तथा ईरान के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई करने के लिए उस पर दबाव बना रहा है, लेकिन उसकी ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद भी इस बात से सहमत है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है. हालांकि यह भी कहा गया है कि अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसियां ईरान पर निगरानी रखे हुए हैं और उसके यूरेनियम संवर्द्धन तथा मिसाइलों के विकास के प्रयास का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है. कुछ महीने पहले अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान 2003 से लगातार परमाणु हथियारों पर अनुसंधान कर रहा है. हालांकि ईरान ने आईएईए की रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया था और कहा था कि यह अमेरिकी इशारे पर तैयार की गई रिपोर्ट है. ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है.

इन विरोधाभासी रिपोर्ट्स को क्या कहा जाए. एक तरफ़ ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर उस पर हमला करने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ़ कहा जाता है कि अभी उसके परमाणु बम बनाने के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं. अब सवाल उठता है कि अमेरिका के पहले के आकलन और अब के आकलन में समानता क्यों नहीं है? या तो अमेरिका पहले झूठ बोल रहा था या फिर अब झूठ बोल रहा है. अगर उसने पहले झूठी रिपोर्ट तैयार कराई थी तो इससे

ईरान में अमेरिका के अंतर्निहित स्वार्थों का पता चलता है. रूस तथा अन्य कई देश पहले से ही कह रहे थे कि ईरान के परमाणु बम बनाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, जिससे उस पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर आर्थिक प्रतिबंध लागाने का कोई औचित्य नहीं बनता है. भारत ने भी ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए और उससे तेल आयात करना जारी रखा है. लेकिन जब भारत ने अमेरिका तथा यूरोपीय संघ की बात नहीं मानी तो उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी. लेकिन अब वह ख़ुद ही कह रहा है कि ईरान के परमाणु बम बनाने के ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. इसके अलावा उसकी पुरानी रिपोर्ट को यदि झूठा माना जाए तो आईएईए की रिपोर्ट को भी ग़लत माना जाना चाहिए. ऐसे में यह बात साफ़ होती है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन अमेरिका के इशारों पर काम करते हैं. अमेरिका जो चाहे, जैसा चाहे उनसे रिपोर्ट तैयार करवा सकता है. भारत ने भी मुद्दा उठाया था कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों में कुछ देशों का दबदबा है. भारत सुरक्षा परिषद के विस्तार की बात कर रहा है. भारत का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय संगठनों में विकासशील देशों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो फिर वर्तमान दौर में इन संगठनों की अहमियत घटती जाएगी. यह समय की मांग है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों को कुछ गिने चुने देशों के चंगुल से बाहर निकाला जाए. अगर आईएईए की रिपोर्ट को इसी तरह झुठलाया गया तब तो इससे विश्वास उठ जाएगा. ईरान तो उसी समय कह रहा था कि आईएईए प्रमुख युकियो अमानो अमेरिका के हाथों की कठपुतली हैं और उसे संतुष्ट करने के लिए ही ईरान विरोधी रिपोर्ट तैयार की है. अमेरिका के इस ताज़ा आकलन से तो ईरान की बात ही सही मालूम होती है.

इसके विपरीत अगर अमेरिकी एजेंसी की नई रिपोर्ट को ग़लत मानें तो कहा जा सकता है कि अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई को या तो कुछ समय के लिए टालना चाहता है या फिर उसे इस बात का डर है कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने से उसे ज़्यादा नुक़सान होगा. चूंकि अमेरिका की तरफ़ से लगातार यह कहा जा रहा था कि अगले कुछ महीने में ईरान पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी. इज़रायल तो अमेरिका की हां का इंतज़ार कर रहा है. वह तो जल्द से जल्द ईरान पर सैन्य कार्रवाई करना चाहता है. उसे तो बस मौक़ा चाहिए, जो परमाणु बम बनाने के मुद्दे पर मिल रहा है. लेकिन अमेरिका अभी ऐसा नहीं चाहता है. ईरान पर सैन्य कार्रवाई टालने के कुछ कारण हैं. अभी वह अफ़ग़ानिस्तान में फंसा है. वहां शांति बहाल करने के लिए तालिबान से वार्ता कर रहा है. इसके अलावा कभी अमेरिका के घनिष्ठ सहयोगी पाकिस्तान के साथ उसके संबंध बिगड़े हुए हैं. हाल फ़िलहाल इस तरह के कोई संकेत भी अमेरिका को नहीं मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान पर अमेरिका की कार्रवाई में उसे सहयोग देगा. सहयोग की बात तो दूर पाकिस्तान तो ईरान के साथ संबंध और मज़बूत कर रहा है. उसने ईरान से अपने आर्थिक संबंध न केवल बनाए रखा है, बल्कि उसे और विस्तार देने की कोशिश भी की है. हाल में पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर आए थे. तीनों देशों ने इस बैठक में एकजुटता का परिचय भी दिया था. इससे अमेरिका ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने से डर रहा है. ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने से बचने का एक कारण ईरान की सैन्य और तकनीकी क्षमता का मज़बूत होना भी कहा जा सकता है. ईरान अमेरिका और इज़रायल की सैन्य कार्रवाई की धमकी से कभी डरा नहीं है. वह उनकी धमकियों का करारा जवाब देता रहा है. ईरान ने तो अमेरिकी ड्रोन को अपने क़ब्ज़े में लेकर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता भी दिखा दी है. हालांकि अमेरिका इसे मानने को तैयार नहीं है और वह कहता रहा है कि उसका ड्रोन तकनीकी ख़राबी की वजह से गिर गया था, ईरान ने उसे अपने क़ब्ज़े में तकनीक के कारण नहीं लिया था. अमेरिका जो भी कहे, लेकिन उसे वास्तविकता का ज्ञान तो है ही. संभव है कि इन्हीं कारणों से अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी ने ऐसा कहा है.

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

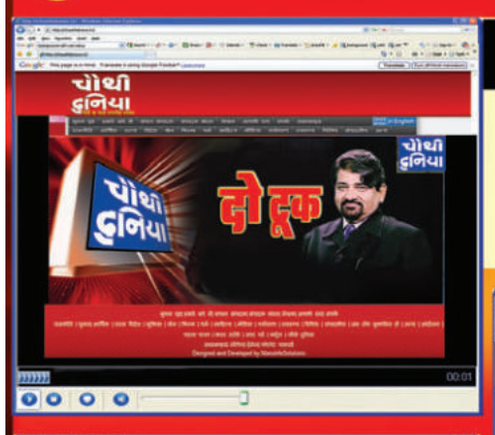

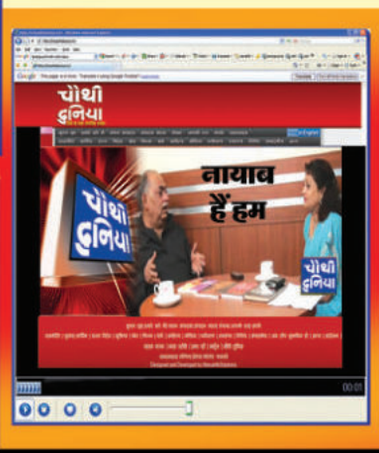

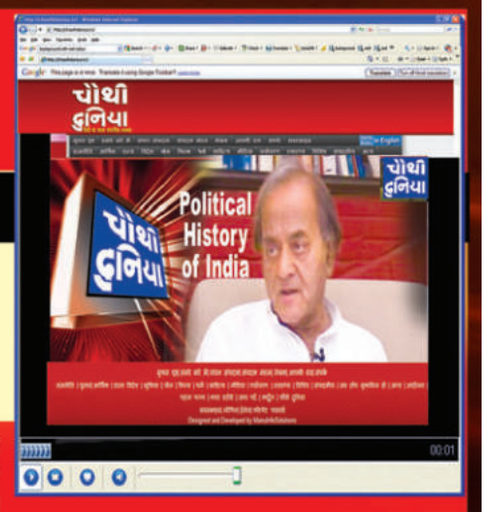

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

पिछले 40 साल से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा सफल नहीं क़रार दिया जा सकता, क्योंकि इन क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या अब तक वैसी ही बनी हुई है.

अब बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सरकार भ्रम फैला रही है

रीतिका एस बर्णवाल

साल 2012 में हमें यह सोचकर ख़ुश होना चाहिए कि समाज के कर्णधार यानी हमारी नौजवान पीढ़ी अब ज़्यादा स्वस्थ हो रही है. देश के सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्थान एम्स द्वारा 19 बड़े शहरों में किए गए सर्वे के अनुसार, साल 1992 के मुक़ाबले 2012 के युवा ज़्यादा लंबे और वज़न में भारी हो रहे हैं. इसी तथ्य पर सरकार यह मानती है कि पोषण में पौष्टिकता बढ़ने की वजह से बच्चे अब स्वस्थ हो रहे हैं. यह सर्वे रिपोर्ट नेशनल मेडिकल जरनल में दर्ज की गई है, जिसे सरकार सही मानती है. डॉ. रमन के. मारवा कहते हैं कि देश एक परिवर्तन की ओर जा रहा है. क्या वाक़ई यह माना जाए कि यह रिपोर्ट जो बताती है, वह सच है. पिछले दिनों एक और सर्वे रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की तरफ़ से. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक़, वैश्विक स्तर पर कुपोषित बच्चों की संख्या में बांग्लादेश के बाद भारत दूसरे नंबर पर है. यहां 47 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी तरह के कुपोषण का शिकार हैं. सामान्य से कम वज़न के बच्चे सबसे ज़्यादा है, यहां तक कि अफ्रीका से भी ज़्यादा. यूनिसेफ की एक और रिपोर्ट के मुताबिक़, भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मरने में 33 प्रतिशत की मृत्यु की वजह कुपोषण है. दरअसल, विश्व में मरने वाले कुल बच्चों की संख्या में आधे के मरने की वजह कुपोषण होती है. कुपोषित बच्चे में बीमारी रोधक क्षमता क्षीण होती है और बच्चों में होने वाली आम बीमारियों जैसे डायरिया, श्वास संबंधी, इंफेक्शन आदि से लड़ने की क्षमता नहीं होती और ऐसी छोटी-मोटी बीमारियों से उनकी मौत भी हो सकती है और इन बीमारियों के बाद जो कुपोषित बच्चे बच जाते हैं, वह स्वस्थ नहीं रहते. उन्हें बार-बार बीमारी होती ही रहती है, उनकी क़द काठी भी विकृत हो जाती है और मानसिक तंदुरुस्ती भी कमज़ोर पड़ जाती है. अब मुश्किल यह है कि भरोसा आख़िर किस रिपोर्ट पर किया जाए.

क्या कहते हैं डॉक्टर

नेशनल मेडिकल जरनल ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, बेहतर आय ग्रुप के और छोटे-बड़े शहरों के बच्चे ज़्यादा लंबे और बढ़े वज़न के हो रहे हैं. एनडीएमसी, सीएजी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. अनिल बंसल के अनुसार, यह संभावना इसलिए हो सकती है, क्योंकि माताएं जागरूक हो रही हैं. 1990 के बाद संचार क्रांति आई और इंटरनेट जैसी चीज़ों से पढ़ी-लिखी नौकरीपेशा या घरेलू महिलाएं भी रूबरू हुई हैं. प्रजनन के पहले और बाद में माताएं अपना और बच्चे का ज़्यादा ध्यान रख रही हैं. ऐसे में बच्चे के पोषण में कमी नहीं आती, जिसका असर उनके पूरे जीवन पर हर उम्र में दिखता है. क्योंकि शरीर की संरचना का मैप 0-3 साल तक की उम्र में ही तैयार हो जाता है. इसके अलावा स्कूलों में आजकल वैसे ही शारीरिक संरचना को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है, मसलन एक्सरसाइज, योग और दूसरी ऐसी प्रैक्टिसेज़ करवाई जा रही हैं, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो. आजकल बच्चे भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं. ऐसे में वे ख़ुद ही जिम इत्यादि जाकर तंदुरुस्त बनने में आगे होते हैं. इस वजह से 1992 के मुक़ाबले 2011 के 12-19 साल के बच्चे ज़्यादा लंबे हो सकते हैं. हालांकि वज़न बढ़ने की वजह डॉ. बंसल बच्चों के अनियमित खान-पान को बताते हैं, जैसे आजकल बच्चे बाहर का खाना या जंकफूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. इससे उनका वज़न बढ़ता है, जो किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है, वज़न बढ़ना स्वस्थ होने की निशानी नहीं है, बल्कि कई रोगों को रास्ता देने का एक ज़रिया है. इससे जहां तक हो सके बचना चाहिए. वहीं रोमासिस चाइल्ड हेल्थ केयर के न्योनाटोलॉजिस्ट डॉ. संजय वजीर कहते हैं कि इस रिपोर्ट में न तो कोई नई बात कही गई है और न ही इस रिपोर्ट से यह आश्वासन मिलता है कि देश में कुपोषण की समस्या ख़त्म हो गई है या हो रही है. यह बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जो अच्छी आय वाले परिवार होंगे, उनके बच्चों को बेहतर खान-पान मिलेगा. लेकिन इस आंकड़े को देश के कुपोषण की समस्या के आंकड़ों के सामने खड़ा नहीं किया जा सकता. इसे स्टैंडर्ड नहीं माना सकता है. दरअसल समय की आवश्यकता है कि हम सुदूर गांव में पैदा हुए बच्चे को कुपोषण के प्रकोप से बचाकर उसे एक अच्छा और स्वस्थ जीवन दे सकें. इसके लिए फूड सप्लीमेंट जैसी योजनाओं के साथ सरकार को भरण-पोषण जैसी सार्थक योजना की शुरुआत करनी होगी. वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट के मुताबिक़, देश के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तक़रीबन 50 प्रतिशत बच्चे कम वज़न के पाए गए, जबकि शहरी क्षेत्र में 38 प्रतिशत बच्चे अंडरवेट पाए गए. इनमें 48.9 प्रतिशत लड़कियां हैं और 45.5 प्रतिशत लड़के हैं. सबसे ज़्यादा अंडरवेट बच्चे पिछड़ी जाति में 53.2 प्रतिशत इसके बाद शेड्यूल ट्राइब, जिसमें 56.2 प्रतिशत और अन्य जातियों में 44.1 प्रतिशत देखे गए हैं. कुपोषण देश में फैलती तमाम बीमारियों में 22 प्रतिशत तक के लिए ज़िम्मेदार है. सामान्य से कम शारीरिक विकास होने की वजह है कि देश में 2 साल तक के बच्चों के लिए किसी प्रकार की देखरेख नहीं है, जबकि 3 साल तक पहुंचते-पहुंचते बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है. शरीर की क़द काठी और बनावट के लिए शरीर की संरचना 0-3 साल में तय हो जाती है, जबकि हमारे देश में कोई भी स्वास्थ्य लाभ योजना 3 साल के बाद के लिए ही है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक़, 1990 के बाद शहरी ग्रामीण, अंतरजातीय, लड़का-लड़की और दूसरे वर्गों में पोषण संबंधी असमानताओं में ज़्यादा फ़र्क़ देखने में आया. ऐसे में वैसी माताएं जिन्होंने प्रजनन के वक़्त अपना और बच्चे का ख़ास ध्यान रखा हो, 0 से 3 साल तक बच्चे के खान-पान का बेहतर ध्यान रखा हो, घर में पानी और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा हो, वैसी महिलाओं के बच्चे कुपोषण से बचे रहे हैं, क्योंकि बच्चों में कुपोषण होने की वजह माताओं में खान-पान का ख्याल न रखना या फिर इनमें से कोई भी वजह हो सकती है. ऐसे में बेहतर इनकम ग्रुप के या शहरी लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ज़्यादा देखी गई, जिसकी वजह से इस वर्ग के परिवारों के बच्चे ज़्यादा स्वस्थ हुए. नेशनल मेडिकल जरनल रिपोर्ट द्वारा करवाए गए सर्वे में ऐसे ही परिवारों के बच्चों का सर्वे करवाया गया है. यह रिपोर्ट देश के 19 शहरों में सर्वे कर तैयार की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि देश की भावी पीढ़ी स्वस्थ और निरोगी हो रही है. 1991 के मुक़ाबले 2011 में 12-19 साल के बच्चे 4 इंच ज़्यादा लंबे और 4 किलो ज़्यादा वज़न वाले हैं. इसलिए सरकार यह मानती है कि बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं जिनका श्रेय स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को दिया जा सकता है. इस बात पर ध्यान दिए बिना कि देश के किस वर्ग पर, किस बुनियाद पर इस तरह का सर्वे कराया गया. ये सरकारी आंकड़ें अब देश में कुपोषण की दर बताने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे यह समझ आएगा कि देश कुपोषण से लड़ने में कितना सक्षम हो पाया है. 1980 से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज़ द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं, जिनका सामान्य जीवन स्तर ज़्यादा संसाधित नहीं है.

असली भारत गांव में ही बसता है और वहां कुपोषण की समस्या जस की तस बनी हुई है. वैसे वर्ल्ड बैंक द्वारा पेश रिपोर्ट देश में तक़रीबन 60 मिलियन बच्चे अंडरवेट हैं, जिसका असर देश के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुधार और आर्थिक विकास पर पड़ रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा असर ग़रीब और ग्रामीणों पर ही पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कुपोषण देखा जाता है. दरअसल, सामान्य से कम वज़न होने की प्रवृत्ति परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है. परिवार जितना अधिक समृद्ध होगा, उनका खान-पान उतना ही बेहतर होगा और परिवार जितना ग़रीब होगा, उनके खान-पान में काफ़ी कमी होगी.

पिछले 40 साल से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा सफल नहीं क़रार दिया जा सकता, क्योंकि इन क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या अब तक वैसी ही बनी हुई है. अब ज़रूरत आ पड़ी थी कि इन कार्यक्रमों में सुधार किया जाए और ग्रामीण और ग़रीब क्षेत्र के बच्चों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सके, लेकिन आवश्यकता को नज़र अंदाज़ करते हुए सरकार ने इससे निपटने का दूसरा बेहतर तरीक़ा अपना लिया और एक नई सर्वे रिपोर्ट तैयार करवा दी, जिससे स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रमों की सफलता पर अपनी पीठ भी थपथपा सके और सुधार की ज़िम्मेदारियों से निपट भी जाए, इसमें उसका साथ दिया मीडिया ने. कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस रिपोर्ट को शान के साथ पहले पन्ने पर छापा जैसे सचमुच देश में बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो गया है और जिसका प्रमाण वह रिपोर्ट है. लेकिन ख़बर लिखने वाले ने शायद अपने आसपास नहीं देखा हो, शहरों में भी जो कम आय के लोग हैं, उनके घर के बच्चों की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. वे भी कुपोषण के शिकार होते हैं. सरकार इस तरह का सर्वे करवाकर और रिपोर्ट प्रकाशित करवाकर समाज में एक तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, वैसे भी यह सरकार आंकड़ों के खेल में ही विकास, ग़रीबी-अमीरी के मायने और महंगाई जैसे मुद्दे के साथ खिलवाड़ करने में माहिर रही है. तेल, खेल, शिक्षा और बाक़ी सभी क्षेत्रों में पेंच लगाकर सरकार घोटालों का गढ़ बन चुकी है और अब इसका अगला क़दम स्वास्थ्य की ओर है.

असली भारत गांव में ही बसता है और वहां कुपोषण की समस्या जस की तस बनी हुई है. वैसे वर्ल्ड बैंक द्वारा पेश रिपोर्ट देश में तक़रीबन 60 मिलियन बच्चे अंडरवेट हैं, जिसका असर देश के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुधार और आर्थिक विकास पर पड़ रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा असर ग़रीब और ग्रामीणों पर ही पड़ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कुपोषण देखा जाता है. दरअसल, सामान्य से कम वज़न होने की प्रवृत्ति परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है. परिवार जितना अधिक समृद्ध होगा, उनका खान-पान उतना ही बेहतर होगा और परिवार जितना ग़रीब होगा, उनके खान-पान में काफ़ी कमी होगी.

कुछ मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस रिपोर्ट को शान के साथ पहले पन्ने पर छापा जैसे सचमुच देश में बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो गया है और जिसका प्रमाण वह रिपोर्ट है. लेकिन ख़बर लिखने वाले ने शायद अपने आसपास नहीं देखा हो, शहरों में भी जो कम आय के लोग हैं, उनके घर के बच्चों की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. वे भी कुपोषण के शिकार होते हैं. सरकार इस तरह का सर्वे करवाकर और रिपोर्ट प्रकाशित करवाकर समाज में एक तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, वैसे भी यह सरकार आंकड़ों के खेल में ही विकास, ग़रीबी-अमीरी के मायने और महंगाई जैसे मुद्दे के साथ खिलवाड़ करने में माहिर रही है.

ritika@chauthiduniya.com

अगर नवीनता सिर्फ़ नयेपन के लिए है तो कोई लाख समझे कि उसकी शायरी में सुर्ख़ाब के पर लग गए हैं, मगर उन परों में उड़ने की ताक़त नहीं हो सकती.

अनंत विजय

काटजू का जादुई यथार्थवाद

पिछले दिनों दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वरिष्ठ पत्रकारों एवं संपादकों का जमावड़ा हुआ, मौक़ा था पत्रकार शैलेश और डॉ. ब्रजमोहन की वाणी प्रकाशन से प्रकाशित किताब स्मार्ट रिपोर्टर के विमोचन का. किताब का औपचारिक विमोचन प्रेस परिषद के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू के साथ-साथ एन के सिंह, आशुतोष, कमर वहीद नकवी एवं शशि शेखर ने किया. विमोचन के बाद वक्ताओं ने बोलना शुरू किया. जस्टिस काटजू के बगल में बैठे ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव एन के सिंह ने सारगर्भित भाषण दिया और पत्रकारों को पेशेगत ज़रूरी औज़ारों से लैस रहने की वकालत भी की. उसके बाद आईबीएन-7 के प्रबंध संपादक आशुतोष ने ओजपूर्ण तरीक़े से अपनी बात रखी और कहा कि एक पत्रकार को अपने पेशे के हिसाब से ज़रूरी जानकारी रहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसे हर विषय का विद्वान होना चाहिए. इसके अलावा आशुतोष ने वाटरगेट कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि एक पत्रकार को छोटी से छोटी घटना को मामूली कहकर खारिज नहीं करना चाहिए. एक पत्रकार की सबसे बड़ी भूमिका यह होती है कि वह जो देखे, उसे दिखाए. आज तक के न्यूज़ डायरेक्टर कमर वहीद नकवी ने एक बेहद दिलचस्प वाकया बयां किया. उन्होंने बताया कि एक दिन उनके चैनल पर ख़बर चली कि अमुक जगह पर पारा साठ डिग्री के पार हो गया. जब ख़बर चली को उन्होंने पूछताछ शुरू की कि ख़बर कहां से आई और कैसे चली. काफी छानबीन के बाद पता चला कि उस इलाक़े के एक स्ट्रिंगर ने ख़बर भेजी और उसमें एक सिपाही की बाइट लगी हुई थी कि इस बार गर्मी काफी बढ़ गई है और लगता है, पारा साठ डिग्री के पार हो गया है. नकवी जी ने बताया कि उन्हें इस बात की हैरानी हुई कि कहीं भी किसी भी स्तर पर यह चेक करने की कोशिश नहीं की गई कि पारा साठ डिग्री तक पहुंच गया, यह बात कौन कह रहा है. नकवी जी ने इस वाकए के हवाले से पत्रकारिता में तथ्यों की जांच करने की कम होती प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया और ख़बरों को चेक करने की जोरदार वकालत की. हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर ने भी एक रिपोर्टर और संपादक की ख़बरों को फिल्टर करने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि जब वह आज तक में काम करते थे, उस दौरान संसद में गोलीबारी की ख़बर आई. उस वक़्त वे लोग एक मीटिंग में थे और जब यह ख़बर आई तो मीटिंग से प्रोडक्शन कंट्रोल रूम तक दौड़ते हुए आशुतोष ने यही कहा था कि संसद में गोलीबारी हुई है, बस इतनी सी ख़बर चलाओ. शशि शेखर ने इस वाकये के हवाले से कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ख़बरों को पेश करने में संतुलन को क़ायम रखने का मुद्दा उठाया.

इसके बाद बारी थी प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस काटजू की. उन्होंने पहले तो शैलेश-ब्रजमोहन की किताब की जमकर तारीफ़ की और उसे पत्रकारिता के कोर्स में लगाने की वकालत भी. थोड़ी देर बाद वह अपने पुराने फॉर्म में लौटे और वहां मौजूद तमाम संपादकों के सामने मीडिया को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका उपदेश देने लगे. तक़रीबन सभी हिंदी न्यूज़ चैनलों के संपादकों की उपस्थिति से काटजू साहब कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गए. बोलते-बोलते वह कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए और सचिन तेंदुलकर एवं देवानंद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर डाली. देवानंद की मौत की ख़बर न्यूज़ चैनलों पर प्रमुखता से प्रसारित करने पर काटजू ने मीडिया पर तीखा हमला बोला. उनके कहने का लब्बोलुआब यह था कि देवानंद मर गए तो कोई आफत नहीं आ गई, जो सारे न्यूज़ चैनल दिन भर उस ख़बर पर लगे रहे. उसके पहले भी उन्होंने वहां मौजूद संपादकों को चुभने वाली बातें कही थीं, लेकिन पद की गरिमा और कार्यक्रम की मर्यादा का ध्यान रखते हुए तमाम संपादक और पत्रकार चुप थे. जब देवानंद के बारे में उन्होंने हल्की टिप्पणी की तो आशुतोष ने उनके भाषण को बीच में रोक कर जोरदार प्रतिवाद दर्ज कराया. आशुतोष ने कहा कि देवानंद एक महान कलाकार थे और उनके बारे में इस तरह की हल्की टिप्पणी नहीं की जा सकती है. उसके बाद थोड़ा सा हो-हल्ला मचा, लेकिन फिर मामला शांत हो गया. संपादकों के विरोध से काटजू और ज़्यादा आक्रामक हो गए. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सौवें शतक की ख़बर बिना रुके न्यूज़ चैनलों पर दिखाए जाने पर भी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सचिन के शतक से ऐसा लगा कि देश में दूध की नदियां बह जाएंगी, ख़ुशहाली आ जाएगी आदि-आदि. काटजू विद्वान न्यायाधीश रहे हैं, काफी पढ़े-लिखे माने जाते हैं, लेकिन वह यह कैसे भूल गए कि भारतीय परंपरा में मृत लोगों के बारे में अपमानजनक बातें नहीं कही जाती हैं. देवानंद हमारे देश के एक महान कलाकार थे और उनकी कला को काटजू के प्रमाणपत्र की ज़रूरत भी नहीं है. जिस तरह उन्होंने देवानंद पर टिप्पणी की, वह उनकी सामंती मानसिकता को दर्शाता है, जिसमें फिल्मों में काम करने वाला महज़ नाचने-गाने वाला होता है. काटजू को देवानंद पर दिए गए अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए.

आज तक के न्यूज़ डायरेक्टर कमर वहीद नकवी ने एक बेहद दिलचस्प वाकया बयां किया. उन्होंने बताया कि एक दिन उनके चैनल पर ख़बर चली कि अमुक जगह पर पारा साठ डिग्री के पार हो गया. जब ख़बर चली को उन्होंने पूछताछ शुरू की कि ख़बर कहां से आई और कैसे चली. काफी छानबीन के बाद पता चला कि उस इलाक़े के एक स्ट्रिंगर ने ख़बर भेजी और उसमें एक सिपाही की बाइट लगी हुई थी कि इस बार गर्मी काफी बढ़ गई है और लगता है, पारा साठ डिग्री के पार हो गया है. नकवी जी ने बताया कि उन्हें इस बात की हैरानी हुई कि कहीं भी किसी भी स्तर पर यह चेक करने की कोशिश नहीं की गई कि पारा साठ डिग्री तक पहुंच गया, यह बात कौन कह रहा है. नकवी जी ने इस वाकए के हवाले से पत्रकारिता में तथ्यों की जांच करने की कम होती प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया और ख़बरों को चेक करने की जोरदार वकालत की. हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर ने भी एक रिपोर्टर और संपादक की ख़बरों को फिल्टर करने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि जब वह आज तक में काम करते थे, उस दौरान संसद में गोलीबारी की ख़बर आई.

काटजू ने मीडिया को एक बार फिर से ग़रीबों, किसानों की आवाज़ बनने और देश की आम जनता को शिक्षित करने के उसके दायित्व की याद दिलाई. जस्टिस काटजू ने यह कहकर अपनी पीठ भी थपथपाई कि अगर उन्होंने मुहिम न चलाई होती तो ऐश्वर्या राय के मां बनने की ख़बर न्यूज़ चैनलों पर बेहद प्रमुखता से चली होती, लेकिन अपनी तारीफ़ करते वक़्त जस्टिस काटजू को यह याद नहीं रहा कि उसके पहले भी संपादकों की संस्था बीईए ने कई मौक़ों पर ऐसे फ़ैसले लिए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले के वक़्त की रिपोर्टिंग में देखी जा सकती है. दरअसल जस्टिस काटजू न्यूज़ चैनलों को भी प्रेस परिषद के दायरे में लाना चाहते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि प्रेस परिषद ने अपने गठन के बाद से लेकर अब तक कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया. उसकी वजह चाहे जो भी हो. दरअसल जिस तरह से देश का माहौल बदला है, वैसे में प्रेस परिषद जैसी दंतविहीन संस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है. प्रेस परिषद तो जनता के पैसों की बर्बादी है, जहां से कुछ ठोस निकलता नहीं है, क्योंकि उसकी परिकल्पना ही सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी. इसलिए अब वक़्त आ गया है कि सरकार प्रेस परिषद पर होने वाले फिजूल के ख़र्च को बंद करे और इस संगठन को ख़त्म करके जनता की गाढ़ी कमाई किसी जनकल्याणकारी कार्य में ख़र्च करे. इन तमाम बहस-मुबाहिसे के बीच शैलेश और ब्रजमोहन द्वारा लिखी गई किताब पर कम चर्चा हो पाई. यह किताब पत्रकारिता में क़दम रखने वालों को बेहद बुनियादी जानकारी देती है, उसे न्यूज़ चैनलों में होने वाली हलचलों से न केवल वाक़िफ़ कराती है, बल्कि उसे शिक्षित भी करती चलती है. ब्रजमोहन जी की इस किताब में देश के शीर्ष रिपोर्टरों के अनुभवों को आधार बनाया गया है, जो इसे पांडित्य और शास्त्रीय बोझिलता से मुक्त करता है. इस किताब की एक और विशेषता है कि इसमें विभिन्न चित्रों के माध्यम से स्थितियों को समझाने की कोशिश की गई है, जिससे पाठकों को सहूलियत होती है. यह किताब सिर्फ़ पत्रकारिता के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए उपयोगी और रोचक है, जिनकी इस विषय में थोड़ी सी भी रुचि है.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

नए रास्तों की तलाश

फ़िरदौस ख़ान

राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित लावा सुप्रतिष्ठित ग़ज़लकार, पटकथाकार जावेद अख्तर का दूसरा ग़ज़ल और नज़्म संग्रह है. उनका पहला ग़ज़ल संग्रह तरकश 1995 में प्रकाशित हुआ था. क़रीब डेढ़ दशक से ज़्यादा अरसे बाद दूसरा संग्रह आने पर जावेद कहते हैं, अगर मेरी सुस्ती और आलस्य को नज़र अंदाज़ कर दिया जाए तो इस देर की एक वजह बताई जा सकती है कि मेरे ख्याल में एक के बाद दूसरे संग्रहों का अंबार लगा देना अपने अंदर कोई कारनामा नहीं है. मैं समझता हूं कि अगर अंबार लगे तो नए-नए विचारों का. जिस विचार को रचना का रूप मिल चुका हो, जिस विचार को अभिव्यक्ति मिल चुकी हो, उसे अगर किसी कारण कहने की ज़रूरत महसूस भी हो रही हो, तो कम से कम कथन शैली में ही कोई नवीनता, कोई विशिष्टता हो, वरना पाठक और श्रोता को बिना वजह तकलीफ़ क्यों दी जाए. अगर नवीनता सिर्फ़ नयेपन के लिए है तो कोई लाख समझे कि उसकी शायरी में सुर्ख़ाब के पर लग गए हैं, मगर उन परों में उड़ने की ताक़त नहीं हो सकती. बात तो जब है कि अक़्ल की पहरेदारी भी मौजूद हो और दिल भी महसूस करे कि उसे तन्हा छोड़ दिया गया है. मैं जानता हूं कि इसमें असंगति है, मगर बेख़ुदी-ओ-शायरी, सादगी-ओ-पुरकारी, ये सब एक साथ दरकार हैं. वह कहते हैं, दरअसल, शायरी बुद्धि और मन का मिश्रण, विचार और भावनाओं का समन्वय मांगती है. मैंने सच्चे दिल से यही कोशिश की है कि मैं शायरी की यह फ़रमाईश पूरी कर सकूं. शायद इसलिए देर लग गई. फिर भी कौन जाने यह फ़रमाईश किस हद तक पूरी हो सकी है.

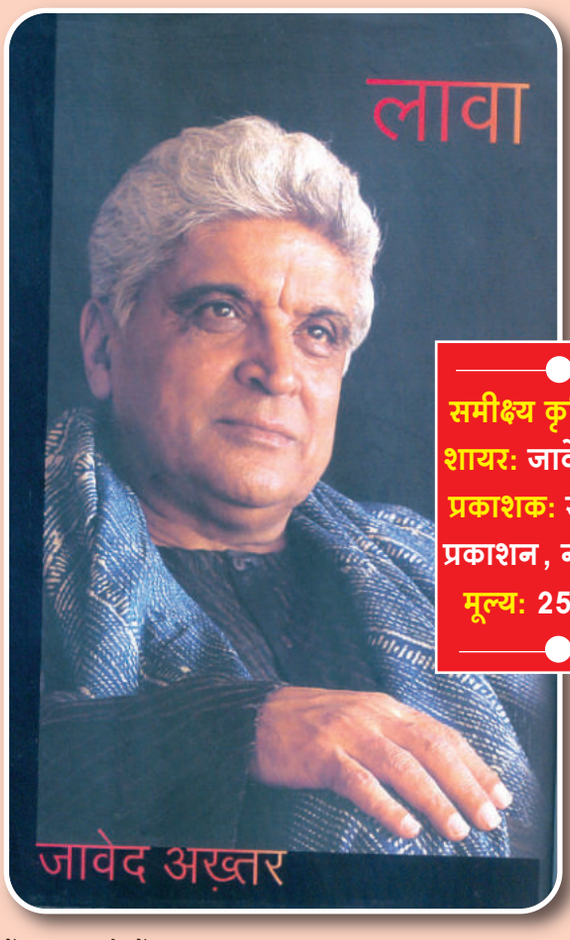

समीक्ष्य कृति: लावा
शायर: जावेद अख्तर
प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य: 250 रुपये

लावा के बारे में यह कहना क़तई ग़लत नहीं होगा कि देर आयद, दुरुस्त आयद. बेशक जावेद साहब अपने चाहने वालों की फ़रमाईश पूरी करने में खरे उतरे हैं. अपनी शायरी के बारे में वह कहते हैं, मैं जो सोचता हूं, वही लिखता हूं:-

जिधर जाते हैं सब, जाना उधर अच्छा नहीं लगता
मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता
ग़लत बातों को ख़ामोशी से सुनना, हामी भर लेना
बहुत हैं फ़ायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता
मुझे दुश्मन से भी ख़ुद्दारी की उम्मीद रहती है
किसी का भी हो सर, क़दमों में अच्छा नहीं लगता

17 जनवरी, 1945 को ग्वालियर में जन्मे जावेद अख्तर के पिता जांनिसार अख्तर प्रसिद्ध प्रगतिशील शायर थे. उनकी मां सफ़िया मशहूर उर्दू लेखिका एवं शिक्षिका थीं. जावेद मशहूर शायर असरारुल हक़ मजाज़ के भांजे हैं. उनके ससुर कैफ़ी आज़मी भी मशहूर शायर थे. जावेद की शायरी में भी वही तेवर नज़र आते हैं, जो उनके पिता के कलाम की जान रहे हैं. वह कहते हैं:-

ख़ून से सींची है मैंने जो ज़मीं मर-मर के
वो ज़मीं, एक सितमगर ने कहा, उसकी है
उसने ही इसको उजाड़ा है, इसे लूटा है
ये ज़मीं उसकी अगर है भी तो क्या उसकी है?

उनकी पंद्रह अगस्त नामक नज़्म 15 अगस्त, 2007 को संसद भवन में उसी जगह सुनाई गई थी, जहां से 15 अगस्त, 1947 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मुल्क की आज़ादी का ऐलान किया था.

यही जगह थी, यही दिन था और यही लम्हात
यहीं तो देखा था इक ख्वाब, सोची थी इक बात
मुसाफ़िरों के दिलों में ख्याल आता है
हर इक ज़मीर के आगे सवाल आता है

जावेद अख्तर इस बात पर ख़ुशी का इज़हार करते हैं कि आज के दौर में भी शायरी की समाज में बहुत अहमियत है, जबकि लोगों को अपने रिश्तेदारों से मिलने तक का वक़्त नहीं मिल पाता. अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में भी लोग शायरी और अदब के लिए वक़्त निकालते हैं.

इंसान में सच कहने के साथ ही सच को क़ुबूल करने की भी क़ूवत होनी चाहिए. यह जज़्बा जावेद की शायरी में नज़र आता है. उनकी नज़्म एतेराफ़ यानी स्वीकारोक्ति इसी जज़्बे को बयां करती है:-

सच तो ये है क़ुसूर अपना है
चांद को छूने की तमन्ना की
आसमां को ज़मीन पर मांगा
फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले
कांटों में की तलाश ख़ुशबू की
आग से मांगते रहे ठंडक
ख्वाब जो देखा
चाहा सच हो जाए
इसकी हमको सज़ा तो मिलनी थी

उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बीती 26 फ़रवरी को दिल्ली के इंडिया हेबिटेट सेंटर में लावा का लोकार्पण किया. बक़ौल अंसारी, जावेद अख्तर की ग़ज़लें और नज़्में लावा शब्द के अर्थों पर पूरी तरह मुकम्मल उतरती हैं. साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष गोपीचंद नारंग का कहना था कि जावेद की ज़िंदगी की जद्दोजहद ही लावा की शायरी में बदल कर आ गई है. इस मौक़े पर शबाना आज़मी, ज़ोया अख्तर और फ़रहान अख्तर भी मौजूद थे.

जावेद अख्तर ने यह किताब अपने एक दोस्त को समर्पित की है. उन्होंने लिखा, यह किताब उन तस्वीरों, गीतों और यादों के नाम, जिन्हें मेरा दोस्त फ़रहान मुजीब अपने पीछे छोड़ गया है. किताब में पहले एक नज़्म, उसके बाद एक ग़ज़ल दी गई है. ग़ज़ल के बाद ख़ाली जगह में एक शेअर दिया गया है. यह किताब उम्दा नज़्मों और ग़ज़लों का एक ऐसा संग्रह है, जिसे बार-बार पढ़ने को जी चाहेगा.

हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है
हम हैं मुसाफ़िर ऐसे, जो मंज़िल से आए हैं

firdaus@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
पावर थिंकिंग

लेखक
डॉ. उज्जवल पाटनी

प्रकाशक
डायमंड बुक्स

मूल्य
185 रुपये

इस किताब में व्यक्तित्व निखारने के गुर बताए गए हैं.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

आई475डब्ल्यू का डिस्प्ले रेज्योलूशन 176/220 है. इसमें दिया गया वीजीए कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का है. इस फोन में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी दी गई है.

मोटोरोला का आई475डब्ल्यू

हैंडसेट के उभरते बाज़ार में मोटोरोला ने नई बाज़ी मारी है. कंपनी ने दूसरे मोबाइल फोन मॉडल्स को मात देने के लिए नया क्वार्टी की पैड फोन लांच किया है. कंपनी के अनुसार, मोटोरोला आई475डब्ल्यू एक बजट फ्रेंडली फोन है. आई475डब्ल्यू फोन में 2 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो 65 मिलियन कलर को सपोर्ट करती है. इसके अलावा फोन में कैमरे का स्टैंडर्ड फीचर भी मौजूद है. अगर आप फोन से अपने पीसी या फिर लैपटॉप में कोई डाटा डालना या लेना चाहते हैं तो इसके लिए यूएसबी पोर्ट और ब्लूटूथ कनेक्टीविटी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं. म्यूजिक लवर्स के लिए भी मोटोरोला आई475डब्ल्यू एक ख़ास विकल्प होगा, क्योंकि इसमें एफएम रेडियो की सुविधा दी गई है. आई475डब्ल्यू का डिस्प्ले रेज्योलूशन 176/220 है. इसमें दिया गया वीजीए कैमरा 0.3 मेगापिक्सल का है. इस फोन में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी दी गई है. इस फोन का वज़न केवल 100 ग्राम है. 100 घंटे का स्टैंडबॉय टाइम के साथ इसमें 3 घंटे 40 मिनट का टॉक टाइम है. भारतीय बाज़ार में मोटोरोला आई475डब्ल्यू फोन 11,000 रुपये की अनुमानित क़ीमत में उपलब्ध होगा.

कैनन का वॉटरप्रूफ कैमरा

कैनन का नया डी-20 कैमरा थोड़ा अलग है. डी-20 में पानी का कोई असर नहीं होता. इसके अलावा इसमें वाईफाई और पॉवर शॉट प्वाइंट का फीचर दिया गया है, जो सटीक फोटो कैपचरिंग में मदद करता है.

कैनन ने अपनी डिजिटल कैमरे की रेंज में एक नया कैमरा लांच किया है. साधारण कैमरे के मुक़ाबले कैनन का नया डी-20 कैमरा थोड़ा अलग है. डी-20 में पानी का कोई असर नहीं होता. इसके अलावा इसमें वाईफाई और पॉवर शॉट प्वाइंट का फीचर दिया गया है, जो सटीक फोटो कैपचरिंग में मदद करता है. कंपनी के मुताबिक़, डी-20 की मदद से पानी के अंदर भी वीडियो और फोटोग्राफी की जा सकती है. कैनन डी-20 में 2.5 इंच डिसप्ले के साथ 3 एक्स ऑप्टिकल जूम और 1080 फुल एचडी सपोर्ट दिया गया है. कैमरे में 12.1 मेगापिक्सल सेंसर इनबिल्ड है, जो पानी के अंदर भी साफ़ क्वालिटी की पिक्चर खींचता है. कंपनी के अनुसार, कैनन का नया डी-20 वॉटरप्रूफ कैमरा मई 2012 तक बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा. कैनन डी-20 वीजीए आउटपुट देता है, जिसे किसी भी फॉरमेट में कनवर्ट कर स्टोर किया जा सकता है. यह डिजिक 4 प्रोसेसर को सपोर्ट करता है. इस शानदार कैमरे की अनुमानित क़ीमत 17,328 रुपये होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

इंटेक्स बार स्पीकर

मारवेल 250 नाम से लांच किए गए इन स्पीकरों की आवाज़ सुनकर मज़ा आ जाएगा. स्पीकरों से 2.4 गीगाहर्ट के सब बूफर दिए गए हैं, जो पिक्चर हाल जैसा साउंड प्रोवाइड करते हैं.

आपके ड्राइंग रूम में चार चांद लगा देते हैं नए-नए प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण. भारत में ऑडियो प्रोडेक्ट बनाने वाली अग्रणी कंपनी इंटेक्स ने नए साउंड बार स्पीकर लांच किए हैं. इंटेक्स के ये नए स्पीकर देखने में सुंदर होने के साथ-साथ कंर्फटेबल और पोर्टेबल भी हैं.

मारवेल 250 नाम से लांच किए गए इन स्पीकरों की आवाज़ सुनकर मज़ा आ जाएगा. स्पीकरों से 2.4 गीगाहर्ट के सब बूफर दिए गए हैं, जो पिक्चर हाल जैसा साउंड प्रोवाइड करते हैं. साथ में स्पीकरों का लुक आपके ड्राइंग रूम को चार चांद लगा देगा.

स्पीकरों के साथ एक वॉयरलैस सबवूफर भी दिया गया है, जिसे यूजर कहीं भी आसानी से रख सकता है. वॉयरलैस कनेक्टीविटी के लिए स्पीकरों में ब्लूटूथ की सुविधा दी गई है. अगर आप अपने ड्राइंग रूम में थियेटर जैसा साउंड एक्पीरियंस लेना चाहते हैं तो इंटेक्स के साउंड बार मारवेल 250 स्पीकर एक अच्छी च्वाइस हो सकती है. इंटेक्स साउंड बार स्पीकरों में वर्चुअल साउंड के साथ लो पॉवर रेडियो और 100 वॉट के सबवूफर दिए गए हैं, जो हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट देता है. इसका एसएमपीएस बेस पॉवर सप्लाई 80 वॉट का आउटपुट देता है. बाज़ार में स्पीकरों को 14,000 रुपये की अनुमानित क़ीमत में लांच किया गया है.

एचसीएल का हैंडी और सस्ता लैपटॉप

अगर आप एक हैंडी और कम दाम का लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आज ही एचसीएल स्टोर में जाकर मस्त लैपटॉप ख़रीद सकते हैं, जो सुंदर और सस्ता होने के साथ-साथ सुविधाजनक भी होगा. दरअसल, लैपटॉप की दुनिया में एचसीएल ने कुछ समय पहले एक नया कीर्तिमान दर्ज किया था. भारतीय कंपनी एचसीएल के ख़ेमे में अब तक का सबसे सस्ता लैपटॉप मॉयलीप मौजूद है, जिसकी क़ीमत मात्र 13,990 रुपये है. इसे दुनिया का सबसे सस्ता लैपटॉप भी कहा जा रहा है. एक्स सीरीज के इस नए लैपटॉप में लाइनेक्स बेस्ड आपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. इस सीरीज के अंतर्गत आने वाले सबसे महंगे लैपटॉप की क़ीमत 16,990 रुपये है. कम क़ीमत के बावजूद लैपटॉप में तकनीकी रूप से कोई कमी नहीं है. क़ीमत को देखते हुए लैपटॉप में वाई-फाई और टच स्क्रीन की सुविधा दी गई है. लैपटॉप में दी गई 7 इंच की स्क्रीन का टच अच्छा वर्क करता है. इसके अलावा अगर आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं तो एचसीएल का नया लैपटॉप आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसका भार मात्र 1 किलोग्राम है. बेहतर पावर के लिए लैपटॉप में इंटल का प्रोसेसर दिया गया है.

भारतीय कंपनी एचसीएल के ख़ेमे में अब तक का सबसे सस्ता लैपटॉप मॉयलीप मौजूद है, जिसकी क़ीमत मात्र 13,990 रुपये है. इसे दुनिया का सबसे सस्ता लैपटॉप भी कहा जा रहा है.

सैमसंग का स्मार्ट म्यूजिक प्लेयर

ऑडियो बाज़ार में भी सैमसंग ने अपने क़दम जमाने शुरू कर दिए हैं. सैमसंग ने हाल में गैलेक्सी 70 प्लस नाम से नया म्यूजिक प्लेयर लांच किया है.

अभी तक तो सैमसंग स्मार्ट फोन के अलग-अलग रेंज के धमाकेदार लांच से धूम मचा रहा था, लेकिन अब कंपनी एक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बाज़ार पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश में लगी है. अब ऑडियो बाज़ार में भी सैमसंग ने अपने क़दम जमाने शुरू कर दिए हैं. सैमसंग ने हाल में गैलेक्सी 70 प्लस नाम से नया म्यूजिक प्लेयर लांच किया है. यह म्यूजिक प्लेयर कई मायनों में ख़ास है. अगर इसमें स्मार्ट फोन की मोबाइल सेवा को हटा दिया जाए तो लगभग सभी फीचर किसी स्मार्ट फोन से कम नहीं है. सैमसंग के नए गैलेक्सी प्लेयर 70 में 5 इंच की टच स्क्रीन के साथ ड्यूल कोर प्रोसेसर और 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया गया है. इसके अलावा यूजर वाईफाई और ब्लूटूथ की मदद से डेटा ट्रांसफर और अपलोड कर सकता है.

बाज़ार में सैमसंग ने गैलेक्सी प्लेयर 70 को 16 जीबी और 32 जीबी मैमोरी ऑप्शन के साथ लांच किया है, जिसमें से 16 जीबी मॉडल की क़ीमत 18,000 रुपये और 32 जीबी मॉडल की क़ीमत 21,000 रुपए है. सैमसंग गैलेक्सी प्लेयर 70 प्लस एंड्रॉएड जिंजरब्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है और इसमें 2500 एमएएच बैटरी है. इसमें एफएम रेडियो भी है. इस म्यूजिक प्लेयर की क़ीमत 21,000 रुपये है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

विराट कोहली

नए भारत की नई तस्वीर

नवीन चौहान

महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर भारतीय उपकप्तान विराट कोहली द्वारा मीरपुर के शेर-ए-बंगाल स्टेडियम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेली गई 183 रनों की धमाकेदार पारी के बाद भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित देखकर संन्यास लेने का विचार कर सकते हैं. विराट की इस पारी के बाद इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने ट्वीट किया था, एक भारतीय सुपर स्टार का एकदिवसीय क्रिकेट में उदय हो चुका है. महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा कि विराट की यह पारी भारत की नई पीढ़ी की कुछ भी पा लेने की ललक, प्यास और जज़्बे को दिखाती है...बहुत ख़ूब विराट...

दिल्ली के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे विराट शुरू से ही अपने नाम के अनुरूप काम करने लगे. पहली बार लोगों का ध्यान विराट की तरफ़ तब गया था, जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी के दिल्ली-कर्नाटक मैच के दौरान पिता की मृत्यु की ख़बर सुनने के बावजूद खेलना जारी रखा और दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण 90 रन बनाए. दिल्ली रणजी टीम के तत्कालीन कप्तान मिथुन मन्हास ने विराट की इस पारी को दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल बताया था. उस दिन के बाद विराट बहुत परिपक्व हो गए, उन्होंने हर मैच को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया. उसके बाद क्वालालंपुर में हुए अंडर-19 विश्वकप के लिए विराट को भारतीय टीम का कप्तान घोषित किया गया. इस विश्वकप के दौरान विराट की कप्तानी एवं बल्लेबाज़ी की बहुत प्रशंसा हुई और भारत अंडर-19 विश्वकप विजेता बना.

विराट की इस उपलब्धि ने उनके लिए भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे खोल दिए. 2009 में आस्ट्रेलिया में हुए इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट में भारत की जीत में विराट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 7 मैचों में 2 शतक और 2 अर्द्धशतक के साथ 398 रन बनाकर विराट शीर्ष पर रहे. विराट का भारतीय टीम में पहली बार चयन 2008 में श्रीलंका में हुए आइडिया कप में सचिन एवं सहवाग की ग़ैर मौजूदगी में हुआ था. उस दौरे में विराट का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा, मगर विराट द्वारा खेली गई 37 और 54 रनों की पारी की वजह से भारत सीरीज जीतने में कामयाब रहा. यह भारत की श्रीलंका में उसके ख़िलाफ़ पहली वन डे सीरीज जीत थी. इसके बावजूद विराट को टीम में जगह के लिए किसी प्रमुख खिलाड़ी के घायल होने का इंतज़ार करना पड़ता था. विराट को टीम से बाहर रहना कतई पसंद नहीं था, वह ख़ुद को मिलने वाले अवसर भुनाते रहे और टीम में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहे. विराट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहली छाप युवराज सिंह की ग़ैर मौजूदगी में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2009 में कोलकाता के ईडन गार्डन में गौतम गंभीर के साथ की गई 224 रनों की साझेदारी के दौरान छोड़ी. इस पारी में विराट ने 107 रन बनाए. उनकी इस साहसिक पारी की वजह से भारत 3-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रहा. गौतम गंभीर ने इस मैच का अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार विराट को दे दिया. इस दिन के बाद विराट ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए.

2010 में वरिष्ठ खिलाड़ियों की ग़ैर मौजूदगी में जिम्बाब्वे दौरे के लिए विराट को भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया. इस दौरान विराट ने सबसे कम मैचों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय होने का गौरव हासिल किया. वह 2010 में 25 मैचों में तीन शतकों सहित 995 रन बनाकर दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने. विराट को 2011 के विश्वकप में सुरेश रैना पर वरीयता दी गई. उन्होंने कप्तान धोनी के इस फ़ैसले को सही साबित करते हुए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ शतक ठोंक कर क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी. विराट ने विश्वकप के 9 मैचों में 35.25 के औसत से कुल 282 रन बनाए और भारत को विश्वकप विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. इसके बाद उन्हें टेस्ट टीम में भी जगह मिल गई, मगर वेस्टइंडीज के विरुद्ध कैरेबियाई धरती पर उनका टेस्ट पदार्पण निराशाजनक रहा. इसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैचों में भी विराट को निराशा हाथ लगी, मगर एक दिवसीय क्रिकेट में उनका करिश्माई प्रदर्शन जारी रहा. भारतीय टीम के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे में निराशाजनक प्रदर्शन के बीच वह अपनी काबिलियत साबित करते रहे. स्वालेक स्टेडियम में खेली गई विराट की 107 रनों की शतकीय पारी भी भारत को इंग्लैंड में जीत का स्वाद नहीं चखा सकी. ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत में विराट कोहली की आलोचना हो रही थी. लगातार चार पारियों में नाकाम होने के बाद कोहली को क्रिकेट दिग्गजों की नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की टिप्पणियों का भी शिकार होना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से सबको शांत कर दिया. विराट ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एडीलेड में 116 रनों के साथ अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया. वह इस दौरे में टेस्ट मैचों में शतक बनाने वाले अकेले और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी थे. विराट का चमत्कारिक रूप एक दिवसीय मैचों के दौरान सामने आया. उन्होंने होबार्ट में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 86 गेंदों पर 133 रनों की आतिशी पारी खेली. इस पारी को विराट ने अपनी सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय पारी बताया था. इसी दौरान विराट ने 9 शतकों सहित सबसे कम मैचों में 3000 रन पूरे करने का नया कीर्तिमान भी बनाया.

विराट की सफलता की यह तो केवल शुरुआत थी.ऑस्ट्रेलिया में किए गए धमाकेदार प्रदर्शन का ईनाम विराट को टीम इंडिया की उपकप्तानी के रूप में मिला, जिसका जश्न उन्होंने बांग्लादेश में खेले गए एशिया कप में दो शतक और एक अर्द्धशतक के साथ मनाया. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 183 रनों की ऐतिहासिक पारी ने विराट को देश की आंखों का तारा बना दिया. लोग अब विराट को सचिन एवं राहुल द्रविड़ के उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगे हैं.विराट की परिपक्वता, सफलता के लिए उनकी भूख और आवश्यकता के अनुरूप बल्लेबाज़ी के तरीक़े में बदलाव कर सकने की क्षमता उन्हें अन्य युवा बल्लेबाज़ों से अलग करती है. टेनिस स्टार रोजर फेडरर को अपना आदर्श मानने वाले विराट ने विभिन्न परिस्थितियों और आक्रमण के सामने ख़ुद को अपने खेल से साबित किया है.वो क्रिकेट के कैनवास पर नए भारत की नई तस्वीर बना रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

क्लेनवेल्ट का डोपिंग टेस्ट

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हरफनमौला क्रिकेटर रोरी क्लेनवेल्ट डोपिंग परीक्षण में असफल रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका की एक डोपिंग रोधी संस्था ने कहा कि प्रोटियाज टीम के रोरी क्लेनवेल्ट एक विशेष पदार्थ के परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए. दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी संघ (साका) ने पहले ही कहा था कि क्लेनवेल्ट को एहतियात के तौर पर आगामी घरेलू मैचों से हटा देना चाहिए. साका ने पदार्थ के बारे में ख़ुलासा नहीं किया. वह कोई टिप्पणी करने से पहले इसकी समीक्षा करने की योजना बना रहा है. डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर चेतावनी से लेकर दो साल के प्रतिबंध तक की सज़ा है. क्लेनवेल्ट 29 वर्ष के हैं और उनसे परीक्षण के लिए बी नमूना भी लिया जा सकता है.

संसद की बधाई

सचिन तेंदुलकर द्धारा सौवां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने और बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल द्धारा स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताब बरक़रार रखने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा ने उन्हें बधाई दी. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि तेंदुलकर ने मीरपुर में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वन डे मैच खेलते हुए अपने करियर का 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं. सचिन का यह प्रदर्शन गर्व का विषय है. उन्होंने भारत की नंबर वन बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल को भी स्विस ओपन टूर्नामेंट में लगातार दूसरी खिताबी जीत पर बधाई दी. सायना ने हाल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चीन की शिजियांग वांग को हराकर अपना खिताब बरक़रार रखा.

बटन की जीत

मैक्लारेन के जेंसन बटन ने आस्ट्रेलियाई ग्रां प्री जीतकर रोमांचक ढंग से सत्र की शुरुआत की. दो बार चैंपियन रह चुके सेबेस्टियन विटेल दूसरे स्थान पर रहे. जबकि पोल पोजीशन से शुरुआत करने वाले मैक्लारेन के दूसरे ड्राइवर लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे. 32 वर्षीय बटन ने ग्रिड पर दूसरे स्थान से शुरुआत की, लेकिन स्लो गेटवे का फ़ायदा उठाते हुए टीम के ब्रिटिश साथी लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़कर पहले कार्नर पर बढ़त ले ली और फिर अंत तक यही लय बनाए रखी. रेड बुल के विटेल ने ग्रिड पर छठे नंबर से रेस शुरू की, लेकिन आख़िर में उन्होंने पोडियम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी. स्थानीय ड्राइवर मार्क वेबर चौथे और फेरारी के दो बार के चैंपियन फर्नाडो अलोंसो पांचवें स्थान पर रहे. सत्र की पहली रेस में सहारा फोर्स इंडिया ने भी अपना खाता खोल लिया है. पाल डि रेस्टा ने सत्र की पहली रेस में 10वां स्थान हासिल किया, जिससे सहारा फोर्स इंडिया को एक अंक मिला. टीम के दूसरे ड्राइवर निको हुल्केनबर्ग के लिए यह निराशाजनक शुरुआत रही. वह रेस में एक लैप भी पूरा नहीं कर पाए. हुल्केनसबर्ग ने ग्रिड पर नौवें स्थान से शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआती लैप में ही उनकी कार को पीछे से टक्कर लग गई, जिससे उनका सस्पेंशन क्षतिग्रस्त हो गया और उन्हें रेस से हटना पड़ा. रेस्टा ने ग्रिड में 15वें नंबर से शुरुआत की और पांच स्थान के फ़ायदे से वह शीर्ष 10 में शामिल रहे.

गुरबाज डेवलपमेंट टीम के कप्तान बनेंगे

भारत ने लाहौर (पाकिस्तान) में 9 से 13 अप्रैल तक होने वाले तीन देशों के हॉकी टूर्नामेंट के लिए अपनी डेवलपमेंट टीम भेजने का फ़ैसला किया है, जिसका नेतृत्व राइट हाफ गुरबाज सिंह करेंगे. हालांकि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही शिरकत करेगी. गुरबाज भारत के लिए अब तक 140 मैच खेल चुके हैं, जबकि सेंटर हाफ मनप्रीत सिंह को उपकप्तान घोषित किया गया है. इस टूर्नामेंट में मेजबान पाकिस्तान, भारत और मलेशिया की टीमें शिरकत करेंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आईपीएल क्रिकेटरों पर सेवा कर

सरकार ने ग़ैर मान्यता प्राप्त खेल कार्यक्रमों, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अगले वित्तीय वर्ष से सेवा कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है. इसके अलावा टीवी रियल्टी शो के जज भी इस दायरे में लाए जाएंगे. केंद्रीय सेवा कर बोर्ड (सीबीईसी) के अध्यक्ष एस के गोयल ने कहा, अब आईपीएल जैसी ग़ैर मान्यता प्राप्त खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को 12 फ़ीसदी सेवा कर देना होगा. टीवी रियल्टी शो में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी भी सेवा कर के दायरे में आएंगे. फिल्मी हस्तियों द्धारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर भी कर लगेगा. आईपीएल भारत में खेली जाने वाली सबसे लोकप्रिय प्रोफेशनल प्रतियोगिता है. इसमें हर खिलाड़ी को लाखों रुपये मिलते हैं.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHI/2009/30467

बड़े फिल्म निर्माताओं ने उनके सामने अपनी विशेष दर्जे की फिल्मों में भूमिकाओं की पेशकश की, जिन्हें उन्होंने स्वीकार कर लिया.

सफ़र मुश्किल था

फिल्म चक दे इंडिया कितनी बड़ी हिट हुई थी, हम सभी जानते हैं. इस फिल्म में हॉकी खिलाड़ी की भूमिका निभाई थी दिल्ली की रहने वाली सीमा आज़मी ने. ग्लैमर वर्ल्ड में उनके करियर की शुरुआत हुए ज़्यादा वक़्त नहीं बीता है, इसलिए वह आने वाले दिनों में मिलने वाले चैलेंजेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं. सीमा दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक उपनिषद गंगा में अभिनय कर रही हैं. उपनिषद गंगा में वह सूत्रधार की भूमिका में हैं. चिन्मय मिशन द्धारा निर्मित धारावाहिक उपनिषद गंगा के निर्देशक हैं चाणक्य फेम डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी. सीमा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की ट्रेनिंग ली है, फिर मुंबई आने के बाद उन्हें एक बार मौक़ा मिला डॉ. चंद्र प्रकाश द्विवेदी से मिलने का, जो उस समय धारावाहिक उपनिषद गंगा के लिए ऑडिशन ले रहे थे. इसी दौरान उन्होंने भी ऑडिशन दे दिया और तभी सूत्रधार की भूमिका के लिए चुन ली गईं. उपनिषद गंगा में काम करने के अनुभव को वह ख़ूबसूरत और यादगार बताती हैं. उन्होंने उपनिषद को थोड़ा-बहुत पढ़ा है. वह मानती हैं कि हमारे उपनिषदों में सीखने को बहुत कुछ है. उनका मानना है कि युवा दर्शकों को इस सीरियल को देखना चाहिए, ताकि वे इससे कुछ सीख सकें. इसे देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है. बहुत कम लोग होंगे, जिन्होंने उपनिषद पढ़ा होगा. टीवी पर इसे देखने से कितनी ही नई बातें हमें पता चलेंगी. चिन्मय मिशन और डॉ. साहब दोनों ने मिलकर उपनिषद गंगा जैसा उत्कृष्ट कोटि का धारावाहिक बनाया. आज के समय की यह बहुत बड़ी ही ज़रूरत है कि युवाओं को हम अपनी धरोहर के बारे में बताएं. लोग उन्हें चक दे गर्ल के नाम से ही जानते हैं. इसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी हुई. वह कहती हैं कि शुरू में तो मुझे बहुत ही मुश्किल रही. मेरा परिवार नहीं चाहता था कि मैं फिल्मों में अपना करियर बनाऊं. मैंने थियेटर भी किया है और एनएसडी से भी अभिनय कोर्स किया है. जब मैंने बताया कि मैं मुंबई जाना चाहती हूं तो घर में तूफ़ान आ गया. मेरे पापा ने सालों तक मुझसे बात नहीं की. मैं मुंबई आ गई और सबसे पहले मैंने दीपा मेहता की फिल्म वाटर में काम किया और फिर उसके बाद चक दे के लिए ऑडिशन दिया और मैं चुन ली गई. सीमा को शाहरुख़ ख़ान के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा. वह कहती हैं कि शाहरुख़ बहुत ही अच्छे हैं. मैं बहुत ही ख़ुश हूं कि उनके साथ मेरा अभिनय करियर शुरू हुआ. शूटिंग के दौरान हम सभी एक साथ हॉकी की प्रैक्टिस करते थे. उपनिषद गंगा के अलावा सीमा फिल्म मोहल्ला असी में भी नज़र आएंगी. इसके अलावा उनके पास एक अंग्रेजी फिल्म और कुछ प्रोजेक्ट भी हैं.

उपनिषद गंगा में वह सूत्रधार की भूमिका में हैं. चिन्मय मिशन द्वारा निर्मित धारावाहिक उपनिषद गंगा के निर्देशक हैं चाणक्य फेम डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी . सीमा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की ट्रेनिंग ली है, फिर मुंबई आने के बाद उन्हें एक बार मौक़ा मिला डॉ. चंद्र प्रकाश द्विवेदी से मिलने का, जो उस समय धारावाहिक उपनिषद गंगा के लिए ऑडिशन ले रहे थे.

कंगना की पसंद

कंगना जब फिल्मों में आ रही थीं, तो परिवार के कुछ लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, ख़ासकर उनके पिता और दादा इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे. वह कहती हैं कि असल में मेरे पूर्वज राजस्थान के शाही घराने से हैं. उन्हीं में से कोई हिमाचल में जाकर बस गया था और वहां भी हमारे परिवार का काफ़ी नाम है. मेरे पापा और दादा जी को लग रहा था कि रॉयल फैमिली की लड़की होकर फिल्मों में काम करना हमारी शान के ख़िलाफ़ होगा. लेकिन यहां आकर पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री लड़कियों के लिए बुरी जगह नहीं है, बल्कि यहां पर लड़कियां ज़्यादा आज़ाद हैं. आज़ाद ख्यालों की हिमायती कंगना कहती हैं कि वह अरेंज्ड मैरिज करेंगी या फिर लव मैरिज, यह इस पर डिपेंड करता है कि वह किस लड़के को पसंद करती हैं. अगर उनका पसंद किया लड़का उनके परिवार को नहीं भाया, तो वह अपनी फिल्म तनु वेड्स मनु वाले स्टाइल में घर से भागकर भी शादी कर सकती हैं. उन्हें समझदार, स्मार्ट और हंसमुख जीवन साथी चाहिए. बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत दिखने वाले और शानदार बॉडी वाले मर्द उन्हें पसंद नहीं हैं. हालांकि वह शख़्स फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में हॉट कुंवारे बचे ही नहीं हैं. जो हैं वे किसी न किसी के साथ उलझे हुए हैं. प्रोफेशनल लाइफ में बिजी कंगना को डायरेक्शन का भी ख्याल आया है. उन्होंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें ख़ुद ही पसंद नहीं आई. वह फिर से स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं और जिस दिन उन्हें लगेगा कि वह अच्छी तरह से तैयार हो गई है, तब वह उस पर फिल्म बनाने का काम शुरू कर देंगी. फिल्म फैशन में अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकीं कंगना की इस साल आई लव न्यू ईयर, डेढ़ इश्किया, कृष-2, तनु वेड्स मनु 2 और प्रियदर्शन की तेज़ प्रदर्शित होंगी.

फिक्की रॉकस्टार के नाम रहा

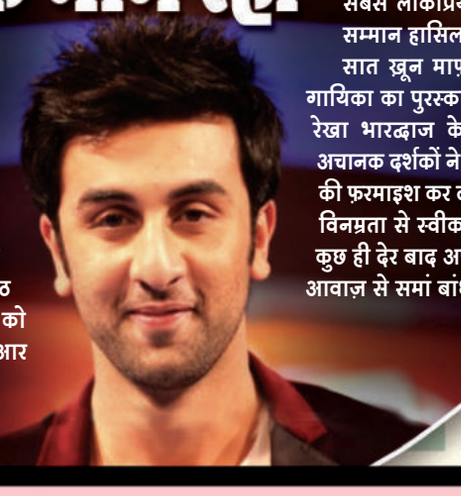

फिक्की फ्रेम्स एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय समारोह है, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव बन चुका है. प्रतिवर्ष होने वाले इस उत्सव में फिल्म, टीवी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स इत्यादि से जुड़े हुए लगभग सभी छोटे-बड़े आर्टिस्ट शामिल होते हैं. इस वर्ष 14 से 16 मार्च तक हुए तीन दिवसीय इस समारोह में पूरी दुनिया से आए दिग्गजों ने हिस्सा लिया. केंद्र सरकार भी खुलकर फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे रही है. सर्विस टैक्स में काफ़ी कटौती की गई है, जिससे इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा पहुंचा है. इस बार इस समारोह में काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए. कई लाइव परफॉर्मेंसेस ने दर्शकों को बांधे रखा. इस समारोह का मुख्य आकर्षण तो अवॉर्ड सेरेमनी ही रहा, जिसमें बॉलीवुड की फिल्म रॉकस्टार ने 4 मुख्य अवॉर्ड लेकर धूम मचा दी. रणबीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इम्तियाज़ अली को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, एआर रहमान को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार और मोहित चौहान को सर्वश्रेष्ठ गायक के पुरस्कारों से नवाज़ा गया. विद्या बालन ने द डर्टी पिक्चर के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता. विद्युत जामवाल को फोर्स के लिए नवोदित अभिनेता और परिणीती चोपड़ा को लेडीज वर्सेस रिकी बहल के लिए नवोदित अभिनेत्री के पुरस्कार दिए गए. ज़ोया अख्तर की ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया. शताब्दी के महानायक अमिताभ बच्चन को सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व होने का सम्मान हासिल हुआ. स्टेज पर जब सात ख़ून माफ़ के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार लेने उषा उत्थप, रेखा भारद्धाज के साथ पहुंचीं तो अचानक दर्शकों ने उनसे गाना गाने की फ़रमाइश कर दी, जिसे उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया और कुछ ही देर बाद अपनी सुरीली आवाज़ से समां बांध दिया.

फिल्मों में शपथ

हुज़ूर, मैं पाक क़ुरआन या गीता पर हाथ रखकर क़सम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, अदालतों में ऐसे संवाद केवल फिल्मों में ही देखे जाते हैं. लेकिन हक़ीक़त में कोई भी शख़्स गीता या क़ुरआन की क़सम खाकर गवाही नहीं देता. यह सब ख़त्म हुए 170 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्मों में आज भी यह सब चल रहा है. लोगों को लगता है कि गवाही देते समय गीता की क़सम खाई जाती है. वास्तविकता की दुनिया में स्थिति थोड़ी भिन्न है. भारतीय दंड संहिता में ओथ एक्ट 1840 में (शपथ अधिनियम) तो है. यह आस्था और निष्ठा पर निर्भर करता है. बयान से पहले गवाह शपथ लेगा तभी वह बयान साक्ष्य माना जाएगा.

लेकिन शपथ की फॉर्म तय नहीं की गई है (यानी शपथ गीता, क़ुरआन, बाइबल या अन्य किस धर्म ग्रंथ की होगी, इसका ज़िक्र नहीं है). गवाही के दौरान सिर्फ़ परमेश्वर के नाम पर क़समें खाई जाती हैं. अंग्रेजों के ज़माने में ज़रूर इस तरह की क़समें खाकर गवाही दी जाती थी. उस समय इसकी काफ़ी अहमियत थी. बाद में धीरे-धीरे इसका प्रचलन ख़त्म हो गया.

1840 में सरकार ने क़ानून बनाकर इसका दायरा बढ़ा दिया कि लोग चाहें तो ईश्वर या अल्लाह की क़सम खाकर गवाही दे सकते हैं, फिर यही सिलसिला चल पड़ा. शुरू में अंग्रेजों ने सोचा कि इस देश के लोग धर्म के प्रति ज़्यादा भावुक हैं, इसलिए गीता या क़ुरआन की क़सम खाकर झूठ नहीं बोल सकते. इस लिहाज़ से इसे लागू किया गया था. लेकिन जल्द ही अंग्रेजों को लगा कि इसका ज़्यादा मतलब नहीं है. इसलिए महज़ परमेश्वर की क़सम खाकर गवाही देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया. एक वकील कहते हैं कि मैंने तो कभी भी गीता या क़ुरआन की क़सम खाकर गवाही देते नहीं देखा. हां, यह ज़रूर है कि फिल्मों में गीता की क़सम खाकर गवाही देने का सिलसिला जारी है. आख़िर फिल्मों में यह बदलाव क्यों नहीं आया. वह कहते हैं, हो सकता है कि फिल्मी निर्देशकों का ध्यान इस ओर नहीं गया हो. ख़बरें छपने के बाद हो सकता है कि बदलाव दिखे और आने वाली फिल्मों में गवाह परमेश्वर की क़सम खाते हुए नज़र आएं.

अब उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाली फिल्मों में गवाह गीता या क़ुरआन की क़सम खाकर गवाही देते नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वैसे ही नज़र आएंगे जैसा कि अदालतों में होता था. 170 साल पहले ख़त्म हो चुका सिलसिला अब फिल्मों में नहीं दिखेगा.

तुम जियो हज़ारों साल

जयाप्रदा : पहला मेहनताना दस रुपये

आंध्र प्रदेश में स्थित राजमंड्री के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जयाप्रदा का जन्म हुआ. नाम रखा गया ललिता रानी. उनके पिता कृष्णा, तेलुगू फिल्म फाइनेंसर थे. उनकी मां नीलवाणी ने उन्हें कम उम्र में ही नृत्य और संगीत कक्षाओं में दाख़िल कर दिया था. जब वह चौदह साल की थीं, तब उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में नृत्य किया. दर्शकों में एक फिल्म निर्देशक भी थे, जिन्होंने जयाप्रदा से तेलुगू फिल्म भूमिकोसम में तीन मिनट के नृत्य प्रदर्शन की पेशकश की. जयाप्रदा हिचकिचाईं, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्हें फिल्म में अपने काम के लिए केवल 10 रुपये दिए गए, पर उन्हें और भी बड़े मौक़े मिले. जब फ़िल्म के ये तीन मिनट के अंश को तेलुगू फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों को दिखाए गए तो उनके सामने प्रस्तावों की बाढ़ आ गई. 1976 में हिट की तिकड़ी के साथ, एक बड़ी स्टार बन गईं. के बालचंदर की अंतुलेनी कथा, जिसमें उनके नाटकीय कौशल को समेटा गया, कं. विश्वनाथ की सिरी सिरी मुव्वा, जिसमें उन्होंने शानदार नृत्य कौशल वाली एक मूक लड़की की भूमिका निभाई, और सीता की शीर्षक भूमिका में बड़े बजट वाली पौराणिक फिल्म सीता कल्याणम, जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा की पुष्टि की. 1977 में उन्होंने अडवी रामुडु में अभिनय किया, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और स्थाई रूप से उन्हें एक स्टार का दर्जा दिया. उन्होंने तेलुगू फिल्मों से बाहर निकलकर, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय किया और उनकी इन सब भाषाओं में फिल्में सफल रहीं. के विश्वनाथ ने फिल्म सिरी सिरी मुव्वा (1976) का पुनर्निर्माण हिंदी में सरगम शीर्षक से किया और 1979 में जयाप्रदा को बॉलीवुड से परिचित कराया. फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई और वह रातों-रात यहां भी स्टार बन गईं. उन्होंने बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पहला फिल्मफेयर नामांकन अर्जित किया, लेकिन अपनी सफलता को भुना नहीं सकीं, क्योंकि वह हिंदी नहीं बोल सकती थीं. इसके तीन साल बाद निर्देशक के. विश्वनाथ ने हिट फिल्म कामचोर (1982) से हिंदी फिल्मों में दोबारा आईं, जहां पहली बार वह हिंदी बोलती नज़र आईं. इसके बाद ही वह प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी (1984) में अमिताभ बच्चन की प्रेमिका के रूप में और के. विश्वनाथ की संजोग (1985) में अपनी चुनौतीपूर्ण दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में दो और फिल्मफेयर नामांकन अर्जित किए. अपने बॉलीवुड फिल्मी करियर के साथ, उन्होंने दक्षिण में के. विश्वनाथ की तेलुगू हिट फिल्म सागर संगमम (1983) जैसी सराहनीय फिल्मों में काम करना जारी रखा. उनके प्रशंसकों में महान भारतीय निर्देशक सत्यजीत रे भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि वह विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हैं. जयाप्रदा ने बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया है, लेकिन कभी सत्यजीत रे के लिए काम नहीं किया. हालांकि रे के साथ फिल्म बनाने का विचार था पर यह संभव नहीं हो पाया. जयाप्रदा ने न केवल अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ सफल जोड़ी बनाई, बल्कि उनकी प्रतिद्धंद्धी श्री देवी के साथ भी उन्होंने लगभग एक दर्जन फिल्मों में अभिनय किया है. फिल्मों ने जयाप्रदा को परंपरागत रूढ़िवादी वर्ग के सिनेमा प्रेमियों का चहेता बना दिया. यह एक ऐसी छवि थी, जो उस समय काम आई, जब उन्होंने एक राजनीतिज्ञ के रूप में अपना नया करियर शुरू किया. 2002 में उन्होंने फिल्म आधार में एक अतिथि भूमिका के ज़रिये मराठी फिल्म उद्योग में क़दम रखा. वह चेन्नई में जयाप्रदा थियेटर की मालकिन भी हैं. 1986 में उन्होंने निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की, जो पहले से ही चंद्रा के साथ विवाहित थे, जिनके साथ उनके 3 बच्चे हुए. इस शादी ने विवादों को जन्म दिया, इसलिए कि नाहटा ने अपनी पत्नी को तलाक़ नहीं दिया और अपनी पहली पत्नी के साथ, जयाप्रदा से शादी करने के बाद भी बच्चे पैदा किए. जयाप्रदा और श्रीकांत के कोई बच्चा नहीं है. जयाप्रदा को 1994 में उनके पूर्व साथी अभिनेता एनटी रामाराव ने तेलुगू देशम पार्टी में शामिल किया. बाद में रामाराव से नाता तोड़ वह चंद्रबाबू नायडू वाले गुट में शामिल हो गईं. 1996 में उन्हें आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया. पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेदों के कारण, उन्होंने तेदेपा को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं तथा 2004 के आम चुनाव के दौरान रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सफल रहीं. फ़िलहाल वह रामपुर से लोकसभा सांसद हैं. राजनीतिक गलियारों में उनका जितना शोर देखा जा रहा है, उतनी ही ख्याति जयाप्रदा ने अपने फिल्मी करियर में भी पाई है. उनके नाम कई फिल्मफेयर पुरस्कार एवं नामांकन दर्ज हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

हाउसफुल 2

साजिद ख़ान की फिल्म हाउसफुल 2 काफ़ी महंगी फिल्म है और इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि फिल्म की शूटिंग यूके के बुर्घले हाउस के बाहर की गई है. यहीं हॉलीवुड फिल्म प्राइड एंड प्रीज्युडिस की शूटिंग भी हुई थी. इसकी वजह यह है कि इस फिल्म का एक किरदार बिलियनेयर है. उसे धनपति दिखाने के लिए काफ़ी बड़े हाउस की ज़रूरत थी. उन्होंने कई दिनों तक इसकी तलाश की और फिर इस हाउस को फाइनल किया गया. यह 400 साल पुराना है, जिसकी बनावट काफ़ी आर्कषक है. चूंकि यह एक ऐतिहासिक भवन है, इसलिए इसके अंदर शूटिंग करने की इजाज़त टीम को नहीं मिली, लेकिन साजिद ने इसके अंदर जाकर थ्री डी इमेज लेने की इजाज़त ले ली और मुंबई में सेट पर वैसा ही इंटीरियर करवाया. फिल्म के शुरुआती सीन में इस हाउस के बाहर दो हेलीकॉप्टर दिखाए गए हैं. साजिद नाडियावाला ने हाउसफुल 2 के सिर्फ़ एक सेट पर 5 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं. बुर्घले हाउस की प्रतिकृति को मुंबई के फिल्मस्तान स्टूडियो में बनाने में 5 करोड़ रुपये ख़र्च हुए. साजिद नाडियाडवाला ने पहली बार इतना बड़ा सेट नहीं बनाया है. इससे पहले फिल्म मुझसे शादी करोगी के लिए भी उन्होंने पूरे शहर को सेट के रूप में बनाया था. सिर्फ़ यही नहीं, इस फिल्म की ख़ास बात यह भी है कि फिल्म हाउसफुल 2 में शामिल सभी जानवर नक़ली हैं. हाउसफुल के शुरुआती दृश्य जारी कर दिए गए हैं. इस श्रृंखला की पहली फिल्म की तरह इसके भी कुछ दृश्यों में जानवर दिखाई देते हैं. निर्देशक साजिद ख़ान ने कहा है कि उनके लिए फिल्म में जानवरों का इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बच्चों को वे पसंद आते हैं. मज़ेदार बात यह है कि रितेश देशमुख और अक्षय कुमार फिल्म में मगरमच्छ के दांत लगाए हुए दिखेंगे. यह हंसाने वाली फिल्म है और बच्चे इसे पसंद करेंगे. इस फिल्म में मुख्य कलाकार ज़रीन ख़ान, असिन, जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख, ऋषि कपूर, बोमन ईरानी आदि हैं. फिल्म का गाना अनारकली डिस्को चली पहले से ही पॉपुलर हो चुका है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 02 अप्रैल-08 अप्रैल 2012

www.chauthiduniya.com

सिंचाई परियोजनाओं से खिलवाड़

प्रवीण महाजन

राज्य व केंद्र सरकार का विदर्भ के प्रति रवैया कितना सहानुभूति भरा रहता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे विदर्भ के जिन विकास कार्यों के लिए जब भी किसी निधि का आवंटन करती है, तो उनका गुमान कुछ इस तरह रहता है कि मानों उन्होंने क्षेत्रवासियों के ऊपर बहुत बड़ा अहसान कर दिया हो. विदर्भ के दर्जनों बड़े, मध्यम और लघु प्रकल्पों का निर्माण कार्य निधि के अभाव में अटका हुआ है, जिस वजह से क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है. कई प्रकल्पों के विस्थापितों का पुनर्वास भी नहीं हो पाया है. कहीं प्रकल्प अधूरा है, तो कहीं नहरों का कार्य नहीं हो पाया है. इसके निर्माण के लिए करोड़ों रुपये की ज़रूरत है, लेकिन हर बार ज़रूरत के हिसाब से निधि न मिलने से जहां निर्माण कार्य समय पर नहीं हो रहा है. इस बेवजह की देरी से लागत भी बढ़ती जा रही है. इस परिस्थिति में केंद्रीय बजट 2012-13 में भी विदर्भ क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सघन सिंचाई विकास कार्यक्रम 2012-13 के वास्ते 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, इस निधि से विदर्भ का कितना भला होगा? इस निधि का कहां-कहां उपयोग किया जा सकेगा? इन सवालों पर विचार करने के लिए वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के पास न बजट पेश करने के पहले वक्त था और न अब है. हक़ीक़त यह है कि विदर्भ के सिर्फ नागपुर की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के लिए क़रीब 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की निधि की आवश्यकता है, जबकि 300 करोड़ रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दिए गए हैं. इसलिए विदर्भ के लिहाज़ से उक्त रक़म कम है.

विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल के अंतर्गत कुल 1089 प्रकल्प हैं, जिनमें से 767 का निर्माणकार्य पूरा हो चुका है. 320 निर्माणाधीन हैं और 2 प्रशासकीय मान्यता मिलने की राह पर हैं. निर्माणाधीन 320 प्रकल्पों की अनुमानित लागत राशि 50382 करोड़ रुपये आंकी गई है और फरवरी 2012 तक 20015 करोड़ रुपये ख़र्च हो चुके हैं. यानि पिछले वर्ष मार्च तक 30367 करोड़ रुपये और लागत राशि लगनी बाकी थी. इन प्रकल्पों की कुल सिंचाई क्षमता 15,62,127 हेक्टर है, जबकि जून 2011 तक मात्र 4,08,460 हेक्टर सिंचाई क्षमता ही हासिल की जा सकी है. अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार के बजट में, जो 300 करोड़ रुपये की निधि का आवंटन किया गया है वे विदर्भ के किसान आत्महत्या के लिए चर्चित पांच ज़िलों के निर्माणाधीन प्रकल्पों में कहां ख़र्च किया जाएगा? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ पूरे विदर्भ में निर्माणाधीन 320 प्रकल्पों में से 60 का निर्माण कार्य पूर्ण होने के नज़दीक हैं, 223 प्रकल्पों का निर्माण कार्य निधि की आपूर्ति के अनुसार चल रहा है और 37 प्रकल्प वन क़ानून के कारण अटके हुए हैं. जहां तक पूर्व विदर्भ के सिंचाई अनुशेष भरने की बात है, तो जब तक जिगांव, बुलढाना, निम्न पैनगंगा यवतमाल और आजनसरा बैरेज वर्धा को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शामिल नहीं किया जाता है तब तक अनुशेष का भरना असंभव ही लगता है. बहरहाल उक्त तीनों प्रकल्प निर्माणाधीन हैं.

केंद्रीय बजट में निधि का प्रावधान करते समय विदर्भ के गोसीखुर्द, बावनथड़ी, अपर वर्धा, निम्नवर्धा, निम्न पैनगंगा, तुलतुली, दिंडोरा बैराज, काटेपूर्णा, जिगांव और एकबुर्जी जैसे महत्वपूर्ण प्रकल्पों के निर्माणकार्य में तेज़ी लाने के लिए केंद्र को अपने बजट में उन्हें शामिल कर निधि आवंटन करना ज़रूरी है. भंडारा ज़िले में निर्माणाधीन गोसीखुर्द प्रकल्प (इंदिरा सागर) विदर्भ का सबसे महत्वाकांक्षी प्रकल्प है. पिछले 24-25 वर्ष से इसका निर्माण कार्य चल रहा है. फरवरी 2009 में इसे राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित किया गया. इसके निर्माण कार्य पर अब तक 6000 करोड़ रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. इसकी राइट साइट की 107 किलोमीटर लंबी नहर का कार्य अब भी अधूरा है. लेफ्ट साइट की 23 किलोमीटर लंबी नहर का कार्य पूरा हो गया है. इसकी शाखा नहरों का निर्माणकार्य, पुनर्वास का काम अधूरा है. इसके बावजूद अभी भी क़रीब 9500 करोड़ रुपये की ज़रूरत पड़ेगी. भंडारा ज़िले के ही बावनथड़ी (राजीवसागर) प्रकल्प भी अपने पूरे होने की राह ताक रहा है. मुख्य अड़चन यहां पुनर्वास की है. निम्नचूलबंद प्रकल्प निधि के अभाव में, हालेडोह मध्यम प्रकल्प मान्यता के अभाव में तो भिमलकसा मध्यम व सोनकुंड लघु प्रकल्प का निर्माण कार्य वन क़ानून के कारण अटका हुआ है. विदर्भ का दूसरा सबसे महत्वाकांक्षी प्रकल्प अमरावती ज़िले का अपर वर्धा प्रकल्प है. वर्धा डायवर्सन का काम रूका हुआ है. इस वर्ष अमरावती ज़िले के प्रकल्पों के लिए 470.45 करोड़ रुपये की निधि की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने वर्ष 2011-12 में केवल 180.81 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान किया था. वर्धा ज़िले में स्थित निम्नवर्धा प्रकल्प को जब 9 जनवरी 1981 को प्रशासकीय मान्यता दी गई थी, तब उसकी अनुमानित लागत मात्र 48.08 करोड़ रुपये बताई गई थी. हालांकि आर्वी तहसील की यह योजना शासन की उदासीनता के कारण उपेक्षित है और वर्तमान में उसकी लागत बढ़कर 2365.85 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यवतमाल ज़िले की निम्न पैनगंगा सिंचाई प्रकल्प पीड़ित किसानों के पुनर्वास के कारण अटकी हुई है. पहले पुनर्वास बाद में प्रकल्प का निर्माण का कार्य करने की मांग पीड़ितों ने शासन के सामने की है. इसके निर्माण होने पर महाराष्ट्र के हिस्से 41.12 टीएमसी पानी आना है, लेकिन अब तक सरकार पीड़ितों की समस्याओं का समाधान गंभीरता से करने का कोई प्रयास नहीं किया है. गढ़चिरोली ज़िले में बड़ी मात्रा में वनसंपदा होने के कारण कई प्रकल्प अटके हुए हैं. तुलतुली प्रकल्प का निर्माण कार्य 1983 से बंद पड़ा है. करवाफा प्रकल्प का कार्य भी वन क़ानून के कारण रूका हुआ है. चेन्ना प्रकल्प कार्य भी वर्ष 1983 से बंद है. पोहार प्रकल्प की भी यही कहानी है. चंद्रपुर ज़िला की हुमन प्रकल्प, वरोरा तहसील में स्थित दिंडोरा बैरेज प्रकल्प और चिमूर तहसील के तलोधी नाइक गांव के पास भदगा नाला पर बनने वाला लघु प्रकल्पों का निर्माण कार्य अब तक वन क़ानून के कारण शुरू नहीं हो पाया है. ज़िले में भविष्य में 5,21983 हेक्टेयर की सिंचाई के उद्देश्य से बड़े, मध्यम और लघु प्रकल्पों को मिलाकर कुल 2,819 प्रकल्प स्वीकृत हैं, लेकिन निधि के अभाव और वन क़ानून के कारण कुछ का कार्य शुरू ही नहीं हुआ है, तो कुछ का निर्माण कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन बंद पड़ा है. गोंदिया ज़िला में मध्यम प्रकल्पों पर अब तक 981 करोड़ 32 लाख 18 हज़ार रुपये व्यय हो चुके हैं. ज़िले के पश्चिम भाग में स्थित 12 प्रकल्पों का निर्माण कार्य रूका हुआ है. निर्माण कार्य को गति देने के लिए 85 करोड़ रुपये की ज़रूरत है. इसके लिए सिंचाई विभाग द्वारा मशक्कत करने के बाद भी निधि नहीं मिली.अकोला ज़िले के 35 प्रकल्पों में से नेरधामना, उमा व काटेपूर्णा प्रकल्प का कार्य मंद गति से चल रहा है. पूर्णा नेरधामना बैराज 2, नेरधामना प्रकल्प के पूरा होने पर 6954 हेक्टर और काटेपूर्णा बैराज के पूरा होने पर 4,137 हेक्टर क्षेत्र के सिंचाई क्षेत्र में शामिल होने की संभावना है. उमा बैराज के पूरा होने पर 5,510 हेक्टर सिंचाई क्षेत्र बढ़ने की संभावना है, लेकिन सभी प्रकल्प निधि उपलब्ध न होने से निर्माण कार्य की बाट जोह रहा है. बुलढाना ज़िले के 4 बड़े प्रकल्प जिगांव, खडकपूर्णा, पेनटाकली व वाण, 8 मध्यम प्रकल्प, 75 लघु प्रकल्प होने के बाद भी यहां सिंचन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है. इन प्रकल्प की कुल सिंचाई क्षमता 2.23 लाख हेक्टर होने के बावजूद वर्तमान में केवल 1.70 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र आता है. मध्यम प्रकल्पों में नलगंगा, ज्ञानगंगा, मन, मस, तोरणा, उतावली, पलढग, कोराडी प्रकल्पों का समावेश है. इनमें से कुछ का काम शुरू है तो कुछ का निधि के अभाव में रूका हुआ है. वाशिम ज़िले के कुल 72 प्रकल्पों के लिए 859.42 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. वाशिम ज़िले की दशा ऐसी है कि यहां जितने क्षेत्र में उपज ली जाती है उसका मात्र 13 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचन क्षेत्र में आता है. यहां एक मध्यम प्रकल्प के साथ 84 लघु प्रकल्प है. यहां के सभी प्रकल्प पूरे होने पर 5,12000 हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा. ज़िले की एकबुर्जी सिंचन प्रकल्प की ऊंचाई एक मीटर बढ़ाने के साथ ही जयपुर, अकोला, व अन्य चार प्रकल्पों का काम शुरू हुआ था, लेकिन निधि के अभाव में अब वे ठप पड़े हैं. अब विदर्भ के सभी ज़िलों में स्थित प्रकल्पों की वर्तमान परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद सवाल यह खड़ा होता है कि केंद्र सरकार ने, जो 300 करोड़ रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दिया, एआईबीपी और गोसीखुर्द को जो निधि आवंटित की जाएगीं, उसके बाद राज्य सरकार को अपने बजट में उक्त प्रकल्पों के निर्माणकार्य को गति देने के लिए निधि की व्यवस्था करनी होगी. निधि आवंटन करने, उनको समयबद्ध निधि उपलब्ध कराई जाए ताकि समय से उनका काम पूरा हो. उसका फ़ायदा किसानों को मिलना शुरू हो. फिलहाल तो प्रकल्पों की संख्या को देखकर यही लगता है कि सरकार विदर्भ के किसानों की हालत पर बहुत चिंतित है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि निधि उपलब्ध कराने के मामले में राजनीति आड़े आ जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

हक़ीक़त यह है कि विदर्भ के सिर्फ नागपुर की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के लिए क़रीब 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की निधि की आवश्यकता है, जबकि 300 करोड़ रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दिए गए हैं. इसलिए विदर्भ के लिहाज़ से उक्त रक़म ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है. विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल के अंतर्गत कुल 1089 प्रकल्प हैं, जिनमें से 767 का निर्माणकार्य पूरा हो चुका है. 320 निर्माणाधीन हैं और 2 प्रशासकीय मान्यता मिलने की राह पर हैं. निर्माणाधीन 320 प्रकल्पों की अब तक लागत राशि 50382 करोड़ रुपये आंकी गई है और फरवरी 2012 तक 20015 करोड़ रुपये ख़र्च हो चुके हैं. यानि पिछले वर्ष मार्च तक 33035 करोड़ रुपये और लागत राशि लगनी बाकी थी. इन प्रकल्पों की कुल सिंचाई क्षमता 15,62,127 हेक्टर है, जबकि जून 2011 तक मात्र 4,08,460 हेक्टर सिंचाई क्षमता ही हासिल की जा सकी है.

छत्रपति शिवाजी पर राजनीति किए जाने पर जनाक्रोश भड़कने की आशंका होते ही सरकार ने फिर पलटी खाई और कहा कि शिवाजी का स्मारक तो अरब सागर में ही बनेगा.

शिवसेना ने झूठा वायदा करके मनसे के सहयोग से अपना महापौर तो बिठा लिया, लेकिन अब उसके सहयोग के बिना उसकी राह मुश्किल हो चली है.

महाराष्ट्र हलचल

[illegible]

कपास पर राजनीति

पणन महासंघ को बचाने की क़वायद

कपास पणन महासंघ राज्य की जनता व किसानों के लिए सफ़ेद हाथी ही साबित हो रहा है. इस महासंघ के साढ़े चार सौ के क़रीब अधिकारी-कर्मचारियों की पलटन के वेतन-भत्तों पर हर साल 12-15 करोड़ रुपये ख़र्च हो रहे हैं, जबकि उनके पास कार्य करने के लिए कुछ नहीं है.

राज्य सरकार ने महासंघों के नाम पर कई हाथी पाल रखे हैं. इन महासंघों में कहने को तो उसके पदाधिकारियों का चयन किया जाता है चुनाव प्रक्रिया द्वारा, लेकिन राजनीतिक आकाओं के आशीर्वाद के बिना उनका अस्तित्व क़ायम रहना असंभव होता है. इसके बावजूद जनता की गाढ़ी कमाई इन महासंघों को पालने में न्यौछावर कर दी जाती है. इन महासंघों में कर्मचारियों की फौज़ तो रहती है, लेकिन उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं रहता है. वहीं दूसरी ओर जिन विभागों पर सतत काम का बोझ बना रहता है, वहां अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी रहने से समय पर कार्य नहीं हो पा रहे हैं. इससे कई बार महासंघों के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जा चुके हैं. बावजूद इसके सरकार इन्हें क़ायम किए हुए है. उदाहरण के तौर पर कपास का एकाधिकार सरकार ने ख़त्म कर दिया है, बावजूद इसके कपास पणन महासंघ को पालने पर सरकार हर साल करोड़ों रुपये लुटा रही है. हाल ही में केंद्र सरकार ने कपास ख़रीदी पर पाबंदी का जो निर्णय लिया था, उसकी मुख्य वजह थी नाफेड को लाभ पहुंचाने की ख़ातिर राज्य के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की भूमिका. ऐसी चर्चा है कि कपास पणन महासंघ के अस्तित्व को बचाने के लिए उक्त निर्णय दवाब डालकर करवाया गया था. केंद्र सरकार को अपना यह निर्णय उग्र विरोध के कारण वापस लेना पड़ा. कपास पणन महासंघ राज्य की जनता व किसानों के लिए सफेद हाथी ही साबित हो रहा है. इस महासंघ के साढ़े चार सौ के करीब अधिकारी-कर्मचारियों की पलटन के वेतन-भत्तों पर हर साल 12-15 करोड़ रुपये ख़र्च हो रहे हैं, जबकि उनके पास कार्य करने के लिए कुछ नहीं है. इस बीच यह भी चर्चा थी कि सरकार कपास पणन महासंघ को बर्ख़ास्त करने वाली है. हालांकि सरकार पणन महासंघ को अब तक बनाए हुए है. कपास उत्पादकों को भी पणन महासंघ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है. इसलिए अब उसकी उपयोगिता न होते हुए उसे बनाए रखना, समझ से परे है. पिछले दिनों पणन महासंघ के हुए चुनाव के बाद भी डॉ. राजेंद्र हिरानी का एकछत्र राज क़ायम है. यह सर्वविदित है कि कपास उत्पादकों के हितों के लिए संचालित एकाधिकार योजना को बंद हुए काफी समय बीत चुका है. एकाधिकार योजना के ख़त्म होने के बाद पणन महासंघ केंद्र सरकार के नाफेड नामक संस्था का एजेंट बनकर रह गया है. नाफेड के लिए पणन महासंघ किसानों से जो कपास ख़रीदता है उसके बदले उसे कमीशन मिलता है. कपास ख़रीदी के लिए केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, किसानों से उसी दर पर पणन महासंघ द्वारा नाफेड के लिए कपास ख़रीदी करना बाध्यकारी है. पिछले तीन माह से कपास के सरकारी भाव से अधिक बाज़ार भाव होने से संघ द्वारा बोंड तक की ख़रीदी नहीं की गई. पिछले कपास ख़रीदी के मौसम में सरकारी नीतियों के कारण नाफेड ने ख़रीदी में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया था. केंद्र सरकार ने पिछले दिनों नाफेड को फ़ायदा पहुंचाने और कपास पणन महासंघ को जीवंत रखने के लिए कपास निर्यात पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी. इस निर्णय पर जब कपास उत्पादकों ने उग्र विरोध जताया और राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई तो केंद्र सरकार को विवश होकर अपना निर्णय बदलना पड़ा. इस पूरी क़वायद में राज्य से लेकर केंद्र तक राजनीतिक खेल नेता खेलते रहे. भला ऐसे कैसे हो सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कपास की मांग बढ़ रही हो और क़ीमत 7000 रुपये से ऊपर हो और सरकार उस पर पाबंदी लगाने का मूर्खतापूर्ण निर्णय ले. वह भी जिस सरकार का मुखिया खुद एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हो. यह बात कुछ हजम नहीं होती है. यह राजनीति इसलिए हो रही थी कि राज्य के पणन महासंघ को बचाना है, जिसकी शाखाएं महाराष्ट्र के बाहर गुजरात, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में फैली हुई हैं. पणन महासंघ के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और कार्यालयीन ख़र्चों पर राज्य सरकार 15 से 20 करोड़ रुपये हर साल न्यौछावर कर रही है. कपास पणन महासंघ पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? इस सवाल का उत्तर उसी राजनीति में छुपा हुआ है, जिसके तहत कपास निर्यात पाबंदी का निर्णय लेने के बाद वापस लिया गया. बहरहाल केंद्र सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए अपने निर्णय को वापस ले लिया है, लेकिन अब पणन महासंघ का संकट बरकरार है. यदि केंद्र सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती तो पणन महासंघ को काम मिल गया था और वह पुनः कपास ख़रीदी शुरू कर देता, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई. चूंकि पिछले तीन वर्षों से कपास ख़रीदी बंद है, उसके पास न काम है और न आय का कोई अन्य जरिया. इन हालात में पणन महासंघ के पदाधिकारियों को अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी है. इन हालात पर विचार करने के लिए पणन महासंघ के पदाधिकारियों की मुंबई बैठक हुई. बैठक में एक बात सभी ने स्पष्ट रूप से रखी कि नाफेड का एजेंट बनकर काम करना भविष्य में संभव नहीं है. कपास पाबंदी का निर्णय भी लागू नहीं किया जा सकता है. ऐसे में कर्मचारियों की फौज़ को पालने और काम देने के लिए पर्यायी आय के माध्यम तलाशना अति आवश्यक है. यह भी विचार किया गया कि व्यवसायिक आधार पर पणन महासंघ कपास द्वारा ख़रीदी-बिक्री का कार्य भविष्य में कर सकता है क्या? इसके लिए महासंघ का कार्यकारी मंडल राज्य व केंद्र दोनों सरकारों के मुखियाओं से मिलकर रास्ता निकालने का अनुरोध करने वाला है. पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि चूंकि उसका नेटवर्क महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में व्यापक स्तर पर फैला है, इसलिए केंद्र से महासंघ को अपनी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने देने का अनुरोध भी करेगा, ताकि वह कपास ख़रीदी का कार्य व्यवसायिक स्तर पर कर सके.

feedback@chauthiduniya.com

साईं के घर में राजनीति

धार्मिक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप ख़त्म हो

[illegible]

जिन धार्मिक स्थलों में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और भरपूर चढ़ावा आता है, वहां राजनेता अपने हित ढूंढ ही लेता है. फिर भला शिर्डी के साईं बाबा का घर इससे अछूता कैसे रह सकता है. [illegible]

[illegible] अपने हाथ में ले लेगी. अब कौन राजनीतिक दल या राजनेता संपूर्ण विश्व से श्रद्धालुओं की शिर्डी में उमड़ने वाली भीड़ और करोड़ों रुपये के कारोबार की वजह से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाले प्रचुर लाभ को देखते हुए छोड़ना चाहेगा. ऐसे संस्थानों के विश्वश्त मंडल में शामिल होने के लिए तो राजनीतिज्ञों के अलावा अन्य क्षेत्र के लोगों में प्रतिस्पर्धा होती रहती है. इसलिए साईं बाबा के इस संस्थान के विश्वस्त मंडल में शामिल होने के लिए पुनः दौड़ शुरू होने की आशंका व्यक्त की जा रही है. इसका साफ मतलब है कि साईंबाबा के घर में कब्ज़े के लिए नए सिरे से राजनीति शुरू हो रही है. राज्य में सत्तारूढ़ दल कभी नहीं चाहेगा कि इतने कमाऊ संस्थान से उसका वर्चस्व ख़त्म हो जाए. लिहाज़ा यहां भी विश्वस्त मंडल में जगह बनाने की जबरदस्त होड़ होगी. वर्तमान घटनाक्रम को मद्देनज़र रखते हुए मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर और शिर्डी के साईं बाबा संस्थान राज्य सरकार के खाते में आने के बाद सिद्धि विनायक मंदिर राकांपा और कांग्रेस के हिस्से में साईं संस्थान आने की संभावना बनी हुई है. दोनों संस्थानों में दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का बंटवारा हो गया है. इसलिए सांईबाबा संस्थान में कांग्रेस का अध्यक्ष और राकांपा का उपाध्यक्ष होना तय माना जा रहा है. हालांकि, सबकी नज़रें लगी है सरकार के अगले क़दम की ओर, कि सरकार आखिर नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू कब करती है. यदि मुंबई में सत्ता के गलियारों में हो रही चर्चाओं को मानें तो सरकार ने नए सदस्यों को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके अनुसार साईं संस्थान के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के सायण और उपाध्यक्ष पद राकांपा के वरिष्ठ नेता शंकरराव कोल्हे को दिए जाने की संभावना जताई जा रही है. यह भी कहा जा रहा है कि राकांपा ने भविष्य में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर और शिर्डी के साईं संस्थान के विश्वस्त मंडल का नेतृत्व अदल-बदल कर अपने पास रखने का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा है.

एशिया का सबसे बड़ा प्रसालय संस्थान ने 40 करोड़ की लागत से बनाया, जिसमें एक लाख श्रद्धालुओं के भोजन करने की व्यवस्था है. इसके लिए के.वी. रमणी नामक साई भक्त ने एक अरब रुपया दान दिया था. इस दान राशि से संस्थान ने 15 हज़ार श्रद्धालुओं के ठहरने हेतु भक्ति निवास बनाया है. एक अरब 10 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया है, जिसमें राज्य में हृदय रोगियों का सर्वाधिक उपचार किया जाता है और यह अस्पताल ग़रीबों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है. हाईटेक गार्डन का कार्य शुरू है. इतने भारी भरकम बजट वाले साईं संस्थान के विश्वस्त मंडल के सदस्यों को काफी महत्व हासिल हो जाता है. वैसे भी देश के सभी मलाईदार धार्मिक संस्थानों में राजनीतिक वर्चस्व हासिल करना हर राजनीतिक दल का शगल बन गया है. ऐसे संस्थानों में आर्थिक कदाचार होने की घटनाएं भी घटित होती रहती हैं. अब सवाल यह कि साईं संस्थान में अवधि ख़त्म होने के बाद भी साढ़े चार साल तक, जो विश्वस्त मंडल क़ायम रहा है, उसके कार्यकाल की जांच-पड़ताल होगी या नहीं? बरहहाल, सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है कि, वह धार्मिक संस्थानों का कामकाज पारदर्शी तरीके से करना चाहती है या उसे भी राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहती है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री के कोटे पर उठा सवाल

राज्य में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. यहां मंत्री-संतरी परेशान हैं. सरकार भी है और उसके मंत्री भी काम कर रहे हैं. इसके बावजूद सरकार का सिरदर्द कम नहीं हो रहा है. अदालती हथौड़ा दनादन चल रहा है. आए दिन नए-नए मामले अदालत के सामने आते हैं और सरकार को सफाई के लिए हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता है, लेकिन सरकार भी पूरी तरह ढीठ हो गई है. वह गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की बजाय उस पर पर्दा डालने का प्रयास करती है. इसी का नतीजा है कि अब राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के कोटे पर ही सवाल खड़े किए जाने लगे हैं. वह भी नेताओं के पुत्र-पुत्रियों व रिश्तेदारों को मुख्यमंत्री कोटे से मनमाने तरीके से विविध सोसायटियों में फ्लैट आवंटन किए जाने का. यह एक नई परेशानी सरकार के माथे आ गई है. इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को अपनी गृह दशा सुधारने के लिए कोई उपाय योजना पंडितों से पूछना चाहिए, ताकि इस बुरे वक्त का तोड़ निकाला जा सके. यदि तोड़ नहीं निकाला गया, तो भविष्य में सिरदर्द बढ़ सकता है.

मुंबई हाईकोर्ट ने केतन तिरोडकर की याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से सीधा सवाल किया है कि मुख्यमंत्री कोटे से नेताओं के परिवार के दो-दो सदस्यों को फ्लैट क्यों दिए गए हैं? यह किस आधार पर दिए गए हैं? इस सवाल से सरकार की घिग्घी बंधना स्वाभाविक है. पहले से ही आदर्श सोसायटी का भूत जब तब जाग उठता है. पिछले दिनों ही कोर्ट ने आदर्श सोसायटी घोटाले मामले में सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि, जब आपके पास सबूत है तो आरोपियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं? तभी से इस घोटाले में आरोपी नेताओं और अफसरों को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है. ऊपर से अब मुख्यमंत्री के कोटे की भी जांच-परख हो सकती है. याचिका की सुनवाई के दौरान केतन तिरोडकर ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री के कोटे से ज्यादातर फ्लैट नेताओं के परिवार के दो-दो सदस्यों को आवंटित किए गए हैं. किस आधार पर एक ही नेता के एक से अधिक पारिवारिक सदस्य व रिश्तेदारों को फ्लैट का आवंटन किया गया है? इस सवाल का जबाव सरकार द्वारा अब तक नहीं दिया गया है. याचिकाकर्ता द्वारा सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर मुंबई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पी.बी. मजूमदार व न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री कोटे से नेताओं के दो-दो परिजनों को फ्लैट आवंटित किए जाने पर नाराज़गी जताते हुए उक्त सवाल सरकार से किया था. खंडपीठ ने सरकार से कहा कि आखिर कैसे व किस नियम के आधार पर एक ही परिवार के दो सदस्यों को फ्लैट दिए गए? सरकार इस सवाल पर अपना रुख स्पष्ट करे. याचिकाकर्ता तिरोडकर का कहना था कि मुख्यमंत्री कोटे से सभी पार्टी के नेताओं की संतानों व रिश्तेदारों को मनमाने तरीके से फ्लैट का आवंटन किया गया है. इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर के बेटे व बेटी अपूर्वा, उद्योग मंत्री नारायण राणे के भाई व भतीजी, विधानसभा में विरोधी दल के नेता एकनाथ खड़से के बेटे तुषार, शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के दो साले, सार्वजनिक निर्माणकार्य मंत्री छगन भुजबल और भतीजा विधायक समीर भुजबल, पूर्व विधायक सुरेश गंभीर के बेटे व बेटी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की सास भगवती शर्मा का नाम शामिल हैं. ये तो कुछ उदाहरण हैं, इनके अलावा भी कई नेताओं के पुत्र-पुत्री व अन्य रिश्तेदारों को कोटे से फ्लैट का आवंटन किया गया है. इन सारे नामों को सुनकर खंडपीठ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने कोटे से फ्लैट देने में कोई पक्षपात नहीं किया है. सत्तापक्ष व विपक्ष के लोगों को समान रूप से वितरण किया गया है.

कोर्ट ने आदर्श सोसायटी घोटाले मामले में सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि, जब आपके पास सबूत है तो आरोपियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं? तभी से इस घोटाले में आरोपी नेताओं और अफसरों को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है. ऊपर से अब मुख्यमंत्री के कोटे की भी जांच-परख हो सकती है.

अदालत में फ्लैट आवंटन के मामले पर नेताओं के पुत्र-पुत्रियों व रिश्तेदारों के प्रति मुख्यमंत्री द्वारा उदारता बरते जाने पर कहा- क्या कहा जा सकता है? विधानसभा-विधान परिषद के अंदर व बाहर विपक्ष के नेता जहां सरकार की जमकर आलोचना करते हैं. उनको भ्रष्ट बताते हैं, लेकिन बात जब अपने फ़ायदे की आती है, तो सरकार के कदाचार में शामिल होने में कोई हर्ज नहीं समझा जाता है. अदालत में हुए इस खुलासे से यही प्रतीत होता है कि बाहर विरोध और अंदर हम भाई-भाई, सब मिल-बांटकर कर खाएंगे का परिदृश्य सामने नज़र आता है. इन हालात में जनता किस पर विश्वास करे? यहां तो चोर-चोर मौसेरे भाई का रिश्ता निभाते हैं. अब देखने वाली बात यह है कि अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अदालत के सवाल का जबाव क्या दिया जाता है? मंत्रालय में आजकल सरकार पर अदालत की वक्रदृष्टि पड़ने को लेकर चर्चा है कि सरकार को अपनी गृहचाल को दुरुस्त करने के लिए पूजा-पाठ करा लेनी चाहिए, क्योंकि आए दिन अदालत में कोई न कोई खुलासा हो रहा है, जिससे सरकार का संकट काफी बढ़ गया है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

उद्धव की उलझन

शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे खुद को भले ही राजनीति का बड़ा खिलाड़ी समझते हों, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ पर तरस आता है. उनके राजनीतिक बचकानेपन से शिवसेना की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. उनके प्रति शिवसेना की सहयोगी पार्टी भाजपा का विश्वास भी कम होता जा रहा है. ग़ौरतलब है कि ठाणे महानगर पालिका में शिवसेना को सत्ता हासिल करने के लिए मनसे की सहायता की ज़रूरत थी. इसके लिए उद्धव ने भाजपा नेताओं को राज ठाकरे से बात करने को मध्यस्थ बनाया. उद्धव ठाकरे ने भाजपा से वायदा किया था कि यदि मनसे ने ठाणे मनपा में शिवसेना का साथ दिया, तो नासिक में मनसे का महापौर बनाने में हम उसका साथ देंगे. हालांकि ठाणे में शिवसेना के सत्ता में आने के बाद उद्धव का मन बदल गया और नासिक में उन्होंने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पहला महापौर बनने में मदद देने से इंकार कर दिया. इस तरह उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से वादाख़िलाफी करने के साथ की भाजपा को भी नाराज कर दिया. हालांकि नासिक की सत्ता हासिल करने में राज ठाकरे को कोई मुश्किल नहीं हुई. भाजपा को साथ लेकर राज ने नासिक मनसे का पहला महापौर बिठाने में कामयाब रहे. नासिक में मनसे का साथ देने से उद्धव ठाकरे अब भाजपा से नाराज़ हैं और उसे अब सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन कैसे सिखायें? यह प्रश्न ही उनकी उलझन है. यदि वे मनसे का साथ देने पर भाजपा से गठबंधन तोड़ने का फ़ैसला लेते हैं तो उनके हाथ से 21000 करोड़ की तिजोरी की चाबी भी जाने का ख़तरा है. मुंबई महानगर पालिका में भाजपा के सहयोग के बिना शिवसेना की सत्ता को एक दिन भी टिकाए रखना मुश्किल है और वहां की सत्ता जाते ही शिवसेना का संकट गहरा जाएगा. वैसे भी महायुति के सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी से भी मनपा चुनाव के बाद शिवसेना से दूरी बढ़ने लगी है. वहीं नासिक में वादाख़िलाफ़ी से मनसे नेता राज ठाकरे भी उद्धव से नाराज़ हैं और ठाणे में इसका असर भी दिखने लगा है. शिवसेना ने झूठा वायदा करके मनसे के सहयोग से अपना महापौर तो बिठा लिया, लेकिन अब उसके सहयोग के बिना उसकी राह मुश्किल हो चली है. मनसे ने यहां अब कांग्रेस गठबंध्न के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है, इसलिए स्थायी समिति के चुनाव में शिवसेना को पसीने छूटने लगे हैं. उधर उद्धव की वादाख़िलाफ़ी से नाराज़ राज ठाकरे ने क़सम खा ली है कि वे उनकी नींद हराम कर देंगे. अब सवाल यह किया जा रहा है कि मनसे के सहयोग के बिना शिवसेना ठाणे की सत्ता कितने दिन संभाल पाएगी? उद्धव इस उलझन से इन दिनों परेशान हैं. इसका तोड़ निकालने के लिए चालू विधानसभा सत्र में अपने सचिव मिंलिंद नार्वेकर को मनसे विधायक बाला नांदगांवकर के पास भेजा. दोनों की बीच हुई गुफ्तगू पर कयास लगाये जा रहे है कि मनसे विधायक नांदगांवकर को उद्धव शिवसेना में लाकर राज ठाकरे का क़रारा झटका देना चाहते हैं. ग़ौरतलब है कि मनसे विधायक नांदगांवकर कुछ दिनों से राज ठाकरे से नाराज़ हैं, लेकिन उनके शिवसेना के साथ जाने के कोई संकेत नहीं हैं. इस तरह उद्धव ठाकरे अपनी बचकानी राजनीति के चलते उलझन में पड़ गए हैं. अब न वे भाजपा को सबक सिखा पा रहे हैं और न राज ठाकरे से निपट पा रहे हैं. लिहाज़ा वह इस सोच में डूबे हैं कि अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए करें तो क्या करें?

भाजपा को साथ लेकर राज ने नासिक मनसे का पहला महापौर बिठाने में कामयाब रहे. नासिक में मनसे का साथ देने से उद्धव ठाकरे अब भाजपा से नाराज़ हैं और उसे अब सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन कैसे सिखायें? यह प्रश्न ही उनकी उलझन है. यदि वे मनसे का साथ देने पर भाजपा से गठबंधन तोड़ने का फ़ैसला लेते हैं तो उनके हाथ से 21000 करोड़ की तिजोरी की चाबी भी जाने का ख़तरा है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त समाचार

हर गैंगस्टर के पीछे एक पुलिस अधिकारी

महाराष्ट्र में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण करने और गैंगस्टरों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस नए-नए मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रयोग करती रहती है . बात अगर मुंबई की हो, तो वह देश की आर्थिक राजधानी होने के साथ माफियाओं व गैंगस्टरों की भी राजधानी मानी जाती है. इसलिए मुंबई के जोन 9 के डीसीपी प्रताप दिघावकर ने जमानत पर छूटे प्रत्येक गैंगस्टरों के पीछे एक पुलिस अधिकारी को तैनात कर दिया है, जो सतत उस पर निगरानी रखेगा. इस मामले में दिघावकर का मानना है कि पुलिस की मॉनिटरिंग से अपराधी भविष्य में यदि अपराध करना भी चाहेगा तो, शायद नहीं कर पाएगा. इसके लिए उन्होंने सात-आठ साल से जमानत पर छूटे उन गैंगस्टरों की सूची बनाई है, जो इन दिनों बाहर घूम रहे हैं और जिन पर मकोका सहित हत्या, हफ्तावसूली सहित अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं. इस कार्य के लिए दिघावकर ने जोन 9 से 92 पुलिस अधिकारियों का चयन किया है. इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पता करें कि, जिन गैंगस्टरों को जमानत मिली है वे ट्रायल के दौरान कोर्ट में हाज़िर हो रहे हैं या नहीं? यदि नहीं, तो ये गैंगस्टर इन दिनों हैं कहां? क्या कर रहे हैं? इस संबंध में उनके जमानतदारों से जानकारी हासिल करें. यदि ये गैंगस्टर मुंबई में ही हैं, तो उनके कॉल रिकार्ड की जांच करने का भी निर्देश दिया गया है. उनके परिजनों और दोस्तों से मिलकर पूरा ब्यौरा एकत्र करने को कहा गया है, ताकि यह पता चल सके कि इन दिनों वे कौन-सा व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं. जोन 9 में पश्चिम बांद्रा से अंधेरी पश्चिम के बीच का इलाका आता है. अब देखना यह होगा कि इस मॉनिटरिंग सिस्टम से गैंगस्टरों की गतिविधियों पर लगाम लगाने में पुलिस को कितनी कामयाबी मिलती है?

रहस्यमयी आग दैविक चमत्कार या साज़िश?

राज्य के भंडारा ज़िले की तहसील लाखांदुर में डांबेविरली निवासी डांभरकर परिवार पिछले तीन-चार माह से घर में लगने वाली अचानक आग से दहशत में है और अपना घर छोड़ कर उसे नज़दीक के हनुमान मंदिर में शरण लेना पड़ा है. इस रहस्यमयी तरीके से लगने वाली आग से अब पूरा गांव दहशत में है. शंकर डांभरकर, शामराव डांभरकर, दिलीप डांभरकर ये तीनों भाई अपने-अपने पत्नी-बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं. तीन-चार माह पूर्व घर में अचानक आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया. उसके कुछ दिन बाद घर में रखे सामान में आग लग गई. सामान को निकाल कर बाहर रास्ते में रख दिया गया. बीच-बीच में उनके घर पर पत्थरों के गिरने की घटनाएं घटीं. इससे परेशान हो कर गांव के ही हनुमान मंदिर में डांभरकर परिवार ने शरण ले रखी है. सर्दी के तीन माह मंदिर में रहने के दौरान कई बार उनके घर को आग लग चुकी है. चूंकि डांभरकर परिवार का घर गांव के बीच में है, इसलिए गांववालों को आशंका है कि इस घर में बार-बार लगने वाली आग आस-पास के घरों को भी अपने चपेट में ले सकती है. इससे गांव में भारी जानमाल को ख़तरा पैदा हो गया है. वहीं कुछ लोग इस रहस्यमयी आग को दैविक चमत्कार, भानामति के कारण लगने की बात कह रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है यह सब डांभरकर परिवार को डराने की साजिश का हिस्सा है. इसलिए इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए. बहरहाल डांभरकर बंधु अपनी व अपने घर की दुर्दशा को देखकर यही कह रहे हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है?

कुतिया का दूध पीता है अशोक

बिल्ली के कुतिया का दूध पीने या बंदर-बिल्ली के साथ रहने की बात हो तो, अजब-गजब लगती है. लोगबाग इसे प्रकृति की देन समझकर संतुष्ट हो जाते हैं. हालांकि, यह सुन कर अजीब लगता है कि कोई 40 साल का आदमी कुतिया का दूध पी सकता है. दरअसल साकोली तहसील के मुंडीपार (सड़क) गांव में यह दृश्य देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा कर रह जाते हैं. मुंडीपार (सड़क) निवासी 40 वर्षीय अशोक नारायण भदाडे दस साल की उम्र से कुतिया का दूध पी रहा है. उसके परिजनों और गांववालों के लिए अब अशोक का कुतिया का दूध पीना सामान्य दिनचर्या में शामिल हो गया है. अशोक पेशे से ट्रैक्टर चालक है और वह अपनी पत्नी, एक पुत्र और लड़की के साथ रहता है. अवसर पड़ने पर गांव में मज़दूरी भी करता है. अशोक का कहना है कि कुतिया का दूध भले खट्टा हो, लेकिन मुझे स्वादिष्ट लगता है. दूध पीने के दौरान एक-दो कुतियों ने उसे काटा भी है, लेकिन बिना दवा लिए वह ठीक हो गया. इसका उसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ा. दूसरी ओर इस संबंध में साकोली स्थित लघु पशु सर्व चिकित्सालय के डॉ. डी.जी. टेकाम का कहना है कि अशोक दस साल की उम्र से कुतिया का दूध पी रहा है, यह बात असामान्य है. यदि वह किसी निरोगी कुतिया का दूध पाता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन बीमार व रैबिजग्रस्त कुतिया का दूध पीता है तो उसके संसर्ग से रोग के फैलने का ख़तरा पैदा हो जाता है. बहरहाल अशोक गांव की किसी भी कुतिया का दूध बड़े चाव से पीता है और अब तक उससे कोई रोग गांव में नहीं फैला है.

शराब की तस्करी में पुलिसकर्मी गिरफ्तार

पुलिस तो अपराधियों-तस्करों-चोरों को पकड़ती है. किसी पुलिसकर्मी के शराब तस्करी में लिप्त होने की बात सामने आने सहज विश्वास नहीं होता. गोवा के आबकारी विभाग ने महाराष्ट्र के 14 पुलिसकर्मियों को शराब की तस्करी करते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. इतना ही नहीं ये पुलिसकर्मी मुंबई स्थित रिजर्व बैंक के वाहन से शराब तस्करी करने का कारनामा कर रहे थे. विशेष बात यह है कि पकड़े गए पुलिसकर्मियों में एक सहायक इंस्पेक्टर, 2 सहायक सब-इंस्पेक्टर और 11 कांस्टेबल शामिल हैं. ये सभी रिजर्व बैंक के उस वाहन की सुरक्षा में तैनात थे, जिसे गोवा से नकदी लाने के लिए भेजा गया था. चूंकि वाहन रिजर्व बैंक का था और सभी खाकी वर्दीधारी थे, इसलिए कोई उन पर संदेह भी नहीं कर सकता था. इसलिए सरकारी वाहन और वर्दी की आड़ में गोवा में मिलने वाली सस्ती दारू की तस्करी का धंधा करने का इन सबने मन बना लिया. जब वे गोवा से वापस आ रहे थे, तो गोवा-महाराष्ट्र सीमा पर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने वाहन रोका तो उससे 500 शराब की बोतलें निकलीं. मामले की सूचना मिलते ही गृहमंत्रालय ने प्रारंभिक जांच के बाद पाया कि तस्करी में लिप्त सभी पुलिसकर्मी नई मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय से संबंधित हैं. गृहमंत्री आर.आर पाटिल ने आयुक्त अहमद जावेद को जांच करने के निर्देश दिए तो, उन्होंने तत्काल सभी 14 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. आगे की कार्रवाई जारी है. अब भला अपराधियों की क्या ज़रूरत, जब पुलिसवाले ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हों ?

निर्मल ग्राम कहां है?

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान
सफाई में भलाई

वर्धा ज़िले के 37 गांवों को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के हाथों निर्मलग्राम पुरस्कार मार्च माह में प्रदान किया गया. जिन गांवों को यह पुरस्कार मिला, उसके सरपंच, उपसरपंच, सचिव, गाम पंचायत सदस्य काफी खुश हैं. निर्मलग्राम योजना के तहत आखिर जनसंख्या के आधार पर लाखों की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं. हालांकि सच्चाई यह है कि ज़िले में एक भी गांव निर्मलग्राम नहीं है. ज़िला परिषद से लेकर मंत्रालय तक की फाइलों में निर्मलग्राम के रूप में दर्ज ग्रामों में सुबह पैदल या दोपहिया वाहन से निकल जाएं तो सांस रोककर रास्तों से गुजरना पड़ता है. ऐसे निर्मलग्रामों में हिंगणघाट तहसील के बोपापुर, मोझरी, कडजना, सस्ताबाद,येरणगांव, उमरी, कारंजा तहसील के दानापुर, धवसा, नारा, ठाणेगांव, मालेगांव, तरोडा, समुद्रपुर तहसील के पाथर, कलमना, चिखली, लाहोरी, मानगांव, वाघेडा गांव सहित आर्वी व आष्टी तहसील के गांव भी शामिल है. इन गांवों को निर्मलग्राम पुरस्कार किस आधार पर घोषित किया गया है, यह यक्ष प्रश्न है. वैसे तो ज़िला प्रशासन ने 131 गांवों के प्रस्ताव की सूची भेजी थी, लेकिन 101 गांवों का ही चयन किया गया और उसमें भी 37 गांवों को निर्मलग्राम घोषित करने का फ़ैसला किया गया. अब इन गांवों में निर्मलग्राम जैसी कोई पात्रता दिखाई नहीं देती है. इससे चर्चा है कि निर्मलग्राम के नाम पर मिलने वाले लाखों रुपये की बंदरबांट करने का प्रायोजन बन कर रह गया है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

शिवाजी महाराज पर राजनीति

महाराष्ट्र की आन-बान और शान व उसके स्वाभिमान पर राजनीति हो रही है. बात-बात पर महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर बवाल मचाने वाले हमारे नेता उस शख्सियत को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जिसने इस राज्य को संगठित किया, जिसने हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न देखा और बाल्यावस्था में ही रणभूमि में उतर गए. अन्यायियों का सामना करते हुए महाराष्ट्र की आन-बान और शान को एक नई पहचान दी. आज राज्य के जन-जन के श्रद्धा के पात्र छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति की जा रही है. सारे नियम-क़ायदों को कचरे की टोकरी में डालकर अवैध रूप से निर्माण की जा रही लवासा सिटी को केंद्र से पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने के लिए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार तक उसकी वकालत तब करते रहे, जब अदालत में उक्त मामला चल रहा हो. सिंचाई विभाग के कई प्रकल्पों को बिना मंजूरी के ही निर्माण कार्य करने के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंजूरी देने के कई मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि, जब बात आई छत्रपति शिवाजी स्मारक की तो पर्यावरण के सारे नियम-क़ायदे आड़े आने लगे. पहले तो राज्य के मुखिया ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी न मिलने पर समुद्र किनारे स्मारक बनाया जाएगा. जगह की खोज के लिए मुख्यमंत्री द्वारा हवाई सर्वेक्षण करने की बात भी सामने आई, लेकिन जनता सत्ताधीशों की बहानेबाजी को हजम नहीं कर पाई. विधानसभा के अंदर-बाहर राजनीति तेज़ हो गई. छत्रपति शिवाजी पर राजनीति किए जाने पर जनाक्रोश भड़कने की आशंका होते ही सरकार ने फिर पलटी खाई और कहा कि शिवाजी का स्मारक तो अरब सागर में ही बनेगा. मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसा लगा जैसे वह कोई एहसान कर रहे हों. वे क्यों भूल जाते हैं कि शिवाजी महाराज की शख्सियत के आगे आज के राजनेता धूल के समान हैं. इसके बावजूद उनके स्मारक को लेकर राजनीति की जा रही है. ऐसा लगता है कि राज्य सरकार रीढ़विहीन हो चुकी है. सरकार जब देखो तब अपनी ही नीतियों और प्रस्तावों को उलटने-पलटने का खेल खेलती रहती है. इस सरकार के माननीयों की न कोई विचारधारा है और न ही कोई सिद्धांत. सरकार कभी कहती है कि छत्रपति शिवाजी का स्मारक समुद्र तट पर बनेगा तो कभी कहती है कि अरब सागर पर बनेगा. यह सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानों मुंबई की सरकार का हर अहम फ़ैसला दिल्ली में ही होता हो. यदि दिल्ली में ही जाकर हर फ़ैसला लेना पड़ता है तो, यहां क्यों मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री बन कर बैठे हैं? महाराष्ट्र की जनता पर बोझ क्यों है? राज्य की जनता चाहती है कि समुद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्यतम स्मारक बने, इसलिए सरकार को बनाना पड़ेगा. उसमें कई पाप कर चुका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बीच में कहां से आ गया? महाराष्ट्र राज्य शिवाजी का है. यहां के थल-जल और नभ में शिवाजी का शासन-प्रशासन रहा है. राज्य का ज़र्रा-ज़र्रा शिवाजी की कहानी सुनाता है. फिर उनके स्मारक को लेकर राजनीति करते समय राज्य के नेताओं को क्या जरा भी शर्म नहीं आई? कम से कम हमारे सत्ताधीशों को यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि राज्य व देश के महापुरुषों को तो कभी राजनीतिक बिसात का मोहरा न बनाया जाए. यदि ऐसी जुर्रत करते हैं तो इसका खामियाजा चुकाना पड़ सकता है. इसलिए छत्रपति शिवाजी के स्मारक निर्माण से राजनीति को परे रख कर उसका निर्माणकार्य शुरू किया जाना चाहिए, ताकि उनकी आन बान और शान को किसी तरह की ठेस न पहुंचे.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बार-बार वेबसाइट हैक होने और मुस्लिम लिबरेशन की साइट खुलने पर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जहां आतंकवादी संगठन का साइबर अटैक होने का मामला सामने आया.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

विचारधारा नहीं, सत्ता ज़रूरी है

राजेश नामदेव

विचारधारा का आज की राजनीति में कोई महत्व नहीं रह गया है. विचारधारा और सिद्धांत अब बातों के लिए ही रह गए हैं, उनसे किसी का कोई लेना-देना नहीं रह गया है. सभी राजनीतिक दलों की पहली प्राथमिकता बन गई है सत्ता हासिल करना. इसलिए सत्ता के लिए किसी से भी समझौता किया जा सकता है. यदि विधानसभा-विधान परिषद को छोड़ दिया जाए और स्थानीय निकाय चुनावों के बाद महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह खिचड़ी दिखाई दे रहा है. यहां यह बता पाना मुश्किल है कि कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका मित्र? नागपुर से लेकर पुणे तक सत्ता की बंदरबांट की, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब विचारधारा-सिद्धांतों की बजाय सुविधा की राजनीति करने का दौर है.

राज्य में सामान्यतः कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस है और शिवसेना का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन महानगर पालिका, ज़िला परिषद और पंचायत समितियों की बागडोर अपने पास रखने के लिए प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों ने होली के त्यौहार के दौरान अपने सारे गिले-शिकवे भुलाकर आपस में गले लगते दिखाई दिए. शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच छत्तीस का आंकड़ा है, लेकिन ठाणे मनपा की सत्ता में शिवसेना को क़ायम रखने के लिए उद्धव को राज के सहारे की ज़रूरत पड़ी.

राज्य में सामान्यतः कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस है और शिवसेना का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन महानगर पालिका, ज़िला परिषद और पंचायत समितियों की बागडोर अपने पास रखने के लिए प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों ने होली के त्यौहार के दौरान अपने सारे गिले-शिकवे भुलाकर आपस में गले लगते दिखाई दिए. शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बीच छत्तीस का आंकड़ा है, लेकिन ठाणे मनपा की सत्ता में शिवसेना को क़ायम रखने के लिए उद्धव को राज के सहारे की ज़रूरत पड़ी. मनसे की बैसाखी के सहारे आज ठाणे में शिवसेना की सत्ता है. इसी तरह की तस्वीर नासिक मनपा की है. भाजपा के सहारे वहां मनसे ने सत्ता हथिया ली है और उसे कांग्रेस-राकांपा बाहर से सपोर्ट कर रही हैं. ठाणे ज़िले में ही कल्याण पंचायत समिति के लिए कांग्रेस को अपना सभापति बिठाने के लिए शिवसेना से हाथ मिलाना पड़ा. भिवंडी में शिवसेना से हाथ मिलाकर राष्ट्रवादी ने उपसभापति पाया. सिंधुदुर्ग ज़िले की सावंतवाड़ी पंचायत समिति में कांग्रेस ने राकांपा को झटका देते हुए शिवसेना की मदद से सभापति पद हथिया लिया और उपसभापति पद शिवसेना को दे दिया. मराठवाड़ा के जालना में शिवसेना-भाजपा युति को यह अपेक्षा थी कि मनसे उनको सहारा देगी, लेकिन हुआ उलटा. मनसे के अंतिम क्षणों में रुख बदलने का फ़ायदा मिला कांग्रेस-राकांपा की आघाड़ी को. वहीं मंठ्या में कांग्रेस ने राकांपा की बजाय शिवसेना से गठजोड़ कर लिया है. पैठण में शिवसेना ने कांग्रेस के साथ युति की है. कन्नड पंचायत समिति में राकांपा ने मनसे से हाथ मिलाकर सभापति अपना बिठाया तो उपसभापति मनसे को दिया है. सोयगांव में कांग्रेस का सभापति है, तो शिवसेना का उपसभापति . कांग्रेस ने राकांपा को यहां दूर कर शिवसेना को अपना मित्र बना लिया है. नासिक ज़िले में तो महायुति और महाआघाड़ी के दोस्त आपस में दुश्मन बन गए हैं और दुश्मन मित्र बन गए हैं. सत्ता के लिए राकांपा ने शिवसेना के सदस्यों को अपना सहयोगी सदस्य बनाया तो कांग्रेस ने भाजपा के चार सदस्यों को सहयोगी सदस्य बनाकर और मनसे के सहयोग से सत्ता हथियाने में कामयाब रही है. मालेगांव पंचायत समिति में मनसे व स्वतंत्र चुनकर आए प्रत्याशियों के सहारे शिवसेना ने बाजी मार ली है. पेठ में मनसे के सहयोग देने से शिवसेना को सभापति पद मिला तो मनसे को उपसभापति से नवाजा गया. इगतपुरी में राकांपा को झटका देते हुए कांग्रेस ने मनसे, शिवसेना व स्वतंत्र सदस्यों की मदद से सभापति पद हासिल किया. वहीं नासिक में पंद्रह साल में सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस ने मनसे से सहयोग लिया है. जलगांव में सभापति व उपसभापति पद चुनाव में सारी तस्वीर उलट-पुलट दिखाई देती है. चालीसगांव और भडगांव में सभापति राकांपा और उपसभापति पद शिवसेना ने आपसी सहयोग से हासिल किया है.

विदर्भ में भी सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने विचारधारा की जगह सत्ता को तरजीह दी है. जिसे जहां भी सता के लिए हाथ मिलाना पड़ा बिंदास मिला लिया है. नागपुर पंचायत समिति में भाजपा का संख्याबल अधिक होने के बाद भी उसके एक सदस्य के राकांपा के खेमे जाने से दोनों के मध्य संख्याबल बराबर हो गए. मगर ईश्वर ने भाजपा की लाज बचा ली और सत्ता की कुंजी उसके हाथ लगी. वहीं काटोल में राकांपा ने शिवसेना के सदस्य को साथ लेकर सत्ता स्थापित की. शिवसेना को काटोल में उपसभापति पद दिया गया है. दूसरी ओर अमरावती ज़िले में चिखलदरा पंचायत समिति में कांग्रेस ने भाजपा को साध कर रजनी बेलसरे को सभापति पद पर बिठाने में सफल रही है तो दर्यापुर में शिवसेना ने राकांपा से गठजोड़ कर सभापति पद पर कब्ज़ा किया है. अमरावती पंचायत समिति शिवसेना ने सभापति-उपसभापति के लिए विधायक बच्चू कडू के प्रहार संगठन से युति की. मोर्शी में भी ईश्वर चिट्ठी के द्वारा फ़ैसला किया गया, लेकिन राकांपा, कांग्रेस के सहयोग से ही भाजपा को सभापति पद मिला. अचलपुर में सभापति पद हासिल करने के लिए कांग्रेस ने प्रहार संगठन का दामन थामा. भातकुली पंचायत समिति में सत्ता हासिल करने के लिए विधायक रवि राणा ने अपने परंपारिक प्रतिद्वंद्वी राकांपा की पूर्व विधायक सुलभा खोडके के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं. वहीं यवतमाल, दारव्हा और पांढरकवडा में राकांपा ने सत्ता के लिए शिवसेना से युति की है और वणी में शिवसेना ने भाजपा से दूरी बनाते हुए बीएसपी से हाथ मिला लिया. महागांव पंचायत समिति में राकांपा का बहुमत होने के बाद भी सभापति पद का उम्मीदवार अपना न होने पर उसने भाजपा की मालती झिंगरे को समर्थन दिया. झरी जामणी पंचायत समिति सभापति पद कांग्रेस को गया, तो उपसभापति पद शिवसेना को मिला है. वर्धा के आष्टी में राकांपा और भाजपा एकत्र हुई हैं. यहां समझौते के तहत भाजपा को सभापति और राकांपा को उपसभापति पद मिला है. समुद्रपुर में कांग्रेस ने शिवसेना के सहयोग से सत्ता हासिल की है, जिसमें स्वतंत्र भारत पार्टी ने भी मदद की है. चंद्रपुर की पोंभुर्णा पंचायत समिति सभापति पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित था और इसके लिए पात्र एकमेव उम्मीदवार भाजपा के पास थी. इसके मद्देनजर राकांपा ने भाजपा से हाथ मिलाना ही उचित समझा. भद्रावती पंचायत समिति के भाजपा और मनसे साथ-साथ आयीं. जिवती पंचायत समिति में एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी भाजपा-कांग्रेस ने सत्ता के लिए हाथ मिला लिया. महाराष्ट्र की इस सियासी तस्वीर को देखकर यह कैसे कहा जा सकता है कि कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है? इससे यह भी साफ हो जाता है कि आज सबसे महत्वपूर्ण बात है सत्ता की मलाई में अपना हिस्सा पाना.

feedback@chauthiduniya.com

विदर्भ

आतंकी संगठन का साइबर अटैक

मेघनाथ अरोड़ा

विदर्भ आतंकवादी संगठनों के निशाने पर पहले से है. अब आतंकवादियों ने जनता के बीच दहशत फैलाने का नया जरिया चुना है इंटरनेट को. विशेषकर शिक्षण संस्थानों की वेबसाइटों को हैक कर, उसमें अपने संगठन की गतिविधियों और जम्मू-कश्मीर में भारत के अधिकार को ग़ैर-क़ानूनी बताया गया है. साथ ही समुदाय विशेष के पढ़े-लिखें नौजवानों को संगठन से जुड़ कर कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने का आह्वान किया है. आतंकियों के इस साइबर अटैक से पूरे विदर्भ में खलबली मच गई है और सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गए है. इससे यह भी पता चलता है कि आतंकवादी संगठन अत्याधुनिक दूरसंचार प्रणाली का अपने प्रचार-प्रसार और दहशत फैलाने के लिए कितनी सफाई से उपयोग कर रहे है. आतंकी संगठन के इस साइबर हमले का पता तब चला, जब पिछले सप्ताह संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय की वेबसाइट को छात्रों ने अपने परीक्षा परिणाम को जानने के लिए क्लिक किया. छात्रों ने जब अमरावती विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर क्लिक किया तो हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर विश्वविद्यालय की बजाय मुस्लिम लिबरेशन आर्मी का वेब पेज खुला था. इसके आरंभ होते ही हैक बाय एक्सट्रीमिस्ट का संदेश भी आया. बार-बार वेबसाइट हैक होने पर मुस्लिम लिबरेशन की साइट खुलने पर लोगों ने पुलिस विभाग को जानकारी दी, जहां आतंकवादी संगठन का साइबर अटैक होने का मामला सामने आया. पुलिस उपायुक्त सुरेश कुमार साखरे ने बताया कि कि आतंकवादी संगठनों द्वारा देश की करीब 12 हज़ार वेबसाइटों को हैक करने की सूचनाएं है. अमरावती ज़िले में स्थित 45-47 संस्थानों की वेबसाइट को आतंकवादी संगठन ने हैक कर लिया है. जिनमें अमरावती विश्वविद्यालय के अलावा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, विद्याभारती शिक्षा संस्थान, पी.आर. पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रा. राम मेघे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, शासकीय फार्मेसी कॉलेज, एनिमेशन कालेज मुख्य रूप से शामिल हैं. इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन लापरवाह ही बना रहा, जैसे-जैसे मामले सामने आते गए तो वह सतर्क हुआ. पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने साइबर सेल की सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता खेड़कर से विचार-विमर्श किया. उसके बाद सभी संस्थानों की शिकायत पर अमरावती पुलिस के साइबर सेल द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है. आतंकी संगठन के हमले की पुष्टि अमरावती विश्वविद्याालय के कुल सचिव दिनेश कुमार जोशी ने भी की है. उनका कहना था कि देश भर में 12 हज़ार साइटों के साथ ही हमारे यहां की वेबसाइट भी मुस्लिम लिबरेशन आर्मी नामक संगठन द्वारा हैक कर ली गई. पुलिस में शिकायत की जा चुकी है और वह हैकर का पता लगा रही है. इस साइबर हमले से विश्वविद्यालय से जुड़े अकोला, यवतमाल, वाशिम और बुलढाना ज़िले के साढ़े चार सौ महाविद्यालय के डाटा ख़तरे में पड़ गए हैं और वहीं विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी व अन्य जानकारियां नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके सामने संकट खड़ा हो गया है.

राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हमला

साइबर हमले के बाद चर्चा है कि आतंकवादी संगठन मुस्लिम लिबरेशन आर्मी ने साइबर हमले के लिए अमरावती विश्वविद्यालय को इसलिए चुना ताकि वह राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें. वरना अमरावती में साइबर हमला करने की कोई वजह नज़र नहीं आती है. विदर्भ के अन्य शहरों में भी सुरक्षा संस्थान, आर्डिनेंस फैक्टी मौजूद हैं. आतंकवादी साइबर हमले के लिए उनका चुनाव भी कर सकते थे. बहरहाल, इस हमले से आतंकवादी संगठनों ने यह ज़ाहिर कर दिया है कि विदर्भ का अब कोई शहर उनकी ज़द से बाहर नहीं है.

जानकारों का कहना है कि साइबर हमले के पीछे आतंकवादियों का स्पष्ट उद्देश्य है कश्मीर के मुद्दे में युवकों को बरगलाना, उनको भड़काना और उनका भावनात्मक दोहन कर अपनी साजिशों को अंजाम देना. यह इस बात से जाहिर हो जाता है कि मुस्लिम लिबरेशन आर्मी के पोर्टल के पहले पेज में जम्मू-कश्मीर में तैनात सेना के खिलाफ ज़हर उगला गया है. खुफिया विभाग की सूचनाओं के अनुसार आतंकवादी संगठनों द्वारा जिन वेबसाइटों को हैक किया गया है, उनमें सिर्फ शिक्षा संस्थान मात्र शामिल नहीं हैं, बल्कि अन्य प्रशासनिक विभागों की वेबसाइटों का समावेश है. इसके पहले मुंबई विश्वविद्यालय की वेबसाइट को भी आतंकवादी संगठन द्वारा हैक किए जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब उन्हें सफलता नहीं मिली थी. इसके अलावा मुंबई स्थित सैन्य प्रशिक्षण अकादमी में एक संदिग्ध कश्मीरी युवक ने प्रवेश लेने का प्रयास किया था. इन सब तथ्यों के मद्देनज़र यह बात सामने आती है कि आतंकवादी संगठनों के मैप पर महाराष्ट्र को विशेषतौर पर लक्षित किया जा रहा है. महाराष्ट्र का शासन-प्रशासन की लापरवाही देखकर ऐसा लगता है कि उसने 26/11 के हमले के बाद भी कोई सबक नहीं लिया है. कहने को राज्य के पुलिस विभाग में एक साइबर क्राइम सेल का गठन किया गया है, लेकिन वह अपने तहत तब तक कार्रवाई नहीं करता है जब तक उसे जगाया न जाए.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 02 अप्रैल-08 अप्रैल 2012

www.chauthiduniya.com

संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान

SANJEEVANI BUILDCON

3rd & 4th floor, GEL Church Complex, Main Road, Ranchi, Customer Care No. - 0651-2331429

Sanjeevani Dynasty-I
PLOT-13 LAC, DUPLEX-25 LAC
Near Ranchi College

Sanjeevani Dynasty-II
PLOT-10 LAC, DUPLEX-22 LAC
Booty More

Future City (BIT)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Namkom)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Pithoria)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Sanjeevani Mega Township
PLOT-3.5 LAC, BUNGLOW-09 LAC
Hazaribagh

रास चुनाव ने गठबंधन का स्वाद कड़वा किया

सब पर भारी नीतीश भाई

सरोज सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का दर्द है कि, बिहार में गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है. हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व सुशील कुमार मोदी कैमरे के सामने मुस्कराते हुए कहते हैं कि हम साथ- साथ हैं. वहीं नंदकिशोर यादव तो एक क़दम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, भाजपा का जो हक़ बनता था वह उसे मिला. ऐसे में भला गिरिराज सिंह कहां मानने वाले थे, वह चिल्लाए- अरे नीतीश जी वो दो सीट भी मांग लेते तो, हम उन्हें दे देते, लेकिन यह भाजपा के मंत्रियों की भाषा है. उसके पीछे उनका सत्ता मोह है या गठबंधन धर्म यह तो जनता समझ रही है, लेकिन उसके बाद जो भाजपा बचती है वह राज्यसभा चुनाव में हुई पार्टी की फ़जीहत से ख़ासा नाराज़ है. सार्वजनिक तौर पर तीसरे सीट की मांग जदयू से की गई, लेकिन नीतीश नहीं माने. आर के सिन्हा व एस.एस अहलूवालिया के नामांकन के कागज़ात धरे के धरे रह गए. आखिर इन दो बड़े नेताओं को बीच मझधार में छोड़कर भाजपा ने क्या संदेश दिया. भाजपा विधायक राम प्रवेश राय ने कहा कि, जो हुआ ग़लत हुआ.

पार्टी के बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि इस तरह के फ़ैसलों से कितना ग़लत संदेश जाता है. कई भाजपा विधायकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह पूरी तरह एकतरफा गठबंधन है. होता तो यह है कि बड़े भाई छोटे भाई की मांग पूरी करता है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी है. वह तो सब पर भारी हैं. भाजपा के पास सबसे अधिक अतिरिक्त वोट है, फिर भी जदयू के समर्थन को मजबूर है. आखिर यह कौन सा गठबंधन धर्म है. असल में, इस पूरे नाटक को समझने के लिए कुछ पुराने पन्ने पलटने होंगे.

जदयू में पहले यह राय बनी थी कि, वह इस बार नए चेहरों को राज्यसभा में भेजेगा. किंग महेंद्र, अली अनवर व अनिल सहनी पार्टी की पहली पसंद इस बार नहीं थे. साबिर अली को राज्यसभा में भेजकर पसमांदा का कोटा पूरा कर दिया गया था. अतिपिछड़ा से किसी दूसरे दल के बड़े नेता को भेजने का अभियान चलाया गया और किंग महेंद्र की जगह ललन सिंह पर डोरे डाले गए कि, वह अपने किसी नुमाइंदे को आगे करें, लेकिन पल-पल बदलते सियासी समीकरण ने जदयू के प्लान एक को ज़मीन पर नहीं उतरने दिया. ललन सिंह नहीं माने और दूसरे दल की सेंधमारी को यूपी चुनाव के परिणामों ने फ़िलहाल रोक दिया. मुस्लिम नेताओं में दावेदारों की इतनी बड़ी फौज़ सामने आ गई कि अली अनवर का रास्ता आसान हो गया. चेहरा बदलने के मिशन के तहत ही वशिष्ठ बाबू को आश्वासन दिया गया था, लेकिन जब प्लान एक फेल हो गया तो, जदयू अध्यक्ष की सांस फूंलने लगी. बार-बार यह संदेश भिजवाया जाने लगा कि इस बार अगर वशिष्ठ बाबू नहीं गए तो, पार्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. दबाव इतना बढ़ा कि नीतीश कुमार को खुद चौथी सीट की बात सार्वजनिक तौर पर करनी पड़ी. उसी दिन यह तय हो गया कि, अब भाजपा को दो सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश की मांग को ठुकराने की हिम्मत फ़िलहाल भाजपा के किसी नेता के पास नहीं है. बात दिल्ली तक गई और बबाल मच गया. अध्यक्ष नितिन गडकरी के इस राय के बाद तो प्रदेश के बड़े नेताओं ख़ासकर सुशील मोदी व नंदकिशोर यादव को सांप सूंघ गया. इन लोगों ने नीतीश कुमार की टीम के पास त्राहिमाम संदेश भिजवाया कि तीसरी सीट भाजपा को दे दी जाए, लेकिन भाजपा के इन नेताओं को दो टूक बता दिया गया कि जदयू के फ़ैसले पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा, भले ही गठबंधन टूट जाए. जदयू के इस रुख के बाद सुशील मोदी के निवास पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि दिल्ली के नेताओं को यह समझाया जाए कि तीसरे सीट पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो, वोटों का इंतज़ाम करना बेहद मुश्किल होगा. राजद व कांग्रेस में सेंध लगाने की हैसियत में पार्टी नहीं है. ऐसे में गठबंधन को नुक़सान तो होगा ही, पार्टी का उम्मीदवार भी नहीं जीत पाएगा. ऐसे में भाजपा न घर की रहेगी और न घाट की. प्रदेश के सभी बड़े नेता इसी लाइन पर पार्टी आलाकमान को समझाने में लग गए. आखिर में तय हुआ कि आगे का कोई आश्वासन लेकर बात ख़त्म की जाए. दिल्ली के नेताओं को अगले दिन बता दिया गया कि वर्ष 2014 के विधान परिषद चुनाव में जदयू पार्टी को एक अतिरिक्त सीट देगी. दिल्ली में भाजपा में छिड़ी आपसी लड़ाई को इसी बात पर समाप्त कराया गया. वहीं दूसरी तरफ झारखंड में अंशुमान मिश्रा प्रकरण को लेकर भी पार्टी हाईकमान कमज़ोर पड़ गया. भाजपा के संभावित उम्मीदवार आर.के. सिन्हा ने बाद में बताया कि पार्टी में बहुत सारी गंदगी आ गई है. भाजपा व देशहित में इसका साफ होना ज़रूरी है. मैंने नामांकन नहीं किया, क्योंकि इससे गठबंधन में दरार आ जाती. इसलिए मैंने उन्हें नामांकन करने दिया, जिन्हें दिल्ली में मकान व गाड़ी की दरकार थी, लेकिन पार्टी को स्वच्छ बनाने की मेरी लड़ाई जारी रहेगी. दूसरी तरफ जदयू को ऐसा लगता है कि, उसने राज्यसभा चुनाव में होने वाली परेशानी से फ़िलहाल राहत पा ली है. परिषद चुनाव में भी सर्वसम्मति से रास्ता निकाल लिया जाएगा. वैसे जानकारों का मानना है कि परिषद के लिए दावेदारों के नामों को अंतिम रूप देने में काफी मशक्कत करनी होगी. सेटिंग-गेटिंग की बात ज़रूर कही जा रही है, लेकिन नए चेहरे को मौका देने के लिए चुनाव के विकल्प भी पार्टी ने खुले रखे हैं. उधर विपक्ष ने अनमने ढंग से ही, लेकिन अशफ़ाक करीम को मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव को रोमांचक बनाने की कोशिश की. अब्दुल बारी सिद्दकी व सम्राट चौधरी उनके लिए पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि आलाकमान के निर्देश के बाद चुनाव में न बने रहने का फ़ैसला लिया गया और अशफ़ाक करीम ने अपना नामांकन वापस ले लिया.

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

भाजपा का बाग़ी चेहरा

विक्रम कुंवर

विक्रम कुंवर एक ऐसा नाम, जो हमेशा सुर्ख़ियों में रहने की कला जानते हैं. भाजपा के रथ की सवारी करने वाले विक्रम कुंवर कभी बाहुबली शहाबुद्दीन के ख़ास थे, लेकिन बाद में भगवा पार्टी में ऐसे रमे की रमते चले गए. सदन का कोई ऐसा सत्र नहीं बीतता है, जब वह जनहित के सवाल पर अपनी ही सरकार को नहीं घेरते हैं. ग़रीबों के अनाज में, जब कालाबाज़ारियों की सेंधमारी हुई तो विक्रम कुंवर ने सदन को चिल्ला- चिल्ला कर बताया कि ग़रीबों का पेट ख़ाली है और मुनाफ़ाखोरों की तिजोरियां भरी जा रही है. अपनी ही सरकार पर उन्होंने इतना दबाब बनाया कि सरकार ने कई क़दम उठाए और कई गिरफ्तारियां भी हुईं. इधर राज्यसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक हुई, इसका दर्द भी विक्रम कुंवर से नहीं सहा जा रहा है. उनका मानना है कि यह गठबंधन का मजाक है. उनके अनुसार यह तो वन वे गठबंधन है. उन्होंने कहा कि पार्टी का आम कार्यकर्ता लोगों को यह समझाने में लाचार महसूस कर रहा है कि आखिर भाजपा ने तीसरी सीट पर अपनी दावेदारी क्यों छोड़ी. विक्रम कुंवर का कहना है कि सत्ता तो आती- जाती है, लेकिन अगर पार्टी अपने सिद्धांतों से पीछे हट गई, तो कितना नुक़सान होगा इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होगा. सुशासन के लिए जदयू से समझौता है, लेकिन जब हम अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो सूबे की जनता हमसे उम्मीद कैसे रखेगी. कुंवर ने बताया कि विधानसभा सत्र के बाद वह पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी से मिलकर प्रदेश भाजपा को सही रास्ते पर लाने की प्रार्थना करेंगे, ताकि बिहार की जनता ने भाजपा के प्रति जो भरोसा दिखाया है, उस पर कोई आंच नहीं आए.

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने तो एक दिन प्रेस के सामने नारायण मेडिकल के वार्षिक समारोह में राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की.

बदल रहा है रोहतास का राजनीतिक गणित

अवैध खनन को लेकर इन दिनों प्रदेश के चारों ओर चिंता जताई जा रही है, लेकिन इसे लेकर सरकार और विपक्ष फ्रिकमंद तो है, लेकिन तमाम चिंताओं के बावजूद भी यह कारोबार बदस्तूर जारी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो, सदन में यहां तक कह डाला कि वह किसी भी क़ीमत पर राज्य में अवैध खनन नहीं होने देंगे. वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय विधायक श्रीमति ज्योति रश्मि लगातार सदन के बाहर धरना देकर मांग कर रही है कि सरकार अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच कराए. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सदन में इनके साथी भी खुलकर उनका साथ नहीं दे रहे हैं. सदन के बाहर अकेले बैठी ज्योति रश्मि आने जाने वाले माननीय सदस्यों को देखती रहती हैं, लेकिन इस मामले में उनका साथ कोई नहीं दे रहा है. वह कहती हैं कि, उनके पति को इस मामले में बेवजह फंसाया जा रहा है. अगर सरकार सीबीआई जांच कराए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. दरअसल, सासाराम व उसके आस–पास के इलाक़ों में अवैध खनन के ख़िलाफ़ हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है. कई राजनेता इस दायरे में आ चुके हैं, इसलिए मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है. इस व्यवसाय में लगे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह की भी काफी फ़जीहत हो रही है. इतना ही नहीं, ज़िले के कुछ कद्दावर जदयू नेता भी सरकार की इस कार्रवाई से आर्थिक मार की चपेट में हैं, जो यहां राजनीतिक समीकरण में नये भूचाल आने का संकेत है. सरकार ने भले की पहाड़ बचाने के बहाने इस बड़े उद्योग के आगे पूर्ण विराम लगाने का प्रयास किया है, लेकिन जिस तरह से रोहतास की अर्थव्यवस्था और विकास पर इस सरकारी आदेश ने कुप्रभाव छोड़ा है, उसका दूरगामी परिणाम ज़रूर देखने को मिलेगा. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने तो एक दिन प्रेस के सामने नारायण मेडिकल के वार्षिक समारोह में राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की. उन्होंने यहां तक कह डाला कि, यहां विकास नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ अख़बारी ढिंढोरा पीटा जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व का परचम हाथ में लिए रोहतास के डेहरी विधानसभा से लगातार दो बार विधायक रहे प्रदीप जोशी पर कार्रवाई के ख़िलाफ़ इनकी विधायक पत्नी ज्योति रश्मि विधानसभा में लगातार संघर्ष कर रही हैं. इसे देखकर भी यहां के लोगों की संवेदना धीरे–धीरे सुगबुगाने लगी है. गाहे–बेगाहे कभी उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीज़ों तो कभी सम–सामयिक घटनाओं पर सरकार की आलोचना करने से नोखा के भाजपा विधायक रामेश्वर चौरसिया भी नहीं चूकते. उनके मन में भी कहीं न कहीं पत्थर उद्योग का दु:ख साल रहा है. भाजपा का एक खेमा गोपाल नारायण सिंह पर लगातार हो रही प्रशासनिक कार्रवाई से काफ़ी नाराज़ है. उनके साथ युगलबंदी करने में जदयू के कुछ कद्दावर नेता भी लगे हुए हैं. रोहतास के पत्थर उद्योग को लेकर राजनीतिक घेरेबंदी की गति अगर इसी तरह से क़ायम रही तो, आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ अप्रत्याशित परिणामों की उम्मीद लगाई जा सकती है. यहां बता देना ज़रूरी है कि, पत्थर उद्योग में सर्वाधिक रोज़गार पाने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और अतिपिछड़ा वर्ग के वैसे लोग थे, जो दिन भर मेहनत मज़दूरी कर अपने परिवार की परवरिश करते थे. उनके बीच पहाड़ बंदी, जीवन में पहाड़ टूटने के समान है. पीड़ित लोगों को नाराज़ भाजपाई और असंतुष्ट जदयू नेता यह समझाने में जुटे हैं कि, यह सब कुछ सुशासन के हिमायती नीतीश सरकार की देन है. अगर इनके मन मस्तिष्क पर सरकार के इस निर्णय का विपरीत असर पड़ा तो, वोट बैंक का एक बड़ा तबका प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा. वैसे भी रोहतास ज़िला के खनन उद्योग पर जदयू और भाजपा गठबंधन से जुड़े 80 प्रतिशत लोगों का एक छत्र राज था. यहां 20 प्रतिशत लोग ही राजद और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े लोग यह व्यवसाय करते थे. ऐसे में ज़ाहिर है कि, इस उद्योग की बंदी से रोहतास ज़िला में गठबंधन का बड़ा हिस्सा सरकार से नाराज़ होगा, क्योंकि यह नाराज़गी हाथों के रोज़गार से जुड़ा हुआ है.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

आंखों का विशेष ख्याल रखें

डॉ. श्रीकांत झा

पूर्णिया का लाईन बाज़ार सीमांचल ही नहीं बल्कि बंगाल में भी प्रमुख चिकित्सीय नगरी के रूप में प्रसिद्ध है. यहां डॉ. श्रीकांत झा शहर के प्रमुख नेत्र सर्जन के रूप में मशहूर हैं. इनके द्वारा प्रस्तुत है वायरल कंजंक्तिविटिस पर दी गई ख़ास जानकारी.

प्र.– वायरल कन्जंक्टिविटिस क्या है? रोग के कारण बताएं

उ.– वसंत ऋतु के समय अक्सर आंखें लाल हो जाती हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग आँख का उठनाफ्फ कहते हैं. इसके विपरीत वायरस के कारण वायरल कन्जंक्टिविटिस भी होती है. कीट के आंख में जाने एवं काटने से यह बीमारी होती है. कभी–कभी मकड़े के संपर्क में आंख के आने से भी यह बीमारी होती है.

प्र.– इस बीमारी के क्या–क्या लक्षण हैं?

उ.– आंख का लाल होना, आंखों में जलन होना, आंखों का खुजलाना और आंख में बालू के कण की तरह चुभन महसूस होना. इसके अलावा आंख बंद करने एवं खोलने पर आंसू गिरना व हल्का धुंधला दिखना और कभी–कभी आंखों में सूजन आना इसके प्रमुख लक्षण हैं.

प्र. लोगों को इस बीमारी से बचने के उपायों के बारे में बताएं.

उ. आंखों को गर्म पानी या कपड़े से नहीं सेंके, आंखों को ठंडा पानी से खूब धोएं. अगर हो सके तो बर्फ से सेकें, आंखों को खुजाना नहीं चाहिए. किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ से उचित परामर्श लें.

नीरज कुमार सिंह
feedback@chauthiduniya.com

सरकार ने अनुबंध पर अस्पताल में मुर्शक विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली तो कर दी है, इससे यहां काम भी नहीं लिया जाता है और उनके स्थान पर दूसरे चिकित्सकों से काम लिया जाता है.

गया-बोधगया की तस्वीर नहीं बदली

सुनील सौरभ

चहुंओर बिहार में विकास की चर्चा है, लेकिन गया ज़िले में विकास की बातें मोर की दोनों पैर देखने के बाद शर्माने जैसी ही है. इसके कोई शक नहीं कि आने वाले समय में गया–बोधगया बिहार की आर्थिक राजधानी होगी. बिहार सरकार की उपेक्षा के बाद भी मोक्ष धाम गया व तथागत की ज्ञान भूमि बोधगया का स्वाभाविक विकास हो रहा है. इसमें सरकार की ओर से होने वाले विकास की तस्वीर कहीं नज़र नहीं आती. सिर्फ सड़कें, गली और नाले बना दिए जाने को विकास कहा जाए तो, यह अलग बात है. ज्ञान भूमि के कारण बोधगया में तमाम बौद्ध देशों के श्रद्धालु बौद्ध मठ व मंदिर का निर्माण कर रहें है, जिससे बोधगया की रौनक बढ़ रही है. यदि गया–बोधगया जैसा धार्मिक पर्यटन स्थल देश के दूसरे राज्य में होता तो, उसकी स्थिति कुछ और ही होती. लालू–राबड़ी के शासन में बिहार की जो भी सामाजिक, राजनीतिक स्थिति रही हो, लेकिन मौजूदा समय में ही बोधगया ने विकास की नई गाथा लिखी है. हालांकि कथित सुशासन सरकार में जहां विकास की बात की जा रही है , वहीं गया में वर्षों पुरानी कॉटन मिल का वजूद मिल रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया. इसी तरह मानपुर के बुनकरों के लिए सरकार की ओर से प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया था, हालांकि उसे भी दूसरी जगह भेज दिया गया. सेना सेवा कोर भी गया से हट गया, लेकिन फिर भी बिहार सरकार की ओर से कोई विरोध नहीं जताया गया. यह कुछ बातें नमूने के तौर पर हैं. गया–बोधगया की उपेक्षा के दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं. अब जबकि केंद्र सरकार गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहती है, तो सुशासन के मुखिया नीतीश कुमार इसका विरोध कर रहे हैं. इन्हीं सब बातों से गया–बोधगया के प्रति बिहार सरकार के सौतेले नज़रिए का पता चलता है. अक्टूबर 2011 के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च 2012 के प्रथम सप्ताह तक साढ़े चार महीने में बोधगया में 2 लाख 69 हज़ार विदेशी पर्यटक आए, जो खुद में एक रिकार्ड है. बोधगया के रास्ते बिहार के विकास के लिए इससे अच्छी बातें और क्या हो सकती है. बिहार सरकार चाहे तो हिन्दुओं तथा बौद्धों के धार्मिक अस्था से जुड़े गया – बोधगया का विकास कर पर्यटन व्यवसाय से बिहार को समृद्ध बना सकती है. बावजूद इसके गया– बोधगया पर नीतीश कुमार गंभीर नहीं दिख रहे हैं. उनकी इस उदासीनता का सच तो यह है कि बोधगया जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल का विकास राजद के कथित जंगल राज में ही हुआ. महाबोधि मंदिर के सौंदर्यीकरण से लेकर बोधगया के विकास की कहानी गया के तत्कालीन ज़िला पदाधिकारी एस. एम राजू ने लिखी. इस ज़िला पदाधिकारी ने गया–बोधगया के विकास का जो ब्लू प्रिंट तैयार किया था, इसका नमूना भर है बोधगया. आज बोधगया में महाबोधि मंदिर की सुंदरता, इस मंदिर के सामने से लेकर पूरे बोधगया में जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ, बाईपास बना वह सब पूर्व ज़िलाधिकारी की ही देन है. यूनेस्को ने वर्ष 2001 में एस. एम राजू की पहल पर ही महाबोधि मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया. बौद्ध महोत्सव की शुरूआत की तैयारी भी उन्होंने ही किया था, लेकिन तभी आज के सुशासन में शामिल दल के कुछ नेताओं ने एक साजिश के तहत एस.एम राजू का तवादला करा दिया. उसके बाद विष्णुपद मंदिर के विकास की योजना अधूरी रह गई. उन्होंने पटना के मौर्य लोक की तरह गया में भी आंबेडकर मार्केट, किरानी घाट व गांधी मैदान के पास फुटपाथी दुकानदारों के लिए बेंगलुरू की तरह दुकानें बना रहे थे, जो उनके तबादले के बाद पूरा नहीं हो सका. पूर्व ज़िलाधिकारी ने बोधगया में माया सरोवर का जीर्णोद्धार कर, इसमें म्यूजिकल फव्वारा और नौका विहार की योजना बनाई थी. यह सब उनके तबादले के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. ज़िला युवा लोजपा के अध्यक्ष तथा ज़िले के विकास के लिए आंदोलन करने वाले अरविंद कुमार सिंह कहते हैं कि एनडीए की सरकार में बोधगया और गया जैसा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल विकास से कोसों दूर है. यहां विकास की बातें करना बिहार सरकार को बेहद नागवार गुजरता है.

feedback@chauthiduniya.com

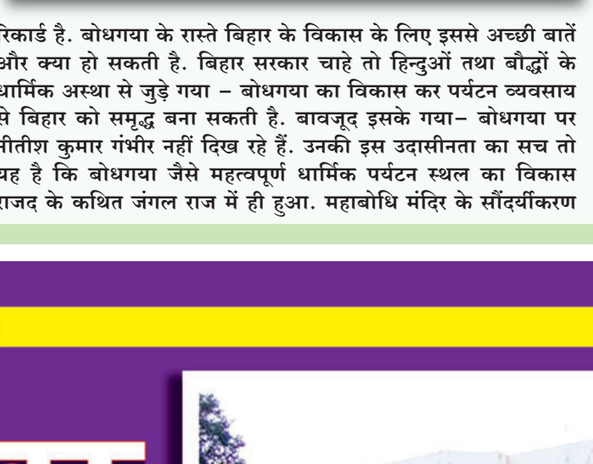

मधुबनी नगर परिषद चुनाव

परेशान जनता सबक़ सिखाने को तैयार

नव निर्मित नगर परिषद प्रशासनिक भवन, मधुबनी

विजय कुमार चौधरी

खालिद अनवर

आगामी मई–जून में प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव होने हैं. इस बाबत मधुबनी में भी इन चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज़ हो गई है. चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां ज़ोरों पर है. लोगों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. नगर परिषद के होने वाले इस चुनाव में नगर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है. वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी इस लड़ाई को फतह कर पाएंगे या नहीं, यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. ब्रिटिश राज में वर्ष 1869 में स्थापित मधुबनी म्युनिसपेलेटी (अब मधुबनी नगर परिषद) अपने स्थापना काल से अब तक कई उतार–चढ़ाव देख चुका है. अपने 143 वर्षों के इतिहास में मधुबनी नगर परिषद ने सैकड़ों वार्ड पार्षद एवं दर्जनों अध्यक्ष देख चुका है, लेकिन विकास के मामले में इसकी चाल कछुए की चाल से भी बदतर है. आबादी बढ़ती गई, आय भी बढ़ा, लेकिन आम लोगों को नगर परिषद द्वारा मिलने वाली सुविधाएं दिनोंदिन घटती चली गई. इसका मुख्य कारण नगर परिषद में व्याप्त अव्यवस्था, अराजकता और बदइंतज़ामी है. चुनाव होते रहे और अध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन मधुबनी नगर परिषद में व्याप्त अव्यवस्था, अराजकता एवं बदइंतज़मी पर रोक नहीं लग पाया. यही कारण है कि हाल के वर्षों में हर चुनाव के बाद कोई भी व्यक्ति दो बार नगर परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज़ नहीं हो पाया. मधुबनी नगर परिषद में वर्तमान बोर्ड का गठन जुलाई 2007 में हुआ था. उस वक्त 30 वार्डों वाली मधुबनी नगर परिषद के 16 वार्ड पार्षदों के समर्थन से पवन कुमार पूर्वे अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. उसके ठीक दो वर्ष बाद वर्ष 2009 में पूर्वे के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन एक वर्ष तक मामला न्यायालय में लंबित रहने के कारण वर्ष 2010 में फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और 18 वार्ड पार्षदों के समर्थन से विजय कुमार चौधरी ने अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना कब्ज़ा जमाया था. वर्ष 2002 के हुए चुनाव में निवर्तमान अध्यक्ष पवन कुमार पूर्वे की पत्नी महारानी देवी अध्यक्ष चुनी गईं थी, लेकिन दो वर्ष बाद लाए गये अविश्वास प्रस्ताव के बाद रेखा नायक अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज़ हुई थी, लेकिन उस वक्त भी अव्यवस्था, अराजकता एवं बदइंतजामी का माहौल ऐसा था कि गबन के आरोप में तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती रेखा नायक को जेल की भी हवा खानी पड़ी थी. हालांकि अव्यवस्था, अराजकता एवं बदइंतज़ामी की चुनौतियां वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के समय में भी मौजूद है. राजस्व में कमी की वजह से आज भी नगर परिषद के कर्मचारियों को पिछले 16 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है. बकाया वेतन भुगतान के समायोजन के लिए मिलने वाला सरकारी मैंचिंग ग्रांट भी बंद है. शहर में जलापूर्ति की व्यवस्था ठप है. सफाई की व्यवस्था पटरी से उतर जाने के कारण शहर के अधिकांश मुहल्लों में लोगों को गंदगी के बीच रहने को विवश होना पड़ रहा है. अतिक्रमण के कारण तंग होती सड़कों पर चलना मुश्किल बना हुआ है. जाम की समस्या से लोग परेशान हैं. अतिक्रमण की वजह से शहर में जल निकासी की एक बड़ी समस्या बन गई है. बरसात में शहर के अधिकांश मुहल्लों में जल जमाव से बीमारियां फैल रही है. सड़कों पर उचित रोशनी की व्यवस्था नहीं है. नगर परिषद में कर्मचारियों की कमी का आलम यह है कि एक काम के लिए आम लोगों को महीनों दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है. ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने शहर के विकास के लिए राशि का आवंटन नहीं किया है, लेकिन नगर परिषद में व्याप्त गुटबाज़ी और वर्तमान अध्यक्ष की कार्यप्रणाली के कारण लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. लोगों में नगर परिषद प्रशासन के प्रति आक्रोश दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है.

अब चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू होने के बाद आम लोगों में व्याप्त आक्रोश बदलाव की शक्ल ले रहा है. यही कारण है कि नगर परिषद की बढ़ती चुनौतियों ने वर्तमान अध्यक्ष श्री चौधरी की प्रतिष्ठा को दांव पर ला खड़ा किया है. चुनाव के पूर्व मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर भी एक नया बवाल शुरू हो गया है. अनुभवहीन लोगों के द्वारा नई मतदाता सूची का निर्माण किया जाना नगर परिषद प्रशासन के गले की फांस बन गया है. मतदाता सूची में त्रुटियों की भरमार है. कई वोटरों के नाम मतदाता सूची से ग़ायब हैं. वहीं कई लोगों के नाम तथा इनके पिता का नाम ग़लत छप गया है, जिस वजह से इन चुनावों में कई मज़बूत प्रत्याशियों के खड़े होने पर सवालिया निशान लग गया है. यहां तक की मुख्य पार्षद विजय कुमार चौधरी का नाम भी आधा–अधूरा प्रकाशित हुआ है. मतदाता सूची में ग़लत नामों की संख्या हज़ारों में है, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. हालांकि वर्तमान अध्यक्ष श्री चौधरी कहते हैं कि, उन्होंने पूर्व नगर परिषद अध्यक्षों की तुलना में बेहतर काम किया है. उन्होंने अपने समय में नगर परिषद के जीर्ण–शीर्ण प्रशासनिक भवन की जगह 77 लाख रुपये की लागत से नये प्रशासनिक भवन का निर्माण कराया है. इसके अलावा 61 लाख रुपये की लागत से सार्वजनिक विवाह भवन का निर्माण का कार्य शुरू कराया है. वहीं शहर के मध्य स्थित निजी बस पड़ाव को शहर के उत्तरी छोड़ पर स्थित गंगा सागर मुहल्ले में शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू की है. इसके अलावा दर्जनों मुहल्ले में पी.सी.सी. सड़क का निर्माण कराया गया है. सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं, लेकिन होल्डिंग टैक्स रिभिजन का काम सर्वे होने के बाद क्यों पूरा नहीं हो पाया और कर्मचारियों के लंबित वेतन के भुगतान समेत अन्य नागरिक सुविधाएं क्यों बहाल नहीं हो पाई है, इसका जवाब उनके पास नहीं है. नगर परिषद में विपक्ष के नेता वार्ड पार्षद ख़ालिद अनवर निवर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के विकास के दावों को खोखला क़रार दे रहे हैं. उनका कहना है कि मधुबनी नगर परिषद में अराजकता, अव्यवस्था एवं बदइंतजामी का केंद्र बन गया है. वर्तमान अध्यक्ष नगर के विकास करने में और नागरिक सुविधा बहाल करने में अक्षम साबित हुए हैं. यही वजह है कि वर्तमान अध्यक्ष के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ा है. लिहाज़ा आगामी चुनाव वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के लिए वाटर लू का मैदान साबित हो सकता है.

डॉ. इंद्रमोहन झा
feedback@chauthiduniya.com

मुआवज़े के बदले पंचायत पर सामूहिक जुर्माना

जिस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में दो–चार लोगों की ग़लतियों का ख़ामियाजा पूरे गांव के लोगों को सामूहिक जुर्माना के रूप में भुगतना पड़ता था, ठीक वैसी ही घटना सुशासन सरकार के अधिकारियों ने पूरे पंचायत के पुरुष मतदाताओं पर सामूहिक जुर्माना लगाकर अंग्रेजी हुकूमत की याद ताज़ा कर दी है. घटना बक्सर ज़िले के सिमरी अंचल अंतर्गत सिमरी पंचायत की है. यहां पिछले वर्ष 28 जुलाई को सिमरी बाज़ार में सड़क पर गड्ढे में भरे पानी में डूबने से बइका गांव निवासी पुतुल कुमार मिश्र नामक एक कॉलेज छात्र की मौत हो गई. छात्र की मौत के बाद लोगों ने शव के साथ सिमरी में सड़क जाम कर पांच लाख रुपये मुआवजा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के विलंब से आने पर नाराज़ लोगों ने मौके पर पथराव कर दिया. ग्रामीणों की इस हरकत से खफ़ा अधिकारियों ने मृत छात्र के परिजनों को मुआवज़ा देने की बजाय पंचायत ते लोगों पर जुर्माना लगा दिया. कुल 5400 लोगों पर जुर्माना लगाया गया. इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि पंचायत के लोगों ने घटना वाले दिन सरकारी संपत्ति को नुक़सान पहुंचाया था. नुक़सान का आकंडा एसपी (पत्रांक 809 दिनांक 19.02.2012) द्वारा डीएम को भेजा गया. इस रिर्पोट का अवलोकन करने के बाद ज़िलाधिकारी अजय यादव ने 12 व्यावसायियों सहित पूरे पंचायत के पुरुष मतदाताओं के विरूद्ध 15 लाख रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया. डीएम का कहना है कि सिमरी पंचायत के सभी पुरुष मतदाताओं ने प्रखंड के सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ की. उपरोक्त आरोपियों का आचरण लोक व्यवस्था और समुदाय के जीवन की सुरक्षा सहित सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा के प्रतिकूल है. इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी अभियुक्तों को सामूहिक जुर्माना का दोषी मानते हुए, यह आदेश दिया जा रहा है. डीएम ने बिहार सार्वजनिक अधिनियम 1988 की धारा–2 के तहत 15 लाख रुपये का जुर्माा लगाया है. डीएम के इस आदेश के बाद भाजपा खेमे में बैचैनी बढ़ गई है. क्षेत्रीय भाजपा विधायिक दिलमणि देवी ने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है. हैरत की बात यह है कि जुर्माना वैसे लोगों पर भी लगाया है जो 80–85 वर्ष के वृद्ध, असहाय और सरकारी कर्मचारी हैं, जो उस दिन कार्यालय गये थे. इस आदेश के विरूद्ध पंचायत की मुखिया निर्मला देवी की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने बैठक कर जुर्माना नहीं देने तथा मामला कोर्ट में ले जाने का निर्णय लिया है. विधायक पुत्र संतोष मिश्रा ने कहा कि ऐसा हिटलरी आदेश जारी करने से पूर्व सरकार से स्वीकृति भी नहीं ली गई. जिला 20 सूत्री सदस्य ध्रुव तिवारी तथा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य शंभूनाथ पांडेय ने कहा कि ऐसे मनमानी आदेश से सुशासन की सरकार शर्मसार हुई है. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रो. बलिराज ठाकुर कहते हैं कि पंचायत के लोगों का मतदाता होना इस सरकार में अपराध बन गया है. पूर्व मंत्री तथा राजद जिलाध्यक्ष अजित चौधरी ने कहा कि इस आदेश से सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया है. सरकार जनता के अधिकार को हनन करना चाहती है.

जयमंगल पांडेय
feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी का सदर अस्पताल ख़ुद बीमार है

इंतजारूल हक़

हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज़ पर चल रहा है मोतिहारी ज़िले का स्वास्थ्य विभाग. सुशासन की सरकार भले ही कागज़ पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का ढ़िढोरा पीट रही हो, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है. सदर अस्पताल के मेडिसीन ओपीडी का मामला हो या हादसों में मरे लोगों के पोस्टमार्टम का, या फिर महिला चिकित्सकों की ड्यूटी का. यहां पदस्थापित अधिकांश चिकित्सक निजी प्रैक्टिस में व्यस्त हैं और केवल हाजरी बनाने के लिए अस्पताल आते हैं. सरकार ने अनुबंध पर अस्पताल में मुर्छक विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली तो कर दी है, इनसे यहां काम भी नहीं लिया जाता है और उनके स्थान पर दूसरे चिकित्सकों से काम लिया जाता है. जानकार बताते हैं कि सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. निर्भय सिंह, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. आरके वर्मा, डॉ. रविरंजन व डॉ. पुष्कर मुर्छक से संबंधित कार्य करते हैं. मुर्छक के विशेषज्ञ डॉ. दीपक कुमार से कोई काम नहीं लिया जाता. पोस्टमार्टम का कार्य ब्रज भूषण श्रीवास्तव नामक एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लिया जाता है, जो अभी कुंडवा चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित हैं. ब्रजभूषण से पोस्टमार्टम का कार्य लेने को लेकर कई बार अस्पताल परिसर में चिकित्सकों ने विरोध भी किया और हंगाम भी हुआ, लेकिन इसका कोई असर नही दिखा. संचिकाओं की डिलिंग में माहिर ब्रजभूषण के साथ स्वास्थ्य विभाग के कई आलाधिकारियों के साथ बेहतर संबंध होने की भी चर्चा हमेशा रहती है. हद तो तब हो जाती है, जब कुंडवा चैनपुर में पदस्थापित ब्रजभूषण विरोध करने वाले चिकित्सकों को देख लेने की धमकी भी दे देता है. महिला चिकित्सकों के ड्यूटी रोस्टर पर अगर नज़र डालते हैं तो वहां भी अनेक गड़बड़ियां सामने आ रही है. फरवरी व मार्च महीने का कोई ड्यूटी रोस्टर यहां नहीं बना और एक ही चिकित्सक डॉ. सीमा कुमारी सिन्हा के हवाले कर दिया गया. हालाकि सदर अस्पताल में चार महिला चिकित्सक पदस्थापित हैं, जिनमें डॉ. शकुंतला सिंह, डॉ. संध्या सिन्हा, डॉ. नूतन सिन्हा व डॉ. सीमा कुमारी सिन्हा का नाम शामिल है. डॉ. शकुंतला सिन्हा प्रतिदिन अस्पताल तो ज़रूर पहुंचती हैं, किन्तु जनवरी माह के ड्यूटी रजिस्टर पर इनका नाम नहीं है. शायद वह निजी प्रैक्टिस में अधिक व्यस्त रहती हैं. हालांकि डॉ. सीमा कुमारी ने कई बार सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को पत्र लिखकर ड्यूटी रोस्टर में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मेडिसीन ओपीडी पर अगर नज़र डालते हैं, तो यहां भी अनेक मामले सामने आते हैं. मेडिसीन ओपीडी का कार्य डॉ. टीपी सिंह व डॉ. अवधेश कुमार के जिम्मे है. डॉ. टीपी सिंह अधिक समय पीओसी में ही देते हैं. ओपीडी व इमरजेंसी सेवा का भी वही हाल है और पिछले डेढ़ महीने में एक भी ओपीडी व इमरजेंसी का कार्य बेहतर तरीके से नहीं हुआ है. अगर ज़िले में निजी नर्सिंग होम नहीं होता तो स्थिति और बेकार होती. पूरे बिहार में 36 वें स्थान पाने वाला ज़िले का स्वास्थ्य विभाग इन्हीं सब कारणों से हमेशा सुर्खियों में रहता है. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. सचिदानन्द सिंह भी इस मामले में पीछे नहीं हैं और वे गोपालगंज के कुचाईकोट में अपनी निजी प्रेक्टिस करते हैं. प्रत्येक बृहस्पतिवार को वे गोपालगंज में रहते हैं और इनकी हाजरी सदर अस्पताल में बनती है. इसकी शिकायतें भी अस्पताल के कई चिकित्सकों द्वारा ज़िलाधिकारी अभिजीत सिन्हा से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस बीच ज़िलाधिकारी के ओएसडी अनुराग कौशल सिंह ने पूछे जाने पर बताया कि सदर अस्पताल से जुड़े अनेक मामलों की जांच की जा रही है. कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग सुधरने को तैयार नहीं है और अनेक गड़बड़ियां खुलेआम हो रही है.

ओपीडी व इमरजेंसी सेवा का भी वही हाल है और पिछले डेढ़ महीने में एक भी ओपीडी व इमरजेंसी का कार्य बेहतर तरीके से नहीं हुआ है. अगर ज़िले में निजी नर्सिंग होम नहीं होता तो स्थिति और बेकार होती. पूरे बिहार में 36 वें स्थान पाने वाला ज़िले का स्वास्थ्य विभाग इन्हीं सब कारणों से हमेशा सुर्खियों में रहता है.

feedback@chauthiduniya.com

विक्रेता के द्वारा बिहार सरकार के सिंचाई विभाग के नहर की ज़मीन को भी बेच दिया. जब इस मामले को वार्ड पार्षद श्याम कुमार जायसवाल ने खोजबीन की तोस, इस बड़े घपला का उजागर हुआ.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

सीमांचल में खनन क़ानून बेअसर

नीरज कुमार सिंह

सुशासन की सरकार सरकारी राजस्व की वसूली और अवैध कारोबार की रोकथाम का चाहे लाख दावे करे, लेकिन सीमांचल एवं कोशी इलाक़े की ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. खनन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी बिहार सरकार द्वारा बनाये गए खनन क़ानून को ठेंगा दिखाते हुए ज़िला खनन कार्यालय से स्टॉकिस्ट लाइसेंस प्राप्त किए बग़ैर अवैध रूप से स्टोन चिप्स और बालू जैसे लघु खनिज का भंडारण एवं बिक्री का करोबार कर रहे हैं. मालूम हो कि, बिहार सरकार ने बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली–1972 के नियम 49 (1) एवं बिहार मिनरल्स (प्रिवेसन ऑफ इलिगल माइनिंग ट्रांसपोटेशन एवं स्टोरेज) नियमावली 2003 के निमय 7 (1) के तहत खान एवं भूतत्व विभाग से स्टॉकिस्ट लाइसेंस प्राप्त किये बग़ैर अवैध रूप से लघु खनिज जैसे, स्टोन चिप्स और बालू इत्यादि के भंडारण एवं इसके बिक्री पर प्रतिबंध का क़ानून बना रखा है.

इस क़ानून में सज़ा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान है. इन लघु खनिजों के भंडारण एवं बिक्री हेतु ज़िला खनन कार्यालय से इसके कारोबारी को एलमएफफार्म में अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है. जानकारी के अनुसार सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार समेत पूरे कोशी में ऐसे कारोबारियों की संख्या लगभग हज़ारों में है, जिन्हें ज़िला खनन कार्यालय से एलमएफ फार्म के अंतर्गत स्टॉकिस्ट लाइसेंस प्राप्त नहीं है. वहीं राष्ट्रीय उच्चपथ, स्टेट पथ, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना और पुल योजना के अंतर्गत लघु खनिजों मसलन, स्टोन चिप्स और बालू का भंडारण संवेदकों द्वारा प्लाट व अन्य जगहों पर किया जाता है, इसके लिए भी स्टॉकिस्ट लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है. हालांकि, इसके विपरीत बड़े–बड़े संवेदक पूर्णिया के डंगराहा में कार्य कर रही एजेंसी कोमेक प्राइवेट लिमिटेड कुर्सेला–फारबिसगंज पथ में कार्य कर रहे चड्ढा एंड चड्ढा कंपनियों द्वारा इस क़ानून की धज्जियां उड़ाई गई है और लाखों के सरकारी राजस्व का चूना लगाया गया है. ज़िला खनन कार्यालय से स्टॉकिस्ट लाइसेंस प्राप्त किए बग़ैर स्टोन चिप्स का भंडारण एवं बिक्री का प्रमुख केंद्र वर्तमान में पूर्णिया का गुलाबबाग़ और खुश्कीबाग़ बना हुआ है, जहां कुछ कारोबारी पिछले दस वर्षों में करोड़ों रुपये की कमाई की है. उक्त कारोबारियों के पास न तो स्टॉकिस्ट लाइसेंस है और न ही वेट लाइसेंस व ट्रेडर्स लाइसेंस. इन कारोबारियों द्वारा बंगाल के दालकोला व पाकुड़ में स्टोन चिप्स, सिलीगुड़ी में बेड मिसाली स्टोन को डंप करके रखा जाता है, जिसे रातों–रात ओवरलोडेड ट्रकों द्वारा पूर्णिया के गुलाबबाग, खुश्कीबाग समेत सीमांचल एवं कोशी के अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है. जानकारी के अनुसार ऐसे कारोबारियों में प्रदीप नारनौली एवं ज्वाला गुप्ता का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है. प्रदीप नारनौली के द्वारा गुलाबबाग मार्केटिंग गेट, दमका चौक गुलाबबाग भारत पेट्रोल पंप के पीछे निज आवास पर पाकुड़ स्टोन चिप्स का भंडारण एवं बिक्री किया जाता है.

वहीं ज्वाला गुप्ता एवं प्रदीप नारनौली के द्वारा गुलाबबाग़ बाज़ार समिति गेट के सामने बस पड़ाव को अतिक्रमण कर इस कारोबार को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है. फिलहाल हालत यह है कि सीमांचल के राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य पथ को अतिक्रमण करके इस धंधे को बड़े

प्रणव कुमार

लघु खनिजों के भंडारण एवं बिक्री हेतु ज़िला खनन कार्यालय से इसके कारोबारी को एलमफफार्म में अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है. जानकारी के अनुसार सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार समेत पूरे कोशी में ऐसे कारोबारियों की संख्या लगभग हज़ारों में है.

पैमाने पर किया जा रहा है. कभी–कभी इस कारोबार के चलते पूर्णिया जीरो माईल, गुलाबबाग मार्केटिंग गेट के सामने एवं अन्य जगहों पर घंटों जाम लगे रहते है एवं इसमें प्रयुक्त जेसीबी लोडर के उपयोग से उड़नेवाले पत्थर, धूलकणों से दिन में ही अंधेरा छा जाता है. राष्ट्रीय उच्च पथ से गुजरनेवाले राहगीरों से लेकर गुलाबबाग़ मंडी पहुंचने वाले व्यवसायी अकारण ही श्वास रोग से ग्रसित हो रहे है. ज़िला प्रशासन के नाकों तले हो रहे इस प्रकार के अवैध कारोबार को लेकर स्थानीय लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं. वैसे पूर्णिया खनन कार्यालय में खान निरीक्षक सह सक्षम पदाधिकारी लक्ष्मण राय को पदभार ग्रहण किए कुछ ही महीना हुआ है और राजस्व वसूली को लेकर इनकी कार्यक्षमता काबिल–ए– तारीफ़ है. उन्होंने सरकारी राजस्व के हित को लेकर ऐसे कारोबारियों पर शीघ्र क़ानूनी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं. ग़ौरतलब है कि पूर्णिया खनन कार्यालय के अंतर्गत ही अररिया, किशनगंज एवं पूर्णिया ज़िला आता है. वैसे पूर्णिया में भारतीय प्रशासनिक सेवा के नव नियुक्त तेज तर्रार युवा अनुमंडल पदाधिकारी प्रणव कुमार ने राजस्व संग्रह और अवैध कारोबारियों पर शीघ्र लगाम लगाने की बात कही है.

feedback@chauthiduniya.com

कब पकड़े जाएंगे ज़मीन घोटाले के दोषी

राकेश कुमार झा | अफसाना परवीन | डीएम एम.सरवणन | श्याम कुमार जायसवाल | जमीन का नज़री–नक्शा

उपेंद्र यादव

जी हां, एक और घपला. एक ऐसे ईमानदार पदाधिकारी के रहते हो गई, जिन्हें लोग मिस्टर क्लीन के नाम से जानते हैं. यह गड़बड़ी नगर परिषद अररिया द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन के लिए क्रय की गई ज़मीन में हुई है. सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस ज़मीन की राशि का भुगतान करने के लिए अनुशंसा ज़िलाधिकारी ने ही किया है. इससे पहले इस ज़िले में क़रीब 30 करोड़ का डेहटी पैक्स घोटाला हुआ है. जिसमें अनुशंसा करने वाले तत्कालीन डीडीसी साज़िद अहमद तलहा सहित छह बीडीओ को भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है. अब लोगों के बीच यह चर्चा है कि मनरेगा में कथित अनियमितता के आरोप में तत्कालीन डीडीसी उदय कुमार सिंह मिस्टर क्लीन कहलाने वाले अररिया के डीएम एम. सरवणन के अनुशंसा पर वे निलंबित हुए. नगर परिषद अररिया की सशक्त स्थाई समिति के निर्णय पर 12 वीं वित्त आयोग मद की राशि से एक एकड़ 91 डिसमिल ज़मीन शहर के वार्ड सं. चार ह्रदय नगर स्थित ओम प्रकाश भगत व इनकी धर्म पत्नी राजकुमारी देवी से दो अलग–अलग डीड सं.8141 व 8142 दिनांक 3 अगस्त 2010 को 57 लाख

नगर परिषद

30 हज़ार 191 रुपये में मौजा ह्रदय नगर, थाना सं.199 खाता सं. 83 ,खेसरा 796 जमाबंदी सं.577,रकबा एक एकड़ 37 डिसमिल एवं मौजा ह्रदय नगर, थाना सं.199 खाता सं. 05 ,खेसरा 776 जमाबंदी सं.492,रकबा 54 डिसमिल ज़मीन ख़रीद की गई, लेकिन विक्रेता के द्वारा बिहार सरकार के सिंचाई विभाग के नहर की ज़मीन को भी बेच दिया. जब इस मामले को वार्ड पार्षद श्याम कुमार जायसवाल ने खोजबीन की तो इस बड़े घपला का उजागर हुआ.

मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले अररिया डीएम एम. सरवणन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है. हालांकि इससे पूर्व अररिया सीओ तैयब आलम साहिदी ने अपनी जांच रिपोर्ट में, जहां 35 डिसमिल ज़मीन कम बताया, वहीं 17 डिसमिल ज़मीन सरकारी नहर के बेचे जाने का भी उल्लेख किया है. इस जांच रिपोर्ट के बाद ही डीएम सरवणन ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है. उधर ज़मीन विक्रेता द्वारा राशि जमा कर दी गई है, लेकिन करीब दो साल तक सरकारी राशि को रखने, बिक्री की गई ज़मीन पर लगातार खेती कर उपज रखने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 02 अप्रैल–08 अप्रैल 2012

www.chauthiduniya.com

पर्दे के पीछे के समाजवादी नायक

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

राजेंद्र केवल प्रवक्ता ही नहीं थे. वह मुलायम के सारथी भी थे. मुलायम के बुरे दिनों में भी वह अपने नेताजी की हौसला अफ़ज़ाई करते रहे. ख़ासकर, 2007 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो मुलायम बुरी तरह से टूट गए थे. ऐसे समय में राजेंद्र चौधरी उनके लिए उम्मीदों का आसमान बन गए. वह बहुजन समाज पार्टी सरकार की प्रत्येक ख़ामी को मीडिया के माध्यम से उभारते रहे.

अजय कुमार

अखिलेश सिंह की ताजपोशी हो गई. चौतरफ़ा उनकी वाहवाही हो रही है. उनकी जीत में कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कुछ पर्दे के सामने थे, तो कई ऐसे भी थे जो पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका का निर्वाहन कर रहे थे. बस, फ़र्क़ इतना था कि पर्दे के सामने के लोगों को सबने देखा और समझा, लेकिन पर्दे के पीछे के चेहरे कभी चर्चा में नहीं आए. ऐसे कई चेहरे थे, लेकिन दो नाम जो सबकी ज़ुबान पर नतीजे आने के बाद सिर चढ़ कर बोले, वे थे खाटी समाजवादी दिग्गज नेता और सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी एवं युवा जोश आशीष यादव उर्फ़ सोनू का. इन दोनों की बेहतर ट्यूनिंग ने ऐसा समा बांधा कि नतीजे आने के बाद समाजवादी दंग और विपक्षी हैरान रह गए. मीडिया को जिस तरह से राजेंद्र चौधरी ने मैनेज किया, वह न केवल तारीफ़ की बात थी, बल्कि एक अचूक रणनीति का हिस्सा भी था. ख़बरनवीसों को मैनेज करने में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दिन-रात एक कर दिए थे. इसका प्रभाव भी देखने को मिला. शायद यही वजह थी, जब नतीजे आए तो मायूस मायावती को तो यहां तक कहना पड़ गया कि मीडिया की भूमिका बसपा को हराने में महत्वपूर्ण रही. शायद वह यह कहकर संदेश देना चाहती थीं कि सपा की जीत में मीडिया ने महत्वूर्ण भूमिका निभाई है.

जननायक जय प्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह जैसे तमाम नेताओं के सानिध्य में रह चुके राजेंद्र चौधरी ने राजनीति की सीढ़ियां साठ के दशक में छात्र जीवन से ही चढ़नी शुरू कर दी थीं. मेरठ विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए एलएलबी तक की शिक्षा ग्रहण की. इस दौरान वह छात्र संघ चुनाव में महामंत्री और अध्यक्ष भी चुने गए. 1967 में चौधरी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की यूथ इकाई समाजवादी युवजन सभा के संयुक्त राज्यमंत्री बने. यह चौधरी के राजनीतिक जीवन का अहम पड़ाव साबित हुआ. शांत स्वभाव और नाप-तौल कर बोलने वाले राजेंद्र चौधरी ने 1968 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले हो रहे किसान आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा. इसके बाद वह सुर्ख़ियों में आ गए. इसी दौरान उनकी नज़दीकियां चौधरी चरण सिंह से और भी बढ़ गईं. वह चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल से जुड़कर 1974 में जाट बाहुल्य गाज़ियाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़े. चौधरी स्वयं जाट बिरादरी से आते हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा. 1975-76 में जेपी के आंदोलन में जेल गए और क़रीब डेढ़ साल का समय चौधरी का जेल में ही बिताना पड़ा.

आपातकाल के बाद 1977 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जनता पार्टी के टिकट से वह एक बार फिर गाज़ियाबाद से चुनाव मैदान में उतरे. उन्हें 62 हज़ार से अधिक वोटों से जीत मिली. इसके बाद राजेंद्र चौधरी की नज़दीकी मुलायम सिंह यादव से हो गई. यह वह दौर था जब मुलायम का सिक्का उत्तर प्रदेश में चल पड़ा था. उनके साथ कई समाजवादी नेता जुड़ते जा रहे थे. इसी में से एक थे राजेंद्र चौधरी. खांटी समाजवादी विचारधारा के राजेंद्र चौधरी और मुलायम का जब आमना-सामना हुआ तो दोनों ने एक-दूसरे को काफ़ी प्रभावित किया. राजेंद्र पढ़े-लिखे तो थे ही, इसके साथ-साथ वह विभिन्न समाचार पत्रों में लेखन का काम भी करते थे. वह उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हक़ीक़त और जनता की नब्ज़ को अच्छी तरह से पहचानते थे. मुलायम को प्रवक्ता के पद पर एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, जो मीडिया को मैनेज करने की क्षमता रखता हो. राजेंद्र की योग्यता को भांप कर कुछ समय बाद ही मुलायम ने उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बना दिया.

चौधरी की लाइफ स्टाइल बेहद साधारण थी. वह न तो कभी पांच सितारा होटलों में जाते और न ही महंगी दावतों का हिस्सा बनते. महत्वाकांक्षा को उन्होंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. वह अपना काम पूरी लगन से करते. पार्टी के प्रति समर्पण क्या होता है, यह बात राजेंद्र चौधरी से सीखी जा सकती है. उनको जो ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, उसका निर्वाहन वह बाख़ूबी करते हैं. अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करने वाले राजेंद्र मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति हैं. सबसे वह सामान्य व्यवहार करते हैं. उनकी नज़र में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता. संगठन के कार्यों में उन्होंने कभी दख़ल अंदाज़ी नहीं की, तो नेताजी के क़रीब आने की चाहत भी उनमें कोई ख़ास नहीं दिखी. सरकार से अधिक संगठन को प्रिय मानने वाले राजेंद्र चौधरी को 1989 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो राज्य एग्रो का चेयरमैन बनाया गया. राजेंद्र चौधरी उस दौर के व्यक्ति हैं, जब प्रेस नोट हाथ या फिर टाइप करके भेजे जाते थे. अक्सर वह समय कम होने पर हस्तलिखित विज्ञप्ति जारी कर देते थे. संचार क्रांति ने उनका काम काफ़ी आसान कर दिया है. समाजवादी पार्टी के समाचार, विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकों और संवाददाताओं के पास ई मेल के माध्यम से कुछ क्षणों में पहुंच जाते हैं. हालांकि राजेंद्र चौधरी को कंप्यूटर की कोई ख़ास जानकारी नहीं है, लेकिन यह कमी उनकी उड़ान को ब्रेक नहीं लगा पाई. उनके साथ जुड़कर काम करने वाले कंप्यूटर मास्टर आशीष यादव की मेहनत और राजेंद्र के समर्पण ने सपा की उम्मीद को पंख लगा दिए. लंबे समय से प्रवक्ता के पद पर विराजमान राजेंद्र ने इस बार विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकों को बुलाकर अखिलेश और मुलायम सिंह के इंटरव्यू कराए.

राजेंद्र केवल प्रवक्ता ही नहीं हैं. वह मुलायम के सारथी भी हैं. मुलायम के बुरे दिनों में भी वह अपने नेताजी की हौसला अफ़ज़ाई करते रहे. ख़ासकर, 2007 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो मुलायम बुरी तरह से टूट गए थे. ऐसे समय में राजेंद्र चौधरी उनके लिए उम्मीदों का आसमान बन गए. वह बसपा सरकार की प्रत्येक ख़ामी को मीडिया के माध्यम से उभारते रहे. कभी प्रवक्ता तो कभी नेताजी के नाम से उनकी विज्ञप्तियां मीडिया तक पहुंचती रहती थीं. समय-समय पर वह मुलायम को उनकी ताक़त का अहसास कराते रहते थे. जब आज़म ख़ां और अमर सिंह जैसे साथियों के जाने के कारण मुलायम दुखी थे, तब भी राजेंद्र चौधरी ने उनका ढांढस बंधाने का काम किया. जब मुलायम के मन में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का ख्याल आया तो उसे भी साकार करने के लिए वह बिना देर किए फ्रंट पर आ गए.

feedback@chauthiduniya.com

ख़बरनवीसों को मैनेज करने में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दिन-रात एक कर दिए थे. इसका प्रभाव भी देखने को मिला. शायद यही वजह थी, जब नतीजे आए तो मायूस मायावती को तो यहां तक कहना पड़ गया कि मीडिया की भूमिका बसपा को हराने में महत्वपूर्ण रही. शायद वह यह कहकर संदेश देना चाहती थीं कि सपा की जीत में मीडिया ने महत्वूर्ण भूमिका निभाई है. जननायक जय प्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह जैसे तमाम नेताओं के सानिध्य में रह चुके राजेंद्र चौधरी ने राजनीति की सीढ़ियां साठ के दशक में छात्र जीवन से ही चढ़नी शुरू कर दी थीं. मेरठ विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए एलएलबी तक की शिक्षा ग्रहण की.

बेरोज़गारी भत्ते पर उम्र का पेंच

चंद्रेश शर्मा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अखिलेश यादव ने पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता दिए जाने के वादे को निभाने का ऐलान कर दिया. लेकिन बेरोज़गारी भत्ते दिए जाने के ऐलान के बाद जब शिक्षित बेरोज़गारों को पता चला कि यह भत्ता 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को दिया जाएगा तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया. नौजवान स्वयं को ठगा महसूस करने लगे. हालांकि पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में इसका ज़िक्र पहले ही कर दिया था, लेकिन चुनाव प्रचार में इसे छिपाया गया. सत्ता मिलते ही समाजवादी पार्टी के तेवरों में धीरे-धीरे बदलाव आने लगा. हालांकि छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप दिए जाने की घोषणा से पार्टी ने किनारा नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जाने लगा है कि मुख्यमंत्री द्वारा इसमें भी कुछ ऐसे पेच लगाए जाएंगे, ताकि घोषणा पत्र में किए गए वादे भी पूरे हो जाएं और सरकार पर कोई आर्थिक दबाव भी न पड़े.

चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी नेताओं द्वारा जनसभाओं में बेरोज़गारों को भत्ता दिए जाने की घोषणा को बार-बार दोहराया जा रहा था, जिससे युवा वर्ग सपा की ओर तेज़ी से झुकने लगा. सात चरणों में हुए मतदान में आ रही रिपोर्टों से भाजपा और कांग्रेस ख़ुश नज़र आ रही थीं. मतदान प्रतिशत बढ़ने से उत्साहित भाजपा को आलाकमान 80-90 सीटों की उम्मीद हो चली थी. ये क़यास लगाए जाने लगे थे कि सपा को रोकने के लिए बसपा और भाजपा मिलकर सरकार बनाएंगे, तो दूसरी ओर राहुल गांधी बयान दे रहे थे कि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कम से कम सौ सीटें जीतना है. कांग्रेस गठबंधन में रालोद है ही. अति उत्साह में बयान देते हुए कह दिया था कि किसी एक दल को बहुमत न मिलने पर सपा के सहयोग से कांग्रेस और रालोद मिलकर सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री जयंत चौधरी को बनाया जा सकता है. मगर राजनीति के माहिर मुलायम सिंह यादव की निगाहें नौजवानों पर लगी हुई थीं. कोई भी राजनीतिक दल युवा शक्ति पर ध्यान देने की बजाय जातिगत समीकरणों पर ही अटका हुआ था. सपा सुप्रीमो ने एक साल पूर्व से ही इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था. अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में योजनाबद्ध तरीक़े से प्रोजेक्ट किया गया. अखिलेश यादव ने साइकिल यात्राओं से अपने पिता के नक्शे-क़दम पर चलना शुरू किया तो विशेष तौर पर ग्रामीणों में इसका ख़ासा असर दिखने लगा. चुनाव आते-आते अखिलेश यादव जनता के बीच उसकी नब्ज़ को पकड़ने में महारत हासिल कर चुके थे.

समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दसवीं पास छात्रों को टैबलेट और इंटर पास छात्रों को फ्री में लैपटॉप देने की घोषणा कर युवा वर्ग को पूरी तरह आकर्षित कर लिया, जिसके कारण मतदान में वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया. नौजवानों की भागीदारी से समाजवादी पार्टी का वोट अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया, जिससे पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया. प्रदेश में रोज़गार कार्यालयों में युवाओं की लंबी कतारें लग गईं. हज़ारों की संख्या में शिक्षित बेरोज़गार छात्र-छात्राएं पंजीयन के लिए उमड़ पड़े. सूत्रों की मानें तो यह सेवायोजन कार्यालय में प्रदेश में एक माह में जितने ज़्यादा पंजीयन हुए हैं, इतने कम समय में उतने पहले कभी नहीं हुए. शिक्षित बेरोज़गारों के अलावा बेरोज़गार प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय के तकनीकी पंजीयन केंद्र में इंजीनियर, पशु चिकित्सक, चिकित्सक, कला, विज्ञान, विधि एवं प्रोफेशनल डिग्री धारक निदेशालय में पंजीकरण कराने के लिए पात्र होते हैं. विभाग के लखनऊ कार्यालय के आंकड़ों के हिसाब से वर्ष 2006 में 2557, वर्ष 2007 में 2765, वर्ष 2008 में 2702, वर्ष 2009 में 2912, वर्ष 2010 में 3455, वर्ष 2011 में 3520 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था. प्रदेश के सभी ज़िलों में मुख्यमंत्री द्वारा बेरोज़गारी भत्ते को 35 से ज़्यादा की उम्र के लोगों को दिए जाने से निराशा का माहौल अवश्य है, लेकिन सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन कराने वाले नौजवानों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है. फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में सपा सरकार चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को इस तरह पूरा करना चाहती है कि सरकार पर आर्थिक बोझ भी न पड़े. चूंकि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह की नज़र 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर लगी है, इसलिए पार्टी का सोचना है कि प्रदेश में सपा के पक्ष में आया अप्रत्याशित समर्थन आगे भी जारी रहे.

feedback@chauthiduniya.com

धरती पुत्र बनाम दलित बेटी

दर्शन शर्मा

सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और बसपा सुप्रीमो कांशीराम के बीच उपजी सियासी प्रतिद्वंद्विता की कहानी बड़ी रोचक है. उन दिनों कांशीराम दलित चेतना जगा रहे थे. मायावती के सियासी गुरु कांशीराम ही रहे. कहते हैं कि 1991 के आम चुनाव में हुई हिंसा के कारण पूरे लखनऊ ज़िले में दोबारा चुनाव हुए थे. इस चुनाव में बसपा सुप्रीमो कांशीराम ने जहां मुलायम की मदद की थी, वहीं मुलायम सिंह ने भी कांशीराम को कभी सहारा दिया था. यही कारण था कि कांशीराम ने जसवंत नगर से बसपा से कोई उम्मीदवार मुलायम के ख़िलाफ़ नहीं उतारा था, जबकि ज़िले की हर विधानसभा सीट से बसपा ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे. कांशीराम इटावा में डेरा डाले हुए थे. मुलायम सिंह उनकी मेहमान नवाज़ी कर रहे थे. मुलायम की मदद से 1991 में इटावा से लोकसभा चुनाव जीतकर कांशीराम संसद पहुंचे थे. कांशीराम ने नारा दिया था, मिले मुलायम कांशीराम-हवा हो गए जय श्रीराम. यूपी में मुलायम-कांशीराम के मिलने से सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा ज़ोरों से होने लगी कांशीराम और मुलायम का गठजोड़ बहुत मज़बूत है. दलित और पिछड़ों का अगर यूपी में साथ रहा तो निश्चित ही न तो भाजपा कभी जीत पाएगी और न ही कोई दूसरी पार्टी. इसका फ़ायदा मुलायम सिंह ने 1995 में सरकार बनाकर उठाया. लेकिन माया और मुलायम में ज़्यादा दिनों तक नहीं बनी. आख़िरकार महत्वाकांक्षी मायावती ने सपा सरकार से हाथ खींच लिया. मुलायम सरकार अल्पमत में आ गई. मायावती अपने विधायकों को लेकर राज्य अतिथि गृह में थीं, लेकिन मुलायम सिंह के लोगों ने बसपा के कुछ विधायकों को अपने पाले में लाने का काफ़ी प्रयास किया. मायावती और मुलायम के विधायकों के बीच टकराहट होती रही. इस पर भाजपा ने बीच में आकर मुलायम के अरमानों पर पानी फेर दिया. उसने बसपा को समर्थन देकर दलित बेटी को कांशीराम के सामने ही पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आरूढ़ करा दिया. भाजपा और बसपा का गठबंधन रुक-रुककर चलता रहा, जिसमें भाजपा को कम और बसपा को ज़्यादा फ़ायदा हुआ. मायावती ने भाजपा को गच्चा दिया. अगले चुनाव में बसपा ने कांग्रेस से हाथ मिलाया. कभी इस पार्टी से, कभी उस पार्टी से हाथ मिलाते-मिलाते मायावती अपनी कूटनीति से 2002 में मुलायम को सत्ता में आने से रोकने के लिए फिर भाजपा से जा मिलीं. इस बार मायावती का क़द कांशीराम से बड़ा था. इस बीच कांशीराम का इंतक़ाल हो गया. बसपा की सर्वेसर्वा मायावती थीं. बसपा मुखिया मायावती ने 2007 में अकेले सोशल इंजीनियरिंग का दांव चलकर सभी दलों को पीछे कर दिया, जिसमें मुलायम बुरी तरह पराजित हुए. विधानसभा में मायावती के 206 विधायक जीतकर पहुंचे. मुलायम की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण रहा, सपा कार्यकर्ताओं की दबंगई और मुस्लिमों का मुलायम से मोहभंग. मीडिया ने माया सरकार के आने के पहले ही नतीजे घोषित कर दिए थे. मुलायम सिंह में यह ख़ूबी रही कि वह विरोधी के सामने हार नहीं मानते थे. नेता विपक्ष रहकर उनके तेवर देखते बनते थे. हालांकि मायावती भी मुलायम को टक्कर देने में पीछे नहीं रहीं. दोनों का मुक़ाबला कभी बराबरी पर छूटा, तो कभी कुछ अंतर से. मायावती का जहां दलितों पर एक छत्र राज रहा, वहीं मुलायम की मुस्लिमों पर पकड़ मज़बूत रही. दोनों पार्टियों के सुप्रीमो एक-दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में थे. कांग्रेस और भाजपा भी इस दौड़ में रहे, लेकिन उनका कोई वर्चस्व यूपी में क़ायम नहीं हो पाया. यूपी में चुनावी महाभारत सिर्फ़ धरती पुत्र और दलित बेटी के बीच सिमटकर रह गया. भाजपा और कांग्रेस हाशिये पर खिसकते रहे. मायावती की शैली जहां कमरे में आने से पहले जूते-चप्पल उतारने की रही, वहीं मुलायम ने कभी माननीयों के जूते-चप्पल नहीं उतरवाए. मायावती ने जहां ब्यूरोक्रेट्स को धमकाकार रखा, वहीं मुलायम सिंह की ब्यूरोक्रेट्स से शालीनता और प्रेम भाव से काम कराने की शैली रही. हालांकि मुलायम सिंह के सामने ऐसे मौक़े भी आए जब उनके माननीयों को सलाख़ों के पीछे जाने की नौबत आ गई तो उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन जब मायावती सरकार में माननीय फंसे तो माया ने उनसे किनारा करना ही उचित समझा. उन्होंने एक के बाद एक क़रीब 110 विधायकों का टिकट ही काट दिया. मुलायम ने जहां किसी मुद्दे को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया, वहीं मायावती ने मुलायम को कभी बख्शा नहीं. स्वयं मुलायम सिंह उनसे शिष्टाचारवश मिलने भी गए. मायावती ने कभी मुलायम से न मिलने की ठान रखी है. मायावती जहां मंत्रियों को हमेशा मीडिया से दूर रहने के लिए आगाह करती रहीं और ख़ुद मीडिया से रूबरू होने से कतराती रहीं, वहीं मुलायम सिंह ने कभी भी मीडिया से परहेज़ नहीं किया. उन्होंने मीडिया पर पूरा ध्यान दिया. आख़िरकार 2012 के चुनाव में हार जाने के बाद मायावती ने मीडिया पर ठीकरा फोड़ा कि मीडिया के कारण ही बसपा हारी है. मीडिया से दूरी बनी रहने के कारण विधान भवन के गलियारों में सन्नाटा तभी टूटता था, जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाता था. सत्र के दौरान ही मंत्री ख़ाली वक़्त में अपने कार्यालय में बैठते थे. ब्यूरोक्रेट्स के मामले में भी दोनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में जातिगत आधार पर अच्छे महकमों में अफ़सरों की तैनाती हुई. इसकी वजह से दूसरे वर्गों पर भी प्रभाव पड़ा. मुलायम सरकार में जहां यादवों को तरजीह मिली, वहीं मायावती सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों के अफ़सरों की पौ बारह देखी गई. जातिगत आधार पर दोनों सरकारों में कर्मचारियों की रिक्तियां भरती रहीं.

दलित और पिछड़ों का अगर यूपी में साथ रहा तो निश्चित ही न तो भाजपा कभी जीत पाएगी और न ही कोई और पार्टी. इसका फ़ायदा मुलायम सिंह ने 1995 में सरकार बनाकर उठाया. लेकिन माया और मुलायम में ज़्यादा दिनों तक नहीं बनी. आख़िरकार महत्वाकांक्षी मायावती ने सपा सरकार से हाथ खींच लिया. मुलायम सरकार अल्पमत में आ गई. मायावती अपने विधायकों को लेकर राज्य अतिथि गृह में थीं, लेकिन मुलायम सिंह के लोगों ने बसपा के कुछ विधायकों को अपने पाले में लाने का काफ़ी प्रयास किया. मायावती और मुलायम के विधायकों के बीच टकराहट होती रही. इस पर भाजपा ने बीच में आकर मुलायम के अरमानों पर पानी फेर दिया.

इस बार की सरकार में शायद मायावती और मुलायम की यह लड़ाई ख़त्म हो सकती है. जनता का रुख़ बदल गया है. जनता ने एक बार जहां बसपा को बहुमत से जिताया है, वहीं दूसरी बार सपा सरकार को भी हर वर्ग से वोट आया है. मायावती जहां उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वहीं मुलायम सिंह तीन बार मुख्यमंत्री हुए. यह बात तब बराबरी पर छूट जाती है कि मुलायम की जगह उनका बेटा मुख्यमंत्री बना है यानी मुख्यमंत्री बनने के मामले में भी सपा और बसपा की बराबरी है. मुलायम सिंह यादव ने भी टीचर से नेतागिरी शुरू की थी, वहीं मायावती ने भी अध्यापिका की नौकरी छोड़ने के बाद राजनीतिक सफ़र शुरू किया था. मायावती दलित जाति में पैदा हुईं, वहीं मुलायम पिछड़ी जाति के यादव हैं. मुलायम सिंह ने समाजवाद को बढ़ाने के लिए जहां लोहिया पार्क की स्थापना कराई, वहीं मायावती ने दलित महापुरुषों की याद में कई ऐतिहासिक पार्क बनवा दिए. ख़ज़ाने को ख़ाली करने में सपा और बसपा का एक ही हाल रहा. लेकिन मायावती-मुलायम की हार-जीत की सियासी लड़ाई केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रही. मायावती और मुलायम के सांसदों की संख्या भी लगभग समान है. दोनों पार्टियों के प्रमुखों की केंद्र में भी उठा-पटक जारी रही है. जब मुलायम सिंह ने यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया तो, माया ने भी लपककर केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन देने में गुरेज़ नहीं किया. विधानसभा चुनाव के बाद अब जब मायावती राज्यसभा का पर्चा भरकर दिल्ली कूच कर गईं, वहीं मुलायम सिंह ने भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री का ताज पहनाकर लोकसभा की सियासत की डगर पकड़ ली है. आय से अधिक संपत्ति के मामले पर मुलायम सिंह का मामला कोर्ट तक गया, वहीं मायावती भी इससे अछूती नहीं हैं. मुलायम सरकार में दाग़ियों की जब बाढ़ आई तो माया सरकार में दाग़ियों ने अपना रुतबा दिखाया. मुलायम सिंह ने जहां अपने पैतृक गांव सैफ़ई को चमकाने में कोई कोताही नहीं बरती है, वहीं मायावती ने बादलपुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है.

feedback@chauthiduniya.com

जेल मंत्री सलमान से मिलना चाहते हैं

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले राजा भइया ने कहा है कि जेल मंत्री बनना बहुत अच्छा लग रहा है. वह जेल से वाक़िफ़ हैं. वह क़रीब 26 महीने जेल में रहे हैं. उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि किस तरह जुर्माने की थोड़ी सी रक़म जमा न कर पाने के कारण लोग जेलों में बेवजह सलाख़ों के पीछे सड़ते रहते हैं. जेल मंत्री बनने के बाद उन्हें वो दिन याद आ गए, जब उन्हें जेल की कोठरी में बंद रहना पड़ा था. जेल का जीवन कितना दुरूह होता है. वह जेल की हर गतिविधि को नज़दीक से देख चुके हैं. राजा भइया ने मंत्री पद संभालते ही क़ैदियों के दुख-दर्द को बांटने के लिए पैरवी शुरू कर दी है. उन्होंने जेलों में सज़ा काट चुके लोगों की रिहाई के लिए फिल्म अभिनेता सलमान ख़ान से मिलने की इच्छा जताई है. सलमान ख़ान बीइंग ह्यूमन नाम से स्वयंसेवी संस्था चलाते हैं, जिसके माध्यम से वह क़ैदियों की मदद करते हैं. यूपी की जेलों में अपनी सज़ा की मियाद पूरा कर चुके क़ैदी जुर्माना अदा नहीं करने के कारण जेल में ही रहने के लिए मजबूर हैं. वह सलमान ख़ान से मिलकर जेल में मियाद पूरी कर चुके क़ैदियों के बारे में विचार-विमर्श करेंगे. राजा भइया ने कहा, अगर सलमान ख़ान इस मामले में पहल करते हैं, तो उन्हें ख़ुशी होगी. सलमान ख़ान ही नहीं, बल्कि वह उन सभी स्वयंसेवी संगठनों की मदद लेने और बात करने को तैयार हैं, जो इस काम में आगे आएगी. फ़िलहाल जेल में सज़ा की मियाद पूरी कर चुके क़ैदियों की संख्या तीन सौ है, जिनमें अधिकतर पांच केंद्रीय जेलों में बंद हैं. इन क़ैदियों की रिहाई के लिए पचास लाख रुपये ख़र्च होंगे. इसके लिए राज्य सरकार में कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए वह स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील कर रहे हैं.

जेल मंत्री का कहना है, जेल सुधार गृह होता है, लेकिन इसे प्रताड़ना घर बना दिया गया है. उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं होता. उनके खाने, पहनने और इलाज का कोई इंतज़ाम नहीं होता, जिसके कारण क़ैदियों की असमय मृत्यु भी हो जाती है. वह इन क़ैदियों के लिए जल्द से जल्द रिहाई कराने की कार्रवाई करेंगे. वहीं अब जेलों को यातना घरों में तब्दील नहीं होने देंगे. अब देखना है कि सज़ा काट चुके क़ैदियों की रिहाई कितनी जल्दी हो पाती है.

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

शिवपाल ने माया के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बहुजन समाज पार्टी के ख़िलाफ़ बदले की कार्रवाई नहीं करने के ऐलान के बीच सूबे के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने पद संभालते ही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की स्वप्निल परियोजनाओं के औचित्य पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं. उन्होंने विभाग का कार्यभार संभालने के फ़ौरन बाद

लखनऊ तथा नोएडा में चल रही ख़ास अहमियत वाली परियोजनाओं के निर्माण तथा कुछ इमारतों को ढहाए जाने और दोबारा बनाए जाने के औचित्य पर प्रश्न उठाकर बसपा सुप्रीमो मायावती के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. पहले ही दिन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यादव ने उनसे इस मामले पर जवाब देने को कहा. लोक निर्माण मंत्री ने इन पार्कों और स्मारकों के निर्माण के औचित्य पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जो माया शासन में सुर्ख़ियों में रही थी. इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर इस निर्माण पर हुए ख़र्च तथा ठेका आवंटन में धांधली के आरोपों पर ग़ौर किया जाएगा.

शिवपाल का कहना था कि एक पार्क और स्मारक के निर्माण के लिए कारागार, एक सरकारी कॉलोनी तथा अनेक कार्यालयों को ढहाए जाने का कोई औचित्य होना चाहिए. अधिकारियों से इस पार्क के निर्माण के लिए अनेक लोगों को विस्थापित किए जाने के औचित्य के बारे में भी पूछा गया. साथ ही उनसे इस बात का भी जवाब मांगा गया कि इस काम के लिए किन हालात में इजाज़त दी गई थी. ग़ौरतलब है कि मायावती सरकार लखनऊ तथा नोएडा में पार्कों, स्मारकों तथा मूर्तियों की स्थापना पर हज़ारों करोड़ रुपये ख़र्च करने को लेकर लगातार निशाने पर रही थी.

संजय सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com

माया के नौ रत्न हटे

अखिलेश सरकार ने सबसे पहले मायावती के उन रत्नों की ख़बर ली, जो कई वर्षों से मलाईदार पदों पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे. माया सरकार में नौ रत्नों के नाम से नवाज़े जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स का तिलस्म आख़िर टूट गया, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही अखिलेश यादव ने उन्हें पंचम तल से हटा दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अपर कैबिनेट सचिव, चार प्रमुख सचिव, तीन सचिव को एक साथ ही हटा दिया गया. इन अफ़सरों में रवींद्र सिंह, फ़तेह बहादुर, नेतराम, राजप्रताप सिंह, दुर्गाशंकर मिश्र, नवनीत सहगल, अनिल संत और चंद्रभानु शामिल हैं. इसके अलावा कैबिनेट सचिव पद से रिटायर हो चुके शशांक शेखर सिंह के स्टाफ अफ़सर एवं आईएएस शशि प्रकाश गोयल को भी किनारे कर दिया गया है. इन अफ़सरों की गिनती माया सरकार में ख़ास अफ़सरों में थी. हटाए गए कैबिनेट सचिव रवींद्र सिंह प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के साथ-साथ लोक निर्माण एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव भी थे. वह सीईओ यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास निबंधन विभाग भी देख रहे थे. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राजप्रताप सिंह राज्य सलाहकार परिषद के सचिव भी थे. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री दुर्गाशंकर मिश्र के पास नगर विकास विभाग भी था. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फ़तेह बहादुर नियुक्ति, कार्मिक एवं सतर्कता देखते थे. कैबिनेट सचिव के बाद सबसे ताक़तवर थे सचिव नवनीत सहगल, जिनके पास शहरी समग्र विकास विभाग, सूडा, ऊर्जा, अपर स्थानिक आयुक्त एमडी पावर, कॉरपोरेशन तथा एमडी यूपीएसआईडीसी कानपुर जैसे अहम विभाग थे. सचिव मुख्यमंत्री अनिल संत बेसिक शिक्षा, सचिव चंद्रभानु वाणिज्यकर, शशि प्रकाश गोयल कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह के प्रमुख स्टाफ अफ़सर थे. वे राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी के परियोजना निदेशक भी थे.

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

फ़ैज़ाबाद

मुग़लकालीन इमारतें विलुप्त हो रही हैं

राकेश कुमार यादव

पर्यटन और पुरातत्व विभाग की उदासीनता के कारण फ़ैज़ाबाद जनपद की ऐतिहासिक मुग़लकालीन इमारतें गुलाबबाड़ी, बहू बेगम का मोती महल और मक़बरे का अस्तित्व संकट में पड़ गया है. पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने के साथ-साथ अतिक्रमण और अवैध क़ब्ज़ों के कारण मुग़लकालीन ऐतिहासिक इमारतें धराशायी होती जा रही हैं. इन इमारतों की दुर्दशा की तरफ़ से पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन ने भले ही आंखें मूंद ली हों, लेकिन पर्यटक इससे काफ़ी आहत हैं. ये मुग़लकालीन इमारतें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानी पहचानी जाती हैं. इन्हें देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते थे, परंतु अब पर्यटकों की बात तो दूर, यहां के स्थानीय लोग भी इन्हें देखने नहीं आना चाहते हैं.

ऐतिहासिक मुग़लकालीन मोती महल क़रीब 20 एकड़ भूमि में स्थित था, जबकि अब 5-6 एकड़ में इसके अवशेष हैं. धराशायी हो चुका यह महल चारों ओर से अतिक्रमण से घिरा हुआ है. यहां बसे लोगों ने महल की पुरानी दीवारों को तोड़कर अपना आशियाना बना लिया है. शिया सेंट्रल बोर्ड महल को वक्फ़ की संपत्ति बताता है. इसके सूचनार्थ दीवारों पर नोटिस बोर्ड भी लगाए गए हैं. पिछले 10-12 वर्षों से इस महल को हड़पने की कोशिशें कुछ ज़्यादा ही की जा रही हैं, जिसके कारण जीर्ण-शीर्ण हो चुके महल के कुछ कमरों पर छत भी डाल दी गई और महल के आंगन में एक इमारत के निर्माण का भी प्रयास किया गया. यहां के समाजसेवियों की शिकायतों की वजह से यह कार्य पूरा नहीं हो सका. फिर भी महल के एक छोर पर यूनिटी वेलफेयर सोसायटी स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, जबकि यहां बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं. समाजसेवी अशोक श्रीवास्तव बताते हैं कि मोती महल की बेशक़ीमती भूमि को वक्फ़ के ही कुछ मुतवल्लियों ने टुकड़ों में बेच दिया है. अब वर्तमान मुतवल्ली भी इस महल के टूटे कमरों पर छत डलवाकर स्कूल के नाम पर और आंगन में एक नई इमारत को मस्जिद का रूप देकर इसे हड़प लेना चाहते हैं.

मोती महल के बारे में फ़ैज़ाबाद गजेटियर 1960 के मुताबिक़, लगभग 250 वर्ष पूर्व नवाब सादात ख़ान के भतीजे मिर्ज़ा मुहम्मद मुक़ीम उर्फ़ अब्दुल मंसूर ख़ान सफ़दरजंग ने बसाया था. फ़ैज़ाबाद को सफ़दरजंग के बेटे शुजाउद्दौला द्वारा सूबा अवध की राजधानी बनाए जाने के बाद अपनी बेगम इमतुल जेहरा के लिए मोती महल का निर्माण कराया था. जेहरा को राजमाता का दर्जा प्राप्त था. ईरानी महिला इमतुल जेहरा मुग़ल सल्तनत के वज़ीर इसहाक़ ख़ान की बेटी थीं. उनका लालन-पालन इसहाक़ ख़ान के क़त्ल के बाद मुग़ल बादशाह मुहम्मद शाह ने अपनी बेटी की तरह किया था. बादशाह के इंतक़ाल के बाद इमतुल जेहरा से नवाब शुजाउद्दौला ने निकाह कर उन्हें बेगम का दर्जा दिया. बाद में यही इमतुल जेहरा बहू बेगम के नाम से जानी गईं, जिनका इंतक़ाल 1815 में हुआ. नवाब ने अपने लिए स्वयं भी एक स्मारक बनवाया था, जो सरकार द्वारा इस समय देखभाल में है. इसमें केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग का कार्यालय स्थापित है. इसे अफ़ीम कोठी के नाम से भी जाना जाता है. इस पुरानी इमारत में दिलकुशा महल के अवशेष देखे जा सकते हैं. इसकी घेरे की दीवारें गिर गई हैं. जेहरा 1743 में नवाब से ब्याही गई थीं. वह नवाब की मृत्यु 1775 के बाद तक फ़ैज़ाबाद में रहीं. उनका मुख्य निवास मोती महल रहा. बहू बेगम को मृत्यु के बाद शहर के दक्षिण जवाहर बाग़ स्थित मक़बरे में दफ़नाया गया. यह मक़बरा अवध क्षेत्र के सबसे सुंदर, आकर्षक और भव्य इमारत के रूप में जाना जाता है. प्रशासनिक उपेक्षा के कारण मक़बरे का मुख्य गेट और चहारदीवारी अतिक्रमण से घिरी हुई है. इस मक़बरे की तामीर के लिए बेगम ख़ुद तीन लाख रुपये छोड़ गई थीं. इसी धनराशि से दराब अली ख़ान के बाद इसका निर्माण वकील पनाह अली और बाद में मिर्ज़ा हैदर द्वारा जारी रखा गया. इन सबके बाद निर्माण कार्य पूरा कराने का ज़िम्मा सरकार ने स्वयं लिया और यह कार्य 1901 तक चला. मोती महल की भूमि को हड़पने का सबसे बड़ा खेल उस समय उजागर हुआ, जब 2000 में इसके मुतवल्ली तबील अब्बास के साथ मिलकर ऑल इंडिया माइनॉरिटीज वेलफेयर एक्शन ग्रुप संस्था के नाम से गुलरेज़ आब्दी द्वारा एक लाख एक हज़ार एक सौ एक रुपये के एवज में इसका तीस वर्षीय एग्रीमेंट कर संस्था को क़ब्ज़ा करा दिया गया. इस विक्री पट्टे की शिकायत यहां के पेश इमाम इब्ने हसन द्वारा की गई तो संरक्षित इमारत के मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी अनिल गर्ग ने जांच अधीनस्थ एडीएम सिटी एन लाल को सौंपी थी. इसी दौरान सैयद हैदर जामिन नामक व्यक्ति द्वारा महल की जर्जर हो रही दीवारों की मरम्मत कराने संबंधी एक अर्ज़ी दी गई, जो बोर्ड के सीईओ के पास नियमानुसार उचित कार्यवाही की संस्तुति करते हुए अग्रसारित कर दी गई. शिकायत के संबंध में दी गई जानकारी तथा जांच के परिणामस्वरूप शासन ने इस विक्री पट्टे को निरस्त करते हुए निर्माण की बाबत मुतवल्ली और नगर कोतवाल से जवाब तलब किया. मुतवल्ली को यूनिटी वेलफेयर सोसायटी के क़ब्ज़े को हटाने का आदेश भी जारी किया. जिस यूनिटी वेलफेयर सोसायटी के बैनर तले मोती महल परिसर में संस्था एवं स्कूल का बोर्ड लगा है. वह उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव शहाबुद्दीन मोहम्मद द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र संख्या 797/52-2-11 दिनांक 8 अगस्त, 2011 में जिलाधिकारी द्वारा संख्यक कल्याण एवं वक्फ़ अनुभाग-2 को भेजे गए पत्र संख्या 180/वक्फ़-मक़बरा/2011-12 दिनांक 8 जुलाई, 2011 के प्रत्युत्तर में निर्देशित किया गया है कि वक्फ़ अधिनियम 1995 की धारा-56 के प्रावधान के मुताबिक़, किसी अचल वक्फ़ संपत्ति को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे अथवा उप पट्टे पर दिया जाना शून्य एवं निष्प्रभावी होगा, भले ही वक्फ़ अभिलेख अथवा वक्फ़ दस्तावेज़ अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में कुछ भी अन्यथा अंतर्निहित हो. इस प्रकार शिया वक्फ़ बोर्ड द्वारा 30 वर्ष के लिए उक्त वक्फ़ का पट्टा यूनिटी वेलफेयर सोसायटी के पक्ष में किए जाने संबंधी पत्र संख्या- 45 (1) दिनांक 16/4/2003 को अवैध होने के कारण निरस्त कर दिया गया.

बताते चलें कि जिलाधिकारी/अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ़ द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित पूर्व में ही प्रेषित पत्र सं. 118/वक्फ़-मोतीमहल/2011-12 दिनांक 18 मई, 2011 में कहा गया है कि मक़बरा बहू बेगम साहिबा फ़ैज़ाबाद की संपत्ति मोतीमहल में स्थित मस्जिद दीवार आदि की मरम्मत/निर्माण संबंधी अनुमति के संबंध में वक्फ़ अधिनियम 1995 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शासन एवं वक्फ़ बोर्ड से समुचित मार्ग दर्शन मांगा गया था, जो अभी तक अप्राप्त है. इस तारतम्य में स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ यूपी शिया सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड लखनऊ, एसए रिज़वी के पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 2000 एवं प्रस्ताव दिनांक 26/12/01 पर स्कूल बिल्डिंग एवं मस्जिद निर्माण की अनुमति दी जाती है, जबकि स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि जब तक वक्फ़ की मंज़ूरी पट्टे के संबंध में नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का अभिलेख या पट्टा शून्य होगा. इस सबके बावजूद मोती महल परिसर में अवैध क़ब्ज़ेदारों द्वारा इसकी भूमि को हड़पने का खेल जारी रहा और काफ़ी जद्दोजहद के बाद हो रहे निर्माण कार्य को रोका गया है. मोती महल पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने के संबंध में प्रिंस एजाज़ बहादुर ने शिया सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड उत्तर प्रदेश को दिए गए शिकायती पत्र को संदर्भित करते हुए बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी सैयद गुलाम रिज़वी द्वारा जिलाधिकारी/अपर वक्फ़ आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा है कि यूनिटी वेलफेयर सोसायटी दिलकुशा मोती महल द्वारा मस्जिद एवं इमामबाड़े के नवनिर्माण हेतु अनुमति मांगी गई थी. इस पर बोर्ड ने 7/9/2011 को मस्जिद एवं इमामबाड़े के निर्माण की अनुमति प्रदान की थी. इस शर्त पर कि कोई व्यवसायिक निर्माण नहीं किया जाएगा.

प्रिंस एजाज़ बहादुर ने अपने को बहू बेगम का वसीका प्राप्त करने के आधार पर उत्तराधिकारी बताते हुए ज़िला दीवानी न्यायालय में एक मुक़दमा दायर करके यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्राप्त करने की बात कही है. प्रिंस एजाज़ ने बहू बेगम की समस्त संपत्ति को ट्रस्ट की संपत्ति बताया और इसे वक्फ़ की संपत्ति होने से मना करते हुए वक्फ़ बोर्ड को अपने अधिकारों के काग़ज़ी पुख्ता प्रमाण दिखाने की उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में चुनौती दी है. प्रिंस एजाज़ का कहना है कि मोती महल के अंदर कभी कोई मस्जिद नहीं थी, जो निर्माण हो रहा था वह सिर्फ़ साज़िश है. जो भी हो वर्तमान समय में मोती महल परिसर में निर्माण या मरम्मत का कार्य तो नहीं हो रहा है, फिर भी महल से सटे क़ब्ज़ेदारों द्वारा महल की पुरानी जर्जर दीवारों को तोड़कर क़ब्ज़े किए जा रहे हैं, जिस पर कार्यवाही होना आवश्यक है. यदि समय रहते पर्यटन और पुरातत्व विभाग द्वारा ध्यान न दिया गया तो अवशेष मोती महल का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

जयंत ने विधायिकी छोड़ी

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की चुनावी हलचल में स्वयं को यूपी की सत्ता या फिर मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल रखने के लिए सांसद से विधायक बने जयंत चौधरी ने राजनीति का रंग बदलते ही विधायक पद छोड़ दिया. अब वह सांसद रहते समाज सेवा करेंगे. विधायक चुने जाने के 15 दिनों के भीतर ही विधायिकी से त्यागपत्र दे दिया. राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) प्रमुख अजित सिंह के सांसद पुत्र और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मथुरा ज़िले की माट सीट से निर्वाचित हुए जयंत चौधरी ने बीते 20 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया.

रालोद के प्रवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि माट सीट से चुने गए जयंत ने विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में प्रमुख सचिव को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है. मथुरा सीट से सांसद जयंत के इस्तीफ़े की वजह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जनता चाहती है कि जयंत चौधरी लोकसभा में ही रहें और उसकी भावना का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया. जयंत के इस्तीफ़े से रिक्त हुई माट सीट से उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने की अटकलों के बारे पूछे जाने पर दुबे ने कहा कि इस बारे में कोई भी फ़ैसला रालोद प्रमुख अजित सिंह ही करेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

पुलिस कर्मियों की गृह जनपद के समीप तैनाती

सपा के सत्ता में आते ही चुनाव पूर्व पुलिस कर्मियों को किए गए वादे के मुताबिक़ उनकी लंबित मांगों को सरकार ने मान लिया है. अब उनकी तैनाती गृह जनपद के समीप ही होगी. पिछली सरकार द्वारा लगाई गई इस रोक को पुन: बहाल कर दिया गया है. प्रमुख सचिव गृह राधे मोहन श्रीवास्तव के अनुसार, शासन ने निर्णय लिया है कि पुलिस विभाग में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी का तबादला उनके गृह ज़िले के पड़ोसी ज़िलों में हो सकेगा. पुलिस कर्मियों की समस्या को देखते हुए तबादलों में लगी रोक को हटा लिया गया है. साथ ही पुलिस की जोन व्यवस्था को भी बहाल कर दिया गया है.

बसपा शासनकाल में लागू की गई इस व्यवस्था के अंतर्गत हज़ारों पुलिसकर्मियों का तबादला दूर दराज के जनपदों में कर दिया गया था, जिससे उन्हें अपने घर आने-जाने में काफ़ी परेशानी होती थी. उन्होंने शासन से गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. चुनाव पूर्व ही सपा ने पुलिसकर्मियों को ख़ुश करने का वादा किया था. बहरहाल, सपा सरकार ने इस व्यवस्था को पुन: बहाल कर दिया है.

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

मिनरल वाटर प्लांट में बोरवेल के ज़रिये भूजल का लगातार प्रयोग करने से बारहसिंघों का वास स्थल प्रभावित हो सकता है.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

सत्ता संघर्ष की पुनरावृत्ति

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद भी कांग्रेस में सत्ता संघर्ष जारी है. हरीश रावत जैसे नेता अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जिसके पीछे उनकी अपनी पद लोलुपता के साथ अपने परिवार को पदारूढ़ करना शामिल है. रावत राज्य में कांग्रेस के दिगगज नेताओं में गिने जाते हैं. राज्य में कांग्रेस का परचम लहराने में उनकी महती भूमिका रही है, जिसके बदले कांग्रेस ने भी उन्हें कुछ कम नहीं दिया है. वर्तमान में हरिद्वार से सांसद होने के साथ केंद्र सरकार में संसदीय मंत्री का दायित्व भी उनके पास है. साथ ही पार्टी ने उनके युवा पुत्र आनंद सिंह रावत को प्रदेश युवा कांग्रेस का दायित्व भी दे रखा है. सूबे की राजनीति में भी दो दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को उनके कहने पर ही चुनाव मैदान में उतारा गया. इस सबके बावजूद रावत जितना भाजपा के रमेश पोखरियाल निशंक जैसे दाग़ी नेताओं के सगे दिखे, उतने कांग्रेस के डोईवाला सीट के प्रत्याशी के नहीं. उन्हीं के कारण इस सीट से कांग्रेस के बाग़ी नेता ने कांग्रेस को क्षति पहुंचाई. इसी के चलते कांग्रेस की जीत हार में बदल गई. इसी तरह उनकी भूमिका हरिद्वार में उनके अपने संसदीय सीट के मामले में भी चिन्हित हुई है. महाकुंभ–2010 में दाग़ी दामन के लिए चर्चित मदन कौशिक की जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस ने निशंक सहित मदन भैया पर जो आरोप लगाए थे, वे सब झूठे थे.

कांग्रेस के दिग्गजों की कलह का असर प्रदेश से रिक्त हो रही राज्यसभा की एक अदद सीट के लिए होने वाली चुनाव प्रक्रिया पर भी दिखा. लाख टके का सवाल यह है कि दिग्गजों ने टिकट तो झपट लिए, लेकिन विधायक जिताकर नहीं ला सके. दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में इस समय कांग्रेस में गुटीय राजनीति अधिक हावी है. यही कारण है कि कांग्रेस सरकार में ग़ैर विधायक को नेतृत्व संभालना पड़ा. तीसरी विधानसभा के गठन के बाद छिड़े सत्ता संघर्ष की तस्वीर भी बदल गई. इस बार जंग सांसदों के ही बीच छिड़ी. सांसदों की जंग में मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार विधायक पीछे छूट गए और बाज़ी एक बार फिर सांसदों के हाथ लगी. वर्ष 2002 को बीते हुए बेशक एक दशक से अधिक हो गया, लेकिन कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर पुराने इतिहास को दोहरा रही है. तब राजनीति के चतुर खिलाड़ी एनडी तिवारी सत्ता के केंद्र में थे और आज विजय बहुगुणा. यह भी एक सच्चाई है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में दलितों के घर खाने, सोने का तो दिखावा करते रहे, लेकिन देवभूमि में कांग्रेस को पाचों संसदीय सीट जिताने वाले दलित नेता यशपाल आर्या को दर किनार कर दिया गया. कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपनी विवेक हीनता के चलते इस द्वंद्व को जन्म दिया है. सूबे में मुख्यमंत्री का चयन विधायक मंडल दल से किया गया होता तो दस जनपथ को इस तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती. सत्ता के लिए संघर्ष आज भी जारी है, बस किरदार बदल गए हैं. कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चयन की लंबी प्रक्रिया के बाद भी दुल्हन वही जो पिया मन भाये की परंपरा सदियों से चली आ रही है. दरअसल, प्रदेश की राजनीति में दख़ल रखने वाले दिग्गजों ने ख़ुद को मज़बूत बनाने के लिए विधानसभा टिकट झपट लिए, लेकिन संयुक्त रूप से भी सुविधाजनक बहुमत नहीं जुटा पाए. यही कारण है कि निकट भविष्य में बनने वाली कांग्रेस सरकार बैसाखी के भरोसे चलेगी. हालांकि हार के कारणों की समीक्षा पार्टी का नितांत निजी मामला है, किंतु सरकार चलाने के लिए जिन निर्दलीयों का सहारा लिया जा रहा है, वे सभी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता रहे हैं. इससे महसूस किया जा रहा है कि टिकट वितरण में दिग्गजों की ओर से हठधर्मिता दिखाई गई. यही कारण है कि टिकट वितरण के बाद असंतुष्टों को मनाने की कमज़ोर कोशिश हुई. राजनीति की समझ रखने वाले इसे एक–दूसरे को कमज़ोर करने की साज़िश भी मानते हैं. बहरहाल, कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने का इंतज़ाम तो कर लिया है, लेकिन अहम मुक़ाम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी एक नई जंग का सबब बन गई है. दिग्गजों ने जिस अधिकार के तौर पर टिकट मांगे, वैसी ही ज़िम्मेदारी विधायकों को जिताने में नहीं निभाई. टिकट वितरण पर सरसरी नज़र डालें तो प्रदेश में सबसे अधिक लगभग 30 टिकट हरीश रावत के कोटे में गए, जबकि विधायक जीतकर आए सिर्फ़ सोलह. मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कोटे में लगभग 12 टिकट आए, जबकि जीत हुई छह सीटों पर. इसी क्रम में पौड़ी के सांसद सतपाल महाराज के कोटे में 10 लोगों को टिकट दिए गए, जबकि जीतकर आए सात. 18 टिकटों का बंटवारा प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत एवं यूथ कांग्रेस के बीच हुआ था. दिग्गजों ने टिकट तो झपटे, विधायक जिताकर नहीं ला सके. सूबे में सदन से सड़क तक जो संघर्ष डॉ. हरक सिंह रावत और आर्या ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ किया, उसे नकारा नहीं जा सकता.

feedback@chauthiduniya.com

नियुक्तियों को लेकर सवाल उठे

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत उत्तराखंड के 81 नए उच्चीकृत विद्यालयों में कार्यालय सहायक एवं 1841 स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक की संविदा पर नियुक्तियों को लेकर भारी गोलमाल किए जाने की चर्चा है. ये सारी नियुक्तियां सूबे में ईमानदारी का डंका बजाने वाले जनरल खंडूरी के राज में मनमाने तौर पर की गई हैं. सभी नियुक्तियां उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से हो रही हैं. उपनल ने मात्र कुछ दिनों की अवधि में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के तहत नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर दी. इससे उपनल भी सवालों के घेरे में है. उपनल अब पूरे प्रकरण से अपना पल्ला झाड़ रहा है. उपनल के अनुसार, अब आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. शासन ने सरकारी आउटसोर्सिंग कंपनी उपनल को रमसा के तहत नियुक्तियों की ज़िम्मेदारी दी. उपनल के कार्मिकों की आउटसोर्सिंग की बानगी देखिए कि बीते पांच और 14 दिसंबर को रमसा के निदेशक ने उपनल से अपने स्कूलों के लिए 1841 एवं 81 अन्य पदों पर प्रयोगशाला सहायक तथा कार्यालय सहायकों की मांग की और बिना विज्ञप्ति जारी किए कुछ ही दिन में अधिकतर नियुक्तियां कर दी गईं. जब तक युवाओं को पता चलता तब तक आचार संहिता लग गई और पूरे दो माह बाद जब मार्च में युवा उपनल कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने आवेदन लेने से इनकार कर दिया और डाक से जो सैकड़ों आवेदन पहुंचे थे, उन्हें रद्दी में फेंक दिया. अब आलम यह है कि राज्य के सीमांत जनपदों से रमसा की संविदा की इस नौकरी के लिए बेरोज़गार युवा देहरादून और हल्द्वानी में डेरा डाले हुए हैं. लेकिन उपनल आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि अभी भर्तियां होनी बाक़ी हैं. उपनल ने नियुक्ति के सारे नियमों को ताक़ पर रख दिया. देहरादून में रक्षा मोर्चा के कार्यकर्ताओं एवं हल्द्वानी में मोहन पाठक कुछ दिन ज़रूर इसके विरोध में हल्द्वानी उपनल कार्यालय में धरने पर बैठे. उपनल को न तो नियुक्तियां कराने का कोई अनुभव है और न ही उसके पास इतना स्टाफ है कि वह राज्य के तमाम विभागों के लिए कार्मिकों को आउटसोर्स कराने का ज़िम्मा ले सके, लेकिन फिर भी उसे ज़िम्मा दिया गया है और इसका ख़ामियाज़ा राज्य के बेरोज़गारों को भुगतना पड़ रहा है. उपनल की दलील है कि उसके पास सैकड़ों आवेदन पहुंचे हैं, इसलिए वह नए आवेदन नहीं ले रहा है, लेकिन बिना विज्ञप्ति जारी किए मात्र कुछ ही दिनों में ये आवेदन उपनल के पास कहां से और कैसे पहुंचे, यह एक बड़ा सवाल है. रमसा ने भी इस बात का संज्ञान तब लिया, जब बेरोज़गार युवा आंदोलन पर उतर आए. रमसा के संयुक्त निदेशक महावीर सिंह बिष्ट एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उपनल के प्रबंधन निदेशक से मिले और मामले का संज्ञान लिया कि क्यों उपनल द्वारा विज्ञप्ति जारी नहीं की गई और नियुक्तियों के लिए कोई तिथि घोषित क्यों नहीं की जा रही है. बिष्ट का कहना है कि इस पूरी चयन प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं है. रमसा के लिए 1841 स्कूलों में प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए अभी सभी नियुक्ति यां नहीं हुई हैं. इसके बावजूद उपनल द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेर में अभी दर्जनों पद प्रयोगशाला सहायक के भरे जाने हैं. उपनल द्वारा नेट पर जारी सूची में अभी आधे ही पद भरे गए हैं. इसके बावजूद अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. कोई सही दिशा देने की बजाय हल्द्वानी उपनल वाले युवाओं को देहरादून जाने और वहां फार्म जमा करने की बात कह रहे हैं, तो देहरादून पहुंचने पर वह हल्द्वानी जाने को. आचार संहिता हटने के बाद से लगातार सैकड़ों युवा उपनल कार्यालय में पहुंच रहे हैं, लेकिन चयन तो दूर उनके आवेदन तक स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. रमसा में नियुक्ति के लिए कई मानक हैं, पहला पूर्व सैनिक हो, दूसरा पूर्व सैनिक आश्रित हो, तीसरा स्कूल के निकटतम स्थान का निवासी हो, चौथा महिला अभ्यर्थी हो, पांचवां विकलांग हो और छठा इंटरमीडिएट विज्ञान विषय में उत्तीर्ण हो. इसके पहले की गई नियुक्तियों में सभी ज़रूरी मानकों की भी अनदेखी की गई है.

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

भूजल दोहन पर सरकार सजग

उत्तराखंड में भूजल के मनमाना दोहन किए जाने से वन्य जीवों के समक्ष पीने के पानी का संकट खड़ा होने लगा है. धर्मनगरी हरिद्वार सहित कई स्थानों पर भूजल को अत्यधिक दोहन करके जल कारोबार करने वाली इकाइयों पर सरकार ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है. इससे यह स्पष्ट हो गया है कि उद्योग अब वन्य जीवों के हलक़ सूखने की वजह नहीं बनेंगे. औद्योगिक इकाइयों के लिए ऐसा कोई भी क़दम प्रतिबंधित होगा, जिससे क्षेत्र विशेष में जंगली जानवरों के लिए पानी का संकट खड़ा हो सकता है. हरिद्वार वन प्रभाग में झिलमिल झील के पास एक औद्योगिक इकाई के भूजल का प्रयोग करने से बारहसिंघों के एकमात्र वास स्थल के लिए उत्पन्न ख़तरों को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस दिशा में संजीदा हुआ है. बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार, उद्योगों की स्थापना की सहमति देने से पहले ऐसे बिंदुओं समेत पर्यावरणीय कारकों का अनिवार्य रूप से अध्ययन कराया जाएगा. सूबे में यूं तो वन सीमा के नज़दीक कई उद्योग पहले से ही स्थापित हैं, लेकिन गत वर्ष हरिद्वार प्रभाग में झिलमिल वेटलैंड की सीमा पर दुधला दयालवाला में स्थापित मिनरल वाटर प्लांट को लेकर आई शिकायत ने बोर्ड के कान खड़े कर दिए. राज्य में झिलमिल झील ही बारहसिंघों का एकमात्र वास स्थल है. आशंका है कि मिनरल वाटर प्लांट में बोरवेल के ज़रिये भूजल का लगातार प्रयोग करने से बारहसिंघों का वास स्थल प्रभावित हो सकता है. इस मसले का भले ही गहन अध्ययन कराने की बात बोर्ड कह रहा हो, लेकिन इसने इसे भविष्य के लिए सबक़ अवश्य दे दिया. यही वजह है कि बोर्ड ने अब उद्योग स्थापना की सहमति देने से पहले ऐसे विषयों का गहन अध्ययन कराना अनिवार्य किया है, ताकि वन्य जीवों के लिए पानी का संकट न हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके. राज्य में जल से जुड़े उद्योगों से घूस लेकर अनापत्ति पत्र जारी किए जाते रहे हैं. इस संबंध में बोर्ड के देहरादून, काशीपुर, रुड़की एवं हल्द्वानी स्थित क्षेत्रीय अधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com